खण्ड–504, अंक–3
गुरुवार, 01 चैत्र शक संवत् 1940
(22 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 504 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
सुल्तानपुर में हुई घटना को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम सुने जाने की मांग...	9
प्रश्नोत्तर	10-58
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	58-59
जनपद एटा के तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	60
लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में होम्योपैथी शिक्षा में फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुसराय मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद शामली के ब्लाक ऊन के पी0डब्ल्यू0डी0 के मुख्य मार्ग समीप स्थित नाली को रोकने के कारण ग्राम में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद चन्दौली के धानापुर विकास खण्ड गुरैनी पम्प कैनाल पर हो रहे गंगा कटान न रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद आगरा के सेवला सराय सरस्वती बिहार के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	62
जनपद आगरा के इन्द्रपुरी कालोनी के जर्जर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद गाजीपुर के जमनिया में मुंसिफ कोर्ट निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में शहीद स्मारक सेनापुर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटावा में जर्जर बिजली के तारों के स्थान पर केबिल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	63-64
जनपद अलीगढ़ के तहसील मुख्यालय गभना को खैर से जोड़े जाने वाले कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर स्थित राजकीय कैंसर संस्थान में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र के रायपुर में राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद सहारनपुर के गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक फोर लेन हाई-वे एवं अण्डर पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ के शिक्षकों का स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	65-66
जनपद सीतापुर में चयनित आई स्पर्श स्मार्ट योजना की शेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	66
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत इन्दिरा कालोनी व बसन्त विहार के तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव खुड्डा से श्मशान घाट जाने का रास्ता बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	66
जनपद महोबा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, चरखारी में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	67
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	68-113
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2740/29-6-2015-115 सा-14, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-178/29-6-2016-116 सा-14, दिनांक 20 जनवरी, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2945/29-6-2016-115 सा-2014, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-1253/29-6-2017-116 सा-2014, दिनांक 07 जुलाई, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	114
लोक आचुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2-2011 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र-2017 (दिनांक 14-12-2017 से दिनांक 22-12-2017 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1988 के नियम-301 के अधीन ग्राह्य सूचननाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	115
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 140वां (एक सौ चालीसवां) प्रतिवेदन (सदन के पठल पर रखा गया) ...	115
अ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) एवं 141वां (एक सौ इक्तालिसवां) प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	115
उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में खेल का मैदान विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मिश्र आदि निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	116
जनपद गाजीपुर के ग्राम महेगवा पलवहीपुर व मीरपुर की आ0न0एन0एच0-29 द्वारा अधिग्रहित पचासों प्रभावित किसानों की प्रतिकर धनराशि लगभग 22 करोड़ लाये दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कामेश्वर चौहान आदि निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	116
जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0क्षे0 जलालपुर के ब्लाक भिगांव के ग्राम पंचायत मथुरा रसूलपुर में रामजीत दलित के खेत के हसनपुर सम्पर्क मार्ग पर कौहाड़ी बाजार एक दूरी लगभग-2 कि0मी0 शून्य लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र निषाद आदि निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	116
जिला जौनपुर के ब्लाक-केराकत के अन्तर्गत नगर पंचायत केराकत में अग्निशमन केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशु जायसवाल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	116
जिला अम्बेडकरनगर के ब्लाक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मिर्जाबेग दुःखवर (मकदुमपुर बना) के दक्षिण से तुरकहिया तालाब से ग्राम सभा नैली (नयानगर) तक के नाला की सफाई जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राजभर आदि निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	116
ग्राम सभा हरीपुर, ब्लाक-चकिया, जनपद चन्दौली में पक्की सड़क बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	117

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हाथरस की तहसील साहाबाद के ग्राम पंचायत नसीरपुर (रसमई) के साहाबाद राजवाहे में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन सिंह आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	117
जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में सिथत धुरियापार सहकारी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राय आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	117
महामना राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती को गृह विज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं चित्रकला में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्विवेदी आदि निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	117
जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351 लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक लालगंज के जर्जर क्षतिग्रस्त सड़कों की निर्माण के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	117
जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्रीर नजीरूद्दीन आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	118
जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	118
जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा ग्वारी में राजकीय डिग्री कालेज/इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री बृजेश सिंह आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	118
जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र रेउसा को तहसील व पुलिस सर्किल ऑफिस बनाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र अवस्थी आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)...	118
जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा थानगांव में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री विकास शुक्ला आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	118
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकासखण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुलरिहा के मजरा संग्राम खेड़ा से जिन्दा खेड़ा गांव तक गड्ढायुक्त कच्चे मार्ग का जनहित में डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में डा0 सर्वेंद्र सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकासखण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछौरा में काशी प्रसाद खेड़ा गांव तक गड्ढायुक्त कच्चे मार्ग का जनहित में डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	118
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा नगर पंचायत मौरावां के अन्तर्गत कस्बे में दस वर्ष पूर्व स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरदीप त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)...	118
जिला उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकासखण्ड-हिलौली के अन्तर्गत ग्राम दुन्दपुर के पास मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल तिवारी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	119
जिला उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के कस्बा मौरावां के अन्तर्गत बसहा तिराहा के पास मौरावां-उन्नाव मुख्य मार्ग पर बनी संकरी पुलिया का चौड़ीकरण जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	119
जनपद लखनऊ में नीलमथा रोड स्थित गोकुल धाम कालोनी में सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रानू त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)...	119
भूसागर कानपुर देहात की विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सचान आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	119
सरवनखेड़ा कानपुर देहात में गत 50 वर्षों से पेयजल टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119
विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के शाहजहांपुर जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार कटियार आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119
जनपद-बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड कोतवाली के ग्राम चकनारंगी नगीना-अकबराबाद मार्ग पर 300 मी0 नाले के निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री इफतेखार हुसैन आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बिजनौर के वि0स0क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत अकबराबाद-किरतपुर मार्ग के ग्राम विरदोंनाली तक 2.00 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री अशफाक आदि निवासीगण की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	120
जनपद-बिजनौर वि0स0क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड किरतपुर के ग्राम पाडला से ग्राम मुबारकपुर खोसा (खुसियाकी) ईइगाह तक 1.5 कि0मी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	120
जनपद-बिजनौर के वि0स0क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड किरतपुर के ग्राम अकबराबाद-किरतपुर मार्ग पर शिव मन्दिर से ग्राम बेगमपुर रूपचन्द (सिसौना) तक लम्बाई 700 मी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	120
जनपद-बिजनौर के वि0स0क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड कोतवाली के नगीना-नहटौर मार्ग से सेदखेड़ी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम लालवाला (उग्रसैनपुर) में टूटी पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	120
जनपद-बिजनौर के वि0स0क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड किरतपुर के ग्राम शादीपुर-किरतपुर मार्ग से जीवनपुर तक लम्बाई 1.00 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	120
जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के फतेहगंज (प0) में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0 लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	121
जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज से हुरदुरी दिवाना होते हुए फतेहगंज (प0) को जोड़ने वाले पुराने रोड को शुरू कराए जाने व दिजोड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	121
जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही से मिर्जापुर चौराहा तक रोड का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गंगवार आदि निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में सिंधौली चौराहे से वाया हल्दीकला धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	121
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर में बैदौला से असुरैना तक जाने वाले मार्ग का मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर सिंह आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) ...	121
जनपद बस्ती के तहसील भानपुर में (पूर्व समाजवादी सरकार के द्वारा तहसील स्तर पर विद्युत उपगृह निर्माण की नीति के तहत) निर्मित विद्युत उपगृह को ऊर्जीकृत किए जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	122
जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के प्रमुख मार्ग महनुआ-बरहपुर का निर्माण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेश जायसवाल आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)... ...	122
जिला-शाहजहांपुर के वि0स0क्षे0-131 कटरा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग-24 पर स्थित कटरा रोडवेज बस अड्डा के नवीनीकरण व सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल कुमार आदि निवासीगण जनपद शाहजहंपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	122
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	122
प्राइवेट आई0टी0आई0 परीक्षण हेतु पंजीकरण छात्रों के फीस की प्रतिपूर्ति रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद-सुल्तानपुर के श्री दीनानाथ पुत्र श्री तुलसीराम पासी के अपने निजी खेत से मिट्टी खनन करने पर कोतवाल द्वारा घूस की मांग न पूरी होने पर उन्हें एवं उनके परिवार को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	125-130
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक चर्चा पर वित्त मंत्री का उत्तर भाषण ...	130-136
नियम-51 के अन्तर्गत सूचना	136-138
जनपद-फैजाबाद स्थित जिला चिकित्सालय में आवश्यक स्टाफ की तैनाती किये जाने एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	139
जनपद-आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बड़े पाइप डलवाने के सम्बन्ध में डा0 जी0एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	139-140

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर में नाले की सफाई कराये जाने से सम्बन्ध में श्री रामअचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	141
जनपद-लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद क्षेत्र के 20 ग्रामों को जोड़े जाने के उपरान्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	141-142
जनपद-वाराणसी के कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में श्री नील रतन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	142-144
भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश में समुचित तहर लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	144
जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर नेशनल वाई-वे से सेंट मोमिना स्कूल के पास लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	144-145
जनपद-श्रावस्ती में सीताद्वार में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	145-146
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	146
प्रदेश के सरकारी विभाग को कैन्टीन में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों एवं प्लेटों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	146-147
जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियान में विकासखण्ड के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	147-148
नत्थी	149-152

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदय-384

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
17. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
34. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
35. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
37. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
40. असलम अली, श्री — हापुड़
41. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
43. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़

45. आलमबदी, श्री आजमगढ़
46. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
48. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
49. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
50. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
51. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
52. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
53. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
54. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
57. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
62. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
63. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
64. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
65. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री देवरिया
69. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
70. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
72. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
73. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
74. केसर सिंह, श्री बरेली
75. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
76. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
77. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
78. गंगा, श्री कुशीनगर
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
81. गौरी शंकर, श्री जालौन
82. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
83. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
84. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
85. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
88. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
93. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
94. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
95. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जय मंगल, श्री महाराजगंज
98. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
99. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
100. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
101. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
102. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
103. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
104. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
107. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली

108. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
109. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
110. दल बहादुर, श्री रायबरेली
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
113. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
114. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
115. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
116. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
119. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
121. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
122. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
123. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
124. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
126. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
127. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
128. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
129. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
130. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
131. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
132. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
133. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
134. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
135. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
136. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
137. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
138. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
139. नाहिद हसन, श्री शामली
140. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
141. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
142. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
143. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
144. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
145. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
146. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
147. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
148. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
149. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
150. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
151. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
152. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
153. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
154. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
155. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
156. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
157. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
158. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
159. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
160. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
161. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
162. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
163. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
164. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
165. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
166. फागू चौहान, श्री मऊ

167. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
168. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
169. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
170. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
171. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
172. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
173. बावन सिंह, श्री गोण्डा
174. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
175. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
176. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
177. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
178. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
179. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
180. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
181. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
182. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
183. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
184. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
185. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
188. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
189. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
190. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
191. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
192. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
193. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
194. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
195. महबूब अली, श्री अमरोहा
196. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
197. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
198. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
199. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
201. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
202. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
203. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
204. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
205. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
206. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
207. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
208. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
209. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
210. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
211. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
212. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
213. यासर शाह, श्री बहराइच
214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
215. योगेश वर्मा, श्री खीरी
216. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
217. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
218. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
219. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
220. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
222. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
226. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी

229. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
231. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
232. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
233. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
234. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
235. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
236. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
237. राज करन कबीर, श्री बांदा
238. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
239. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
240. राजबाला, श्रीमती रामपुर
241. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
242. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
243. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
244. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
245. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
246. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
247. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
248. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
249. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
250. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
251. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
252. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
253. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
254. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
255. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
256. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
257. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
258. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
259. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
260. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
261. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
262. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
263. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
264. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
265. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
266. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
267. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
268. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
269. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
270. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
271. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
272. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
273. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
274. लाखन सिंह, श्री औरैया
275. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
276. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
277. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
278. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
279. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
280. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
281. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
282. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
283. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
284. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
285. विजय मिश्र, श्री भदोही
286. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
287. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
288. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर

289. विनय शाक्य, श्री औरैया
290. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
291. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
292. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
293. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
294. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
295. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
296. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
297. वीरेन्द्र, श्री एटा
298. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
299. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
300. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
301. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
302. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
303. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
304. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
305. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
306. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
307. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
308. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
309. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
310. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
311. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
312. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
313. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
314. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
315. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
316. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
317. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
318. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
319. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
320. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
321. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
322. संजय, श्री बुलन्दशहर
323. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
324. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
325. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
326. संजय यादव, श्री बलिया
327. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
328. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
329. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
330. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
331. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
332. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
333. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
334. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
335. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
336. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
337. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
338. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
339. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
340. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
341. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
342. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
343. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
344. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
345. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
346. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
347. सुचि, श्रीमती बिजनौर
348. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
349. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
350. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

351. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
352. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
353. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
354. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
355. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
356. सुरेश कुमार, श्री शामली
357. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
358. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
359. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
360. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
361. सुरेश राही, श्री सीतापुर
362. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
363. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
364. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
365. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
366. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
367. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
368. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
369. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
370. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
371. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
372. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
373. सौरभ सिंह, श्री खीरी
374. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
375. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
376. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
377. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
378. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
379. हरीराम, श्री सोनभद्र
380. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
381. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
382. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
383. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
384. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन, प्रोटोकाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] सुल्तानपुर में हुई घटना को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिये। आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सुल्तानपुर जिले का है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल नहीं करना है?

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है। लेकिन यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

मैं जो पूछ रहा हूँ इसका बतायें। अभी तो पूरे दिन भी सदन चलना है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नोत्तर जरूरी है लेकिन यह उससे भी ज्यादा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो दिन भर सदन चलाना है। बीच में किसी समय यह बात आ जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

एक वकील के साथ.....। इसको आप किसी समय ले लेंगें यही कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यही तो हम कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिये। बाद में किसी समय ले लेंगें।

श्री लाल जी वर्मा-

ठीक है मान्यवर।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, एक हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष-

आपसे भी तो बात हो गई है।

श्री संजय गर्ग-

ठीक है मान्यवर।

[11:01] प्रश्नोत्तर

नत्थी-क

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र संचालित एवं उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्य-योजना की मांग

***1-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं में ड्रग्स सेवन की बढ़ती आदत एवं ड्रग्स के आदी हो चुके लोगों को नशा सेवन से मुक्ति हेतु सरकार द्वारा नशामुक्ति केन्द्र संचालित हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

जी हां।

वर्ष 2016-17 में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के भारत सरकार से अनुदान हेतु उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है :--

1-भारतीय समाज सेवा संस्थान, बर्फ खाना मिश्री का बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा संचालित सिद्धार्थ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, 438/109, निकट मंजू टंडन नर्सिंग होम, ठाकुरगंज, लखनऊ।

2-प्रेरणा समिति, चिनहट, नियर गोयल शीतगृह, लखनऊ द्वारा संचालित प्रेरणा नशा मुक्ति केन्द्र, बी0बी0डी0 कालेज के सामने, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

3-अर्चना महिला कल्याण समिति, ग्राम-अबहीपुर, भानमऊ, बाराबंकी द्वारा संचालित आनन्द पथ नशा निवारण केन्द्र, बाल विहार कालोनी, लखपेड़ाबाग बाराबंकी।

4-शिफा केयर संस्थान, ग्राम वादेखेड़ा, पो0 भटगांव, लखनऊ द्वारा कृष्ण गंगा नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र 31 जनतानगर बर्रा-2, कानपुर नगर।

5-ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र, चकिया, अलखपुरी, इलाहाबाद।

6-परख थरबिलार, पीड़ी करछना, इलाहाबाद द्वारा संचालित केन्द्र गंगा जी रोड कर्वी, चित्रकूट।

7-खण्डवारी देवी शिक्षा प्रसार समिति, चहनियां, चन्दौली द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, चहनियां, चन्दौली।

8-परख थरबिलार, पीड़ी करछना, इलाहाबाद द्वारा संचालित केन्द्र ग्राम व पो0 सलखन, सोनभद्र।

9-वैष्णवी फाउन्डेशन, जमुआ पवारी बाया कोरावं, इलाहाबाद द्वारा संचालित केन्द्र ग्राम व पो0 बिहसड़ा, जिगना, मिर्जापुर।

10-रत्न ग्राम्य विकास समिति, शाहबाद, रामपुर द्वारा संचालित आर0आर0एस0 नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, शाहाबाद, रामपुर।

11-गंगासुख ग्रामोद्योग विकास संस्थान 484 चाहबाई बरेली।

12-एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इंडिया, 180 अग्रवाल काम्पलेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा संचालित जागृति नशामुक्ति केन्द्र, 180, अग्रवाल काम्पलेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ।

13-भागीरथी सेवा संस्थान, आर-10/144, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित केमकुश नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, सुर्तीराम भीमसेन अस्पताल, असालत नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद।

14-सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन, लल्लाबाबू चौराहा, टीचर्स कालोनी, बुलन्दशहर द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र, लल्ला बाबू चौराहा, टीचर्स कालोनी रोड, बुलन्दशहर।

15-कौशिल्या देवी पूर्व मा0 विद्यायल समिति, शिवपुरी, टिमरूआ, पोस्ट-हरदोई, इटावा द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन एवं पुनर्वास केन्द्र, पुरविया टोला, इटावा।

16-वासुदेव तिवारी सेवा संस्थान ग्राम महाइचपुर, पो0 भेड़ापाकड़ देवरिया द्वारा संचालित पुनर्जन्म नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, सोनबरसा बाजार, गोरखपुर।

वर्ष 2017-18 में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के भारत सरकार से अनुदान हेतु उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है :--

1-ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र, चकिया, अलखपुरी, इलाहाबाद।

2-रत्न ग्राम्य विकास समिति, शाहबाद, रामपुर द्वारा संचालित आर0आर0एस0 नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, शाहबाद, रामपुर।

3-परख थरबिलार पीड़ी करछना, इलाहाबाद द्वारा संचालित केन्द्र ग्राम व पो0 सलखन, सोनभद्र।

4-वैष्णवी फाउनेशन जमुआ पवारी बाया कोरावं, इलाहाबाद द्वारा संचालित केन्द्र ग्रा0 व पो0 बिहसडा, जिगना, मिर्जापुर।

5-खण्डवारी देवी शिक्षा प्रसार समिति, चहनियां, चन्दौली द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, चहनियां, चन्दौली।

6-शिफा केयर संस्थान ग्राम वादेखेडा, पो0 भटगांव, लखनऊ द्वारा संचालित कृष्ण गंगा, नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, 31 जनतानगर बर्रा-2, कानपुर नगर।

प्रदेश में मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व से ही नशा एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों यथाः--शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्द्धक व खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, प्रभातफेरी/रैलियों, वालपेन्टिंग्स, होडिंग्स, ट्री गार्ड्स व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रचार सहित्य वितरण कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, में नशे से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराने के लिये भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है। प्रदेश की मलिन बस्तियों में भी विभाग द्वारा नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करने हेतु शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रचार का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुल दो सवाल पूछना चाहुँगी। उससे पहले मैं आपको एक आँकड़ा सुनाना चाहुँगी कि भारत में प्रतिवर्ष 101 अरब रुपये की ड्रग ट्रेप होती है मेरे कुल दो प्रश्न हैं एक तो जो माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत सारे एन0जी0ओज गिनाए हैं उनमें से छः ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार से फंड मिलने की स्वीकृति हो गई है तो क्या सरकार के मद्यनिषेध विभाग द्वारा प्रदेश में सभी जनपदों में विभाग के माध्यम से सीधे नशा मुक्ति केन्द्र खोलकर उसके माध्यम से नशे के आदी लोगों का इलाज किए जाने और प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जाने की योजना है क्योंकि सबको पता है कि एन0जी0ओज की और जो सरकारी केन्द्र हैं उनकी मॉनीटरिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है अभी तक जो माननीय मंत्री जी ने गिनाए हैं वह सारे एन0जी0ओज हैं इसमें सरकारी संस्था एक भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा कोई 'कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ ड्रग्स यूजेज इन उत्तर प्रदेश' की तैयारी की गयी है, क्योंकि अभी तक यदि मान लीजिए कि किसी की ड्रग्स यूजेज से मौत होती है, चाहे वह एच0आई0वी0 की हो, चाहे हेपेटाइटिस की हो, चाहे वह ओवर यूजेज से हो, हमें यही नहीं पता चलता है कि वह ड्रग्स यूज से हुई है या किसी और कारण से मौत हुई है। अभी तक कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनायी ही नहीं गयी है, जिससे हम लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है कि प्रदेश में कितना ड्रग्स यूज किया जा रहा है। खास तौर से आप देख रहे हैं कि जो पंजाब का हाल हुआ है, हरियाणा का हाल हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अलीगढ़ में, अतरौली में यहां बहुत तेजी से ड्रग्स यूजेज बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि मेरे रायबरेली जिले में भी पिछले काफी सालों से मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा तेजी से युवा ड्रग्स के प्रति झुकते जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसे इफ इन बड नहीं करेंगे, अगर शुरू में ही इसको बन्द नहीं करेंगे तो यह बहुत तेजी से फैलता है। मैं एक युवा विधायक होने के नाते यह जानना चाहती हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी क्यों नहीं तय की गयी है? क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है, उनको इस समाज की बहुत चिन्ता है, हम सबको भी है। अभी तक जिन एन0जी0ओज0 को केन्द्र सरकार द्वारा फन्डिंग मिलता है, उन्हीं के द्वारा हमारे यहां जो भी है मद्य निषेध विभाग में संचालित है। उनके द्वारा जो फीडबैक हमको मिलता है, उनके द्वारा जितने लोग उनके अस्पतालों में भर्ती होते हैं, वह हमको एक आंकड़ा मिलता है कि कितने प्रतिशत लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। यह सही बात है कि अभी इस विभाग में बजट बहुत कम है। मेरे विचार से जो हमने पूरे एक साल इस विषय पर स्टडी किया है, हम चाहते हैं कि इस विभाग को और...

श्री अध्यक्ष-

आपका विचार जो आपने सोचा वह बहुत महत्व का नहीं है, सरकार की नीति और लक्ष्य क्या है, यह बतायें ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की मद्य निषेध विभाग के प्रति जो नीति है, मात्र उसमें प्रचार-प्रसार के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में या खेल-कूद के कार्यक्रम में, मेले में या ट्री गार्डर होर्डिंग के

द्वारा इस तरह से प्रचार-प्रसार करना, जिसमें युवा लोग उस तरफ न जाए, इस बीमारी से इस चिंताजनक विषय से दूर रहें।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने नशे से ग्रसित लोग हैं, इसमें कितनी महिलायें हैं और कितने पुरूष हैं और उसके साथ-साथ पूरे विभाग का जो बजट है, उसमें कितना धन इसको रोकने के लिए आवंटित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि बजट कम है।

श्री मोहम्मद असलम राइनी 'एडवोकेट'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। आपका आदेश हो तो एक सवाल पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आप खड़े ही हो गये हैं, तो पूछ लीजिए।

श्री मोहम्मद असलम राइनी 'एडवोकेट'-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो स्कूल या कालेज या डिग्री कालेज के आस-पास छोटी-छोटी गुमटियां, जो पान-मसाले के नाम पर या सिगरेट के नाम पर खड़ी रहती हैं, वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल सिगरेट और बीड़ी के माध्यम से बच्चों को सप्लाई किया जाता है। माननीय मंत्री जी ऐसे कालेजेज, यूनिवर्सिटीज या ऐसे स्कूलों के सामने जो गुमटियां लगाकर बच्चों को खराब करने की उत्तर प्रदेश में प्रथा चली आ रही है, क्या सरकार उस पर कोई अंकुश लगाने का काम करेगी ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न तो माननीय सदस्य श्री रितेश पाण्डेय जी ने भी पूछा था, इसमें आज के समय में हमारे पास पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार के लिए 31 लाख 50 हजार का बजट है। लगभग दो करोड़ 92 लाख 65 हजार का इस्टेब्लिसमेंट का कास्ट है जिसमें सैलरी वगैरह आती हैं यह इतना ही है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने पूछा था कि जो शिक्षण संस्थाओं के अगल बगल पान की गुमटियाँ या अन्य छोटी छोटी गुमटियाँ लगती हैं अधिकांश जगहों पर स्कूल के प्रबन्धक या प्रबन्ध समिति जो होती हैं अगर वह थोड़ी इसमें सक्रियता बरतें तो उनके पास जितनी भी जमीन है उस पर वह उनको मना भी कर सकते हैं हटा सकते हैं बाकी जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है हम लोग प्रयास करेंगे कही अगर ऐसा है तो हम उसके लिए निर्देश देंगे अपने विभाग से कि इसको चिन्हित करके जिला प्रशासन से यह कह दिया जाएगा कि वहाँ किसी स्कूल के अगल बगल छोटी -छोटी गुमटियों में अगर कहीं पान या ड्रग बेचे जाते हैं उनको हटाया जाए इसके लिए प्रयास करेंगे।

श्री मोहम्मद असलम राइनी (एडवोकेट)-

आप सरप्राइज चेकिंग करा लें। सरप्राइज चेकिंग से यह होगा कि एक अंकुश लगेगा और हमारे जो छोटे बच्चे आज खराब हो रहे हैं वह खराब नहीं होंगे।

सुश्री अदिति सिंह-

मेरा माननीय मंत्री जी से बस एक ही सवाल है कि क्या कोई कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी आफ ड्रग यूजेज के लिए तैयार की जाएगी और उसमें क्या एम्स और जान हाकिन्स जैसे इन्स्टीट्यूट जो कई अन्य शहरों में ऐसे कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं क्या उनकी मदद ली जाएगी इस कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि फण्ड की कमी की वजह से बहुत सारे केन्द्र नहीं खुल सकते हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा और फण्ड आवंटन करने के लिए ताकि यहाँ और सरकारी केन्द्र खुल सकें।

श्री जय प्रताप सिंह-

इस पर विचार कर लेंगे। बजट की व्यवस्था करने के बाद कुछ और कार्यक्रम हम लोग सम्मिलित करना चाहते हैं इस विभाग में उसको करने के बाद इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी अपने विभाग के प्रति काफी गम्भीर भी हैं और उन्होंने अपने प्रश्न के अन्तिम पैरा में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेश में मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व से ही नशा एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। तो माननीय मंत्री जी यह बताएं कि यह कार्यक्रम कब से संचालित हैं किस शासनादेश के तहत संचालित हैं। दूसरा अगर माननीय मंत्री जी खुद संतुष्ट नहीं है इस संचालित व्यवस्था से कि हम अंकुश लगा पा रहे हैं तो इधर एक साल में जब से माननीय मंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण किया है तो क्या इसको कोई और प्रभावी कार्यवाही करने के लिए माननीय मंत्री जी कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं और ला रहे हैं तो कब तक ला रहे हैं।

श्री जय प्रताप सिंह-

मुख्यालय स्तर पर और मण्डलीय कार्यालयों पर इस तरह के कार्यक्रम संचालित भी हैं और बजट की व्यवस्था को देखते हुए छोटे-छोटे कार्यक्रम हर स्तर पर हैं। सात मण्डल कार्यालय हमारे हैं सातों मण्डल कार्यालयों में अलग अलग शिक्षा संस्थाओं और अलग-अलग खेल कूद प्रतियोगिताओं में इनको शामिल किया गया है परन्तु जैसा कि आपने कहा अध्यक्ष जी मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ और इसकी व्यवस्था करने पर मैं लगा भी हूँ प्रयास करूँगा कि जल्दी इसमें व्यवस्था करके इस नशामुक्ति को और प्रभावी ढंग से उसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी यह एक ऐसा सवाल है जो सम्पूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा है खासतौर से नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है। जो सवाल की मंशा थी हमारी नई विधायिका जी ने उठाया था उस सम्बंध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ तीन बातें आदमी को जरूर प्रभावित करती हैं एक माँ बाप के जीन्स दूसरा गृह नक्षत्र और तीसरा माहौल पहली दो चीजों को हम बदल नहीं सकते अगर हम बदल सकते हैं तो माहौल बदल सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे समाज को खासतौर से नौजवान पीढ़ी को जरूर इस बात के लिए सोचना भी चाहिए और उसके लिए और अधिक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता भी है हमारी यह कोशिश होगी जैसी जिज्ञासा भी प्रकट की गई चाहे पाण्डे जी ने किया हो चाहे राइनी जी ने किया हो चाहे उमाशंकर जी ने अभी तक जो व्यवस्था है इसको रोकने की मद्यनिषेध की वह पर्याप्त नहीं है हम इस बात को स्वीकार करते हैं और

यह हमारी कोशिश होगी कि इसको और अधिक प्रभावी तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं उनको और भी अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और इस संबंध में चाहे सरप्राईज चेकिंग के माध्यम से हो चाहे सर्वे के माध्यम से हो, एक स्टडी कराकर एक सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूँ और इस सामाजिक बुराई को दूर करने में हम सबका सहयोग चाहते हैं और हमारी सरकार की यह कोशिश होगी कि हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें।

अध्यक्ष-

सदस्य श्री नितिन अग्रवाल जी उपस्थित है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में उद्योग स्थापित करने एवं उद्यमियों द्वारा पूंजी निवेश की जानकारी

***2-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने उद्योग लगाने के लिए कितने एम0ओ0यू0 साइन कराते हुये कितने उद्योग स्थापित कराये तथा कितने उद्यमियों में पूंजी निवेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना) (अनुपस्थित)-

प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु दिनांक 21-22 फरवरी, 2018 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 में लगभग रु0 4.28 लाख करोड़ पूंजी निवेश हेतु 1045 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं। उद्योगों की स्थापना उद्यमियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से एन0ओ0सी0/अनुमति प्राप्त कर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ख)

प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना की जानकारी

***1-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला तथा प्रतीक भूषण सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों का कृषि उपज का उचित दर दिलाकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां।

प्रदेश के किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :--

(क) प्रदेश की मण्डियों का सुदृढ़ीकरण जिसमें मुख्य रूप से उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु 100 मण्डियों को ई-नाम (इलैट्रानिक-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) से जोड़ दिया गया है। ई-नाम के माध्यम से बेहतर मूल्य किसानों को प्राप्त होता है। ई-नाम के द्वारा किसान की उपज के

लॉट बनाये जाते हैं जिसका ऑन-लाइन ऑक्सन कराकर भुगतान किसानों के खातों में किया जाता है। इससे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है।

(ख) मोबाइल ऐप का आरम्भ मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 24 जनवरी, 2018 को किया गया है जिसके अन्तर्गत किसान किसी भी जिन्स का किसी भी मण्डी का बाजार भाव एवं आवक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।

भारत सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है एवं प्रदेश सरकार द्वारा यथा आवश्यकता घोषित मूल्यों पर क्रय करने की व्यवस्था की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के किसानों के उन्नयन एवं उनके सतत विकास हेतु कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के कार्यो को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से ''कृषक समृद्धि आयोग'' का गठन किया गया है जिसके द्वारा कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी करने हेतु समय-समय पर सुझाव दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-01, मा0 सहेन्द्र सिंह रमाला जी का प्रश्न है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-02 रह गया है।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मेरा एक छोटा-सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

यह मा0 सहेन्द्र सिंह रमाला जी का प्रश्न है, वह उपस्थित नहीं हैं। मा0 प्रतीक भूषण सिंह जी।

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री को इसमें मेरा एक सुझाव था जो मैं सबके सामने रखना चाहता था। मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस का जो सिस्टम है वह डिमाण्ड पर आता है। इसमें मेरा सुझाव है कि इसको अब क्वालिटी पर ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि प्राईवेट सेक्टर ऑर्गेनिक के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर उसको उचित दामों में बेच रहा है। उन्होंने तो उसको सर्च कर लिया कि यह बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारी सरकार के पास भी इनकम का यह एक बहुत अच्छा मौका है। आजादी के बाद हरित क्रान्ति के नाम से मिनिमम सपोर्ट की एक अच्छी शुरूआत हुई थी। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वह हैवी व्हीट कटोरा माना जाता है, किन्तु वहाँ पर आज इतनी बुरी स्थिति हो गयी है कि हमारी सरकार को वहाँ पर 01 लाख 36 हजार किसानों का कर्जा माफ करना पड़ा है यानी कि आबादी के हिसाब से प्रत्येक 07 में से 01 परिवार को कर्जा माफी की मदद लेनी पड़ी है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि हम क्वालिटी की तरफ बढ़ें और ग्रेडिंग के सिस्टम को लागू करें कि जिसने अच्छी पैदावार की तो उसको अच्छा मूल्य मिले। अभी हम लोग केवल डिमाण्ड की तरफ ध्यान देते हैं तो जहाँ पर डिमाण्ड है वहाँ पर काम अच्छा जाता है तो मेरा यह सुझाव है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें कि जैसी क्वालिटी हो वैसा पेमेन्ट हो। किसी ने बहुत मेहनत की तो उसे और अच्छा मूल्य मिलना चाहिये। किसी ने ऑर्गेनिक तरीके से किया तो उसे बहुत

ही बेहतरीन मूल्य मिलना चाहिये। एम0एच0पी0 के चक्कर में किसानों की रूचि घटती जा रही है। इस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। हम लोग क्वालिटी के ऊपर कब ध्यान देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपने बताई तो बहुत सी चीजे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है ?

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

मान्यवर, इसमें मेरा यही प्रश्न है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर कब ध्यान देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सुझाव दिया है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि एक नया मण्डी संशोधन बिल आज आपके सामने आ रहा है और हाउस में उस पर विचार किया जाना है। उस बिल में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि मण्डी समितियों के भीतर जहॉ हमनें ई-मैप से जोड़ा है वहॉ पर एक लैब स्थापित की गयी है जहॉ पर उसकी ग्रेडिंग होगी और ग्रेडिंग के हिसाब से उसको पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा जिससे कोई भी किसान किसी भी मण्डी के भीतर बैठकर के दूसरी मण्डी से व्यापार कर सकता है और अपनी नीलामी की बोली लगा सकता है। प्रदेश में जब से मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी है तब से किसानों की समस्या के समाधान के लिए सदैव अनवरत प्रयास कर रही है, सावधान है, सतर्क है और इसलिए जब कभी भी आप लोगों ने चर्चाओं के भीतर जो बेहतर सुझाव दिए हैं हम उन पर विचार करते हुए उनको आगे क्रियान्वित कर रहें हैं। (**सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपाई गयीं**)।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, पहला सवाल मेरा यह है कि प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए अभी जो खाद की बिक्री में पी0ओ0एस0 मशीन लगायी गयी है इसमे हमेशा यह शिकायत आ रही है कि सर्वर डाउन है जिससे खाद खरीदने में किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है तो फिर सरकार का सपना कैसे पूरा होगा कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं? दूसरा सवाल मा0 मंत्री जी से यह है कि बाराबंकी में पूर्ववर्ती सरकार के समय से बन रही सब्जी मण्डी के लिए 11 करोड़ 33 लाख 75 हजार रूपया गया था जिसमे पिछले 6 महीने से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, पूर्णतः बन्द हो चुका है। क्या उक्त मण्डी में रूके हुए काम को आगे बढ़ाकर चालू करने में सरकार सहयोग करेगी और करेगी तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष-

बाराबंकी वाला प्रश्न इसमें नहीं जुड़ा है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि मण्डियां हम बना रहे हैं इसलिए मैंने यह सवाल किया।

श्री अध्यक्ष-

बाराबंकी का किस्सा उनके पास होगा नहीं।

श्री सोबरन सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से हमारा एक अनुरोध है और प्रश्न भी है। सन् 1979 में धान का समर्थन मूल्य 102 रूपये प्रति क्विंटल था। उस समय किसान के साथ काम करने वाला खेतिहर मजदूर 5 रूपये पाता था। एक क्विंटल धान में बीस सहयोगी उसे मिलते थे।

आज धान का समर्थन मूल्य 1500 रूपये है और खेतिहर मजदूर को ढाई सौ रूपये मिलते हैं तो आज 6 मजदूर उसे एक क्विंटल धान के समर्थन मूल्य में मिल रहे हैं। मजदूरी का दाम बढ़ा, डीजल का पैसा बढ़ा, बच्चे की पढ़ाई बढ़ी और बुर्जुग के इलाज की कीमत बढ़ी, इतना बड़ा अन्तर जो आया है क्या इन विसंगतियों को मा0 मंत्री जी दूर करने की कृपा करेंगे? और यदि करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जो मा0 सदस्य ने धान की कीमतों के बारे में चर्चा की है, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के पहले धान के तीन-चार वर्षों में जो रेट रहे हैं पहले मैं आपके सामने उसका उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि 1979 के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं वह आंकड़ा उनके पास है, लेकिन वह आकड़ा मेरे पास है वह जब से मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है में उन आंकड़ों का उल्लेख मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। सन् 2013-14 में किसान को 1310/- रूपये मिलते थे, 2014-15 में 1360/- रूपये मिले, 2015-16 में 1410/- रूपये मिले और हमारी सरकार बनने के बाद 1550/- रूपये पर हम लोगों ने धान की भरपायी की है (**सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपाई गयीं**) तो आप यह देख सकते हैं। श्रीमन् इसलिए बता रहा हूँ कि मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद 100 रूपये क्विंटल से ज्यादा हमने खरीददारी के लिए दाम बढ़ाये और साथ ही साथ हमने धान की रिकॉर्ड खरीददारी की है। मान्यवर, 43 लाख मैट्रिक टन खरीददारी की है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि धान की खरीददारी जो हमने की है उस खरीददारी का पाई-पाई का मूल्य हमने भुगतान कर दिया है और एक रूपया भी हमारे किसान का, धान की खरीददारी का बकाया नहीं है (**सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपाई गयीं**) यह योगी आदित्यनाथ जी की पहली पारदर्शी सरकार है जिस सरकार ने धान के क्रय के लिए 6663 करोड़ रूपये यानी किसानो का शतप्रतिशत भुगतान हम लोगों ने किसानों के खाते में कर दिया है। किसान का एक रूपया भी अवशेष नहीं है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने अभी कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने ''कृषि उन्नत मेला'' जो दिल्ली में पिछले सप्ताह लगा था और इसमें लाखों किसानों का सम्मेलन हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कहा कि हम लागत की डेढ़ गुना कीमत अगली फसलों की देने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने पूछा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि फसल व मानव श्रम, पशु श्रम, मशीन श्रम, बीज, सिंचाई, उवर्रक, औषधि का मूल्य, बीमा का प्रीमियम, भूमि का किराया, फसली ऋण पर ब्याज को सम्मिलित करते हुए जो लागत आयेगी उसमें दस प्रतिशत प्रबन्धकीय व्यय को जोड़कर पचास प्रतिशत लाभांश को जोड़ते हुए अगले फसल सत्र से किसानों को लाभ दिया जायेगा। यह आप नहीं कर पाये, यह हम लोगो ने किया है। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको पूरा करने के लिए हमने कदम भी बढ़ा दिये हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार कितनी जागरूक है कि जब अधिकृत रूप से समाचार नहीं आये थे तभी 16 जनवरी, 2018 को यहां पर हमने बैठक की थी। यह मूल्य परामर्शदात्री परिषद् की बैठक मेरी ही अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। अगले साल की खरीद के लिए जो हमने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसके रेट मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ । इस साल जो हमने धान के रेट

1550 और 1590 दिये हैं उसको अगले साल के लिए हमने 2494 प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रस्तावित किया है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर न देकर सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। हमें प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग प्रश्न पूछने के बाद उत्तर सुनने की क्षमता रखे तो बेहतर रहेगा। यह पूछ रहे हैं कि मानव श्रम बढ़ गया, लागत मूल्य बढ़ गई, खाद की कीमते बढ़ गई इसलिये आप बताईये कि कितना मूल्य दोगे। मैं जब मूल्य देने की बात बता रहा हूँ तो इनको पसीने छूट रहे हैं। आप अपने आपको किसानों का हितैषी कहते हैं, प्रदेश में दो करोड़ तैंतीस लाख किसान रहते हैं और एक परिवार के भीतर यदि पांच सदस्य मान लें तो लगभग बारह करोड़ लोगो की भावनाओं से संबंधित यह प्रश्न है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा लेकिन जब मैं जब उत्तर दे रहा हूँ तो कम से कम आप उसको सुनने की हिम्मत तो रखिये। आप तो अपने आपको किसानों का हितैषी कहलाते हैं लेकिन जो आप नहीं कर पाये वह हम एक साल के भीतर कर रहे हैं और आपको पसीना छूट रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने दस फसलों के लिए केन्द्र सरकार को सुझाव भेजे हैं वह आपके माध्यम से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ । मुझे लगता है कि यदि आप इस बात को जान जायेंगे तो आपको भी प्रसन्नता होगी। धान के सामान्य रेट को 2495 रूपये क्विंटल के हिसाब से, ग्रेड-ए को 2795 के हिसाब से, बासमती को 3970 रूपये के हिसाब से, ज्वार को 2445 रूपये क्विंटल के हिसाब से, बाजरा को 2240 रूपये क्विंटल के हिसाब से, मक्का को 2195 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, उड़द को 6180 रूपये क्विंटल के हिसाब से, मूंग को 6180 रूपये क्विंटल के हिसाब से, अरहर को 5833 रूपये क्विंटल के हिसाब से, मूंगफली को 5355 के हिसाब से, सोयाबीन को 4200 रूपये क्विंटल के हिसाब से, तिल को 6625 रूपये क्विंटल के हिसाब से। मान्यवर, जो आपने कहा कि कैसे 2022 तक आमदनी बढ़ायेंगे तो हमने जो निर्णय किये हैं, इन्हीं निर्णयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी हम दूना करेंगे।

[श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री सोवरन सिंह यादव, श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री रितेश पाण्डेय द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है, कृपया आप लोग बैठिये। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ ।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमसे पूछा था कि आप किसानों की स्थिति को कैसे सुधारेंगे, कठिनाईयों से उन्हें कैसे निजात दिलायेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने किसी प्रकार की ठोस योजना नहीं बताई और इधर-उधर की बातें करके अपना उत्तर पूरा कर दिया। आज किसानों को खाद और बीज समय से नहीं मिल रहा है, बिजली उन्हें नहीं मिल रही है। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है और किसान दुर्दशाग्रस्त है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हें परेशानी इस बात के लिए है कि जो पहले जो यह कालाबाजारी करते थे, जो गोरखधन्धा यह करते थे, जो यह करवाते थे, किसानों के ऊपर जो लाठियां चलवाते थे, खाद की ब्लैक करवाते थे, वह नहीं हो पा रहा है।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर विरोध करने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

समाजवादी पार्टी के जमाने यूरिया के लिए लम्बी लाइन लगती थी, चार-चार दिन, पांच-पांच दिन लोग लाइन में खड़े रहते थे फिर भी उन्हें नहीं मिलती थी बल्कि लाठियां मिलती थी। हमारी सरकार जब से आई है हमने कहीं पर भी उर्वरक की कमी नहीं होने दी है। जब से योगी आदित्य नाथ जी की सरकार आई है कहीं पर भी उर्वरक के लिए किसानों को डन्डे नहीं खाने पड़े। मा0 अध्यक्ष जी, जो मिलावटी खाद होती थी, जो धांधली होती थी। केन्द्र सरकार ने यह तय किया कि कृषि स्नातक को ही खाद और बीज के लाइसेंस दिये जायेंगे। जो आपकी सबकी मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के नाम पर आने वाली यूरिया, नेपाल जाती थी, बंगाल जाती थी। जो औद्योगिक इकाईयों के द्वारा यूरिया में मिलावट करके और उसकी मात्रा को बढ़ाकर के बड़े पैमाने पर सब्सिडी किसानों के नाम पर लूटी जाती थी। मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक तो यूरिया को नीम कोटेट किया। जिससे 10 परसेंट यूरिया की बर्बादी रूक गई।

(सत्तापक्ष द्वारा मेंजों की थपथपाहट)।

10 परसेंट खेतों की लागत और यूरिया का उपभोग घटा। इस प्रकार से 20 परसेंट यूरिया की बचत हुई है। और पी0ओ0एस0 के माध्यम से जो किसान खाद लेगा और जब किसान जाकर पी0एस0ओ0 पर अपना अगुंठा लगायेगा उतनी ही सब्सीडी मिला कर जा पायेगी जिससे अनुदान पर होने वाली लूट बचेगी। आज प्रदेश में लगभग अधिकांश हमारे लाइसेंसीं के पास पी0एस0ओ0 मशीन हो गई है। हम नेटवर्क को ठीक कर रहे हैं। अभी तत्काल में किसी भी फर्टीलाइजर की जरूरत नहीं है। गर्मी के तापमान में फर्टीलाइजर नहीं पड़ता। यह आपको जानकारी भी है। हमने 31 जनवरी तक सभी जगहों पर पी0एस0ओ0 मशीन लगा दी है और पी0एस0ओ0 के माध्यम से जितना खाद्य विभाग उतना ही ऑन-रिकार्ड होता चला जायेगा और उतना ही औद्योगिक इकाईयों को सब्सिडी जा पायेगी। किसान के नाम पर जो मील मालिक और कारखाने वाले लूटते थे। उससे आज हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को निजात दिला दी है।

(सत्तापक्ष द्वारा मेंजों की थपथपाहट)।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, विद्वान मंत्री जी ने बहुत लम्बा उत्तर दिया और बहुत मेज भी थपथपाई। इन्होंने कहा कि जब हम लोग सरकार में थे तो काला-बाजारी में ही खाद बेचते थे। इस देश और प्रदेश का हर आदमी जानता है कि काला बाजारियों से आपकी सांठ-गांठ है। यह पूरा देश जानता है कि [x x x] इस देश की बैंकों से भारी रुपया लूट करके विदेश भाग गये। यह देश जानता है कि आप

नोट :--[x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुशार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोग पूंजीपतियों के एजेंट हैं। हम लोग किसानों के प्रतिनिधि हैं। मान्यवर, यह एक भी उत्तर नहीं दे पाये।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह आपत्तिजनक था, मा0 नेता विरोधी दल। प्रधानमंत्री का नाम लेना जोकि इससे कोई संबंध नहीं था और उनको सीधे आरोपित करना। इसका कोई औचित्य नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी बात का जवाब तो दे दें। एक मिनट पूरी बात तो आ जाये। उसको डायलूट क्यों कर रहे हो। अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति दी है। मा0 अध्यक्ष जी, गांव की एक मिसाल है कि-

'कहां नांद है, कहां मुंह मार रहे हैं।' (सदन में हंसी)

मा0 अध्यक्ष जी, विषय कृषि का चल रहा है। मा0 सोबरन सिंह यादव जी ने एक सवाल किया था कि 79 में धान का मूल्य क्या था और लेबर का रेट क्या था। उसका मा0 मंत्री जी ने आपकी सरकार का उद्धरण देते हुए जवाब दे दिया और मा0 नेता विरोधी के पास कोई तथ्यात्मक बात नहीं है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया, शोर शराबा के मध्य)

मान्यवर, कृषि की आय को दुगुनी करने, किसानों को हर प्रकार से लाभ पहुँचाने और इस सरकार में हर प्रकार से यह कोशिश की जा रही है कि किसानों को जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, जो खेती में काम आने वाली हैं उनको सुविधापूर्वक उपलब्ध कराया जाये। पूरा जवाब आया है। उनके पास जब कोई तथ्य बचा नहीं तो वह वहॉ पर पहुंच गये। मान्यवर, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जो बैंकिंग का विषय उठाया गया उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो आप कम से कम एक मेरिट पर बात करिये। एक जिम्मेदार सदस्य को कम से कम अपने पद की गरिमा तो बनाये रखनी चाहिए और विषय क्या हो रहा है और कहॉ पहुंच गये। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस विषय को मा0 नेता विपक्ष ने रखा है आप इसको कार्रवाई से निकाल दें। सांठगांठ तो यह करते हैं हम लोग सांठगांठ करने वाले नहीं हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में लाठी चली। बता दें कहाँ लाठी चली ? इन्होंने कहा कालाबाजारी हुयी। बता दें कहॉ कालाबाजारी हुयी ?

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या आज उत्तर प्रदेश में किसान कर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, किसान हताश है, निराश है और किसान परेशान है। यह सरकार किसान विरोधी है। सरकार के किसान विरोधी रवैये के विरोध में हम सदन से बहिगर्मन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें।

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत के इतिहास में 10 प्रतिशत किसानों की आत्महत्या गिरी है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में गिरी है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। मैं तो इसलिए खड़ा हो गया था कि थोड़ा सा वातावरण गरम हो गया था। और प्रश्न बहुत सुंदर था और मा0 मंत्री जी उत्तर भी बहुत सुंदर दे रहे थे। बीच में कुछ कटुता आ गयी जिसका संबंध प्रश्न और उत्तर से नहीं था। हम समझते हैं कि हमारे खड़े होने से और आप सबका ध्यान आकर्षित करने से वह कटुता समाप्त हो गयी। अगर आप अनुमति दें तो हम अगला प्रश्न ले लें।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, उत्तर तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

अगर उत्तर नहीं आयेगा तो कोई जबरदस्ती होगी क्या।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द जी, नेता कांग्रेस से बराबर मिला करते हैं। उन्हीं से मिलकर पूछ लेंगे तो सही जानकारी उनको मिल जाएगी कि नीरव मोदी और ललित मोदी को किसके जमाने में बैंक वालों ने किसके कहने से कर्जा दिया।

श्री अध्यक्ष-

सुखदेव राजभर जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारे कृषि मंत्री जी का उत्तर भी आ गया था। आपने दूसरा प्रश्न आमंत्रित कर लिया और महाना साहब खड़े भी हो गये उत्तर देने के लिए फिर मा0 मंत्री जी का प्रवचन शुरू हो गया और आपका आदेश भी नहीं था। आपकी रूचि भी नहीं है। अच्छी बात है। यह किसानों से जुड़ा मसला है। मान्यवर, हम नियम-49 में लिखकर दे रहे हैं। आप इस पर एक घंटे की चर्चा करवा दीजिए। हम इसी की मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन यह जो परस्पर एक-दूसरे के नेताओं पर टिप्पणियां होती हैं इनको हम किस नियम में लिया करें ? आप तो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। आप यहां पर बैठते भी रहे हैं। हमको मार्गदर्शन चाहिए कि जब कृषि पर बहस हो, बेरोजगारी पर बहस हो, बिजली पर बहस हो और उस बहस में थोड़ी गर्मी आए तो भी ठीक है, थोड़ी नोक-झोंक हो तो भी ठीक है, लेकिन यहां तमाम विद्ववतजन अनुभवी आदरणीय सदस्य होने के बावजूद लगता है कि जैसे किसी एक का नाम आया तो बड़े आक्रमकता के साथ दूसरे पक्ष द्वारा, आलू को लेकर शोर का ऐसा वातावरण हमने नहीं देखा। कृषि कार्य को लेकर, धान को लेकर मैंने आक्रमकता नहीं देखी। यदि धान के साथ

किसी का नाम आ जाए तो उसमें रेडी-टू-गो उबलने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरा ख्याल है कि हो गया ऐसा कांड मनोरंजन का। अब हम आगे बढ़ें।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आपने बड़ी अच्छी परिपाटी डालने के लिए एक बात खड़े होकर कहीं, लेकिन हमारी संसदीय परम्परा में जो एजेंडा बनता है उसमें प्रश्न के उत्तर का अलग विषय है। हम जब जनरल किसी विषय पर चर्चा करते हैं चाहे वह बजट पर हों, चाहे अभिभाषण पर हों, लेकिन जब अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो उस पर अलग बातें आती हैं उसमें कुछ अंताक्षरिक जवाब और तर्क-विर्तक हो जाए तो वह अच्छा है। लेकिन जब सवालों के जवाब देते समय अगर कुछ ऐसी बातें बोली जाएंगी तो उसमें गलत संदेश जाएगा और गलत परिपाटी बनेगी। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है आप ही देख लें कि मा0 कृषि मंत्री जी ने उत्तर देते समय कुछ भावावेश या अपनी पीठ थपथपाते हुए तमाम मा0 सदस्यों के साथ इन्होंने जो शुरू किया उसमें जमाखोर तक भी बता दिया। मान्यवर, आजादी के 70 सालों में यह बात सर्वविदित है कि किसान का हिमायती कौन है और कौन जमाखोरों का हिमायती है? यह आम जनता जानती है और आम मतदाता जानता है। इसको कोई छुपा नहीं सकता है, लेकिन सवालों के जवाब में अगर ऐसा उत्तर दिया जाएगा तो यहां इस तरह का वातावरण जरूर पैदा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

पारस नाथ जी कम से कम इतनी बात तो जरूर कही है कि इस आदरणीय सदन में कोई बेईमान, कोई कामचोर नहीं आया है।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। इस सदन की एक गरिमा है और प्रतिष्ठा भी है। मंत्रीगण की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। मान्यवर, एक साल से हम लोग विधान सभा में सत्ता से बाहर हैं। जनता ने इनको बहुमत में कर दिया और हमको अल्पमत में कर दिया। कोई कारण होगा तभी इनको सत्ता में कर दिया और हमको सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन एक साल से लगातार मुख्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री आज तक हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जमाखोर हैं। इसमें किसान जमाखोर होता है क्या ? इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब किसानो के जनप्रतिनिधि हैं। किसान के बेटे हैं। मान्यवर, यह लोग किसानों के बड़े हितैषी हैं और एक महीने में महोबा में, ललितपुर में, झांसी में, सीतापुर में कई-कई किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है और ये सरकार जान-बूझकर जनता के बीच में अफवाह फैलाती है, इसलिए किसान-विरोधी सरकार के विरूद्ध हम और हमारा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इन्होंने महोबा और हमीरपुर के बारे में जो चर्चा की है, यह नितांत निराधार और गलत तथ्यों पर आधारित है। वहां पर किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है, यह एकदम निराधार और गलत है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमने एक छोटी-सी मांग की थी कि ये अगर किसान के हमदर्द हैं तो आपका निर्देश हो तो उस पर एक घंटा चर्चा हो जाए। लेकिन सरकार किसानों पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री सुखदेव राजभर ने बसपा के सदस्यों साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

प्रदेश में रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु मेक इन यू0पी0 सेल का गठन के सम्बन्ध में

***2-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार को प्रोत्साहन देने व मैन्यूफैक्चरिंग व निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति के तहत मेक इन यू0पी0 सेल का गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं। मेक इन यू0पी0 विभाग के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आर0 के0 वर्मा जी कुछ पूछना चाहेंगे ?

डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, मेक इन यू0पी0 सेल का गठन अभी प्रक्रियात्मक है, इसलिए किसी अनुपूरक प्रश्न का औचित्य नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आर0 के0 वर्मा जी इससे संतुष्ट हैं ?

डा0 आर0 के0 वर्मा-

जी हां।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि गठन की कार्रवाई प्रक्रियात्मक है तो, वे केवल इतना बता दें कि यह कार्रवाई कब तक क्रियाशील हो जाएगी ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें कई विभागों से संबंधित अन्तर्विभागीय परामर्श करना पड़ता है, क्योंकि एक नया विभाग अपने आपमें बनाना है और यह मेक इन यू0पी0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमने गवर्मेंट ऑफ इण्डिया में भी हमने निवेदन किया है कि मेक इन इण्डिया के साथ मेक इन यू0पी0 का एक अलग सेल बना दिया जाए। मान्यवर, ये सभी कार्य प्रक्रियाशील हैं, इनमें थोड़ा समय भी लगता हैं, इन्हें यथाशीघ्र पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि ये समन्वयकारी होगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें कोई समय-सीमा नहीं तय की गई है।

प्रदेश के दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को वर्ष 2016-2017 में वंचित छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने विषयक

3-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पढ़ रहे दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को वर्ष 2016-2017 में धनाभाव के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वंचित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हां।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर पात्र छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित देय धनराशि छात्रों के बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

राज्य वित पोषित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 580621 छात्रों को उपलब्ध धनराशि रु0 65304.83 लाख का भुगतान नियमावली में अंकित वरीयता श्रेणी के अनुसार किया गया है। यह योजना फण्ड एडेड योजना होने के कारण वर्ष विशेष की देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, राजनीति में बहुत सारे विषय राजनीति के होते हैं और कुछ विषय सामाजिक होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं। खासकर, जब समाज में उन बच्चों की बात हो जो देश और प्रदेश का भविष्य हैं तो उस पर इस तरह का जवाब जो माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं दो सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो प्रश्न मैंने पूछा उसके जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से यह धनराशि जब आएगी तो इन बच्चों को छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन बच्चों की छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति अभी नहीं हुई है। क्या भारत सरकार को प्रदेश सरकार या माननीय मंत्री जी ने कोई पत्र लिखा या उस पर क्या जवाब आया कि कब तक केंद्र सरकार से यह आश्वासन मिला है कि इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जल्दी-से-जल्दी ये छात्रवृत्ति आएगी क्या इसकी कोई समय-सीमा तय हो गयी? अध्यक्ष जी, यह 2016-17 की बात है, वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं है और वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति आने की भी कोई गुंजाइश मुझे दिखायी नहीं दे रही है। 02 वर्ष पीछे हम पहले से ही चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न सबसे पहले यह है कि क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को इस छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति के लिए कोई पत्राचार किया है और किया है तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया कि कब तक यह पैसा उन छात्रों की पढ़ाई के लिए आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न बहुत बढ़िया है।

श्री रमापति शास्त्री-

भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी मॉग प्रस्तुत की गयी है। भारत सरकार से यह आश्वासन भी मिला है कि जल्दी से जल्दी केन्द्रांश आयेगा और छात्रों को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वर्ष 2016-17 का कब तक आ जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, भारत सरकार से निवेदन किया गया है और भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इसका पत्र कब लिखा गया है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट सवाल है कि क्या पत्राचार हुआ, उस पत्र का जवाब भारत सरकार से क्या आया, क्या समयावधि तय की गयी कि कब तक उन बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा आ जायेगा ? अध्यक्ष जी, मेरा यह सीधा सा प्रश्न है।

श्री रमापति शास्त्री-

एक प्रक्रिया है, पत्र आने-जाने की और भारत सरकार ने हमें आश्वासन दिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट सवाल है, वर्ष 2017-18 का यह शैक्षिक सत्र चल रहा है जो मार्च में खत्म हो जायेगा, अभी जो 2016-17 की फाइल चली है, दिल्ली तक नहीं पहुँच पायी है, उसका जवाब नहीं आ पाया है। वर्ष 2016-17 का नहीं आया, 2017-18 का कब आयेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मान्यवर, आप इस पर जवाब दिला दीजिए कि यह पैसा कब तक आ जायेगा, इसका आश्वासन हम चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य का सवाल है, हम स्पेशल मैसेन्जर भेज कर और इस बात के लिए परसू भी करेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जवाब आ जाए। मान्यवर, मैं यह आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ ।

श्री उमा शंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी पूरा उत्तर पढ़े होंगे और थोड़ा सा मेरी जानकारी में भी है इसलिए आपके माध्यम से आ जाए। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के प्रथम अंश में यह कह दिया है कि भारत सरकार से प्राप्त होने के बाद यह भुगतान किया जायेगा और द्वितीय अंश में इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि यह योजना एडेड योजना होने के कारण वर्ष विशेष की देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जाती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, जो यह उत्तर आया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रथम अंश में लिखे हैं कि हमने भारत सरकार से मॉग किए हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि कब आपने मॉग किया है और भारत सरकार की रिप्लाई क्या आयी, लेकिन यह नहीं बता पाए। मान्यवर, फिर उत्तर में आया कि हमने इसकी मॉग की है और प्राप्त होने के बाद इसका भुगतान करेंगे और द्वितीय अंश में लिख रहे हैं कि यह अगले वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सकता तो माननीय अध्यक्ष जी, हम इसमें आपका मार्ग-दर्शन चाहेंगे।

श्री रमापति शास्त्री-

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 2016-17 में धनराशि उपलब्ध होती है तो उसको देने के बाद में जितने छात्र बच जाते हैं, वह बच जाते हैं क्योंकि यह व्यवस्था आप लोगों ने पहले से ही बना रखी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

अध्यक्ष जी, इसमें कोई छात्र-छात्राओं की गलती तो है नहीं और आप यह स्वीकार भी कर रहे हैं कि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, हम पत्राचार कर रहे हैं और आप यह भी कह रहे हैं कि उनसे प्राप्त होने के बाद हम वितरण भी करेंगे और द्वितीय अंश में कह रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में यह नहीं किया जा सकता है तो इसमें उन छात्र-छात्राओं का क्या दोष है ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए भारत सरकार से मांग के माध्यम से मिलता है। भारत सरकार से निवेदन कर लिया गया है और भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है। यह सामान्य वर्ग का है, सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जितना छात्रवृत्ति का पैसा होता है, वह दे दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सामान्य वर्ग शब्द कहॉ आया है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक प्रश्न है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई इन्होंने कहा कि जी हां प्राप्त नहीं हुई है फिर पूछा कि यदि हां तो सरकार ऐसे वंचित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायेगी, इसके जवाब में कह रहे हैं कि नहीं अगले वित्तीय वर्ष में हम नहीं करायेंगे। प्रथम में कह रहे हैं कि हां प्राप्त नहीं हुई है प्राप्त होने पर हम करायेंगे और द्वितीय में कह रहे हैं कि हम अगले वित्तीय वर्ष में नहीं करा सकते हैं। अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर विषय है। इस सवाल का जवाब जिन भी अधिकारियों ने जो भी दिया है यह बहुत गम्भीर विषय है इस पर आपका निर्देश चाहिए और आपका इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर का पहला पैराग्राफ है वह आप देख लें वह केवल एस0सी0/एस0टी0 के लिए है और दूसरा पैराग्राफ में यह है कि राज्य वित्त पोशत सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 दूसरे में स्पष्ट रूप से है कि सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वह केवल सामान्य वर्ग के लिए है और उसी सामान्य वर्ग के लिए यह कहा गया है कि यह योजना फण्ड एडेड योजना होने के कारण वर्ष विशेष की देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनित नहीं की जा सकती। ये एस0एसी0/एस0टी0 के लिए लागू नहीं है, पहले पैराग्राफ में पूरी बात कही गयी और जैसा कि मैंने आपके माध्यम से आश्वस्त किया कि हम स्पेशल मैसेनजर भेजकर इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, सवाल तो उसी का है कि यदि प्राप्त होगा तो क्या करेंगे उसके जवाब में दे रहे हैं तो उसका जवाब ही आ जाये कि नहीं जो लोग वंचित रह गये हैं, उनको हम देंगे।

श्री अध्यक्ष-

एस0सी0/एस0टी0 को तो कह रहे हैं कि देंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें यह है कि 2016-17 के जो वंचित छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, क्या उनको इस सत्र में देंगे कि नहीं देंगे सिर्फ यह बता दें और 2017-18 का देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

किस वर्ग के पूछ रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

एस0सी0/एस0टी0 या सामान्य।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर भी तो अलग-अलग है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो मैंने मूल प्रश्न पूछा है उसमें मैंने किसी वर्ग की बात ही नहीं की। मैंने एक सामान्य बात पूछी उसमें सामान्य भी हैं उसमें अनुसूचित जाति भी हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग भी है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में तो अलग-अलग आ गया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अलग-अलग सामान्य वर्ग के छात्रों की बात है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो महत्वपूर्ण बात यह कही जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विषय से जहां कहीं भी काम अटका होगा, विशेष संदेश वाहक भेजकर आग्रह करा लिया जायेगा और शेष कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी, आप सब अवगत हैं कि ऐसा कहना आश्वासन हो गया, आश्वासन समिति भी पीछे पड़ेगी तो काम हो जायेगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद।

प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन के लिये कार्य-योजना विवरण

4-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या योजनाएं, स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सलेंस प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

जी हां।

खेल विभाग द्वारा उदीयमान खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविर, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास, स्पोर्ट्स कालेजेज, विशेष प्रशिक्षण शिविर, प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों एवं समितियों को अनुदान, राष्ट्रीय एवं

अन्र्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार, विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार, प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता आदि से कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का विवरण अनुपूरक सामग्री में उल्लिखित है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में 16 खेलों में 19 जनपदों में कुल 890 (670 बालक एवं 220 बालिका) खिलाड़ियों का 44 छात्रावास संचालित किया जा रहा है। साथ ही खेल के विकास हेतु प्रदेश के 03 स्थानों पर स्पोर्ट्स कालेज संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे दो सबसे पहले ऐतिहासिक हिस्टॉरिकल फैक्ट देना चाहूंगा और उसके बाद अपना सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं सवाल पहले पूछिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

एक बात यह है कि एक क्लीयर को-रिलेशन है किसी भी मूल्क का अगर वो एक पॉवर बना है तो उसी स्पोर्ट्स के साथ चला। ओलंपिक गेम्स में जब ग्रीस एक सुपर पॉवर था तभी चला, जब सोवियत यूनियन सुपर पॉवर था तो वो लोग ओलंपिक्स जीतते थे। फिर अमेरिका का समय आया और सौ गोल्ड मेडल चाइना में जीता।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पर आइये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

कि जब कोरिया में दोनों कोरिया साउथ में नॉर्थ कोरिया का विभाजन हुआ था 1950 में तो एक नस्ल होने की वजह से दोनों की हाइट बराबर थी, एवरेज हाइट पॉपुलेशन भी बराबर थी, क्योंकि एक नस्ल थी, लेकिन बेटर स्पोर्ट्स फैसेलिटिज और बेटर न्यूट्रिशियन की वजह से 50 साल के बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की हाइट में 3 इंच का फर्क हो गया। सेम नस्ल होने के बावजूद।

मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम लोगों को भी पॉवर बनना है तो को-रिलेशन है स्पोर्ट्स से और अगर हमें अपनी नस्ल इम्प्रूव करनी है और एवरेज हाइट बढ़ानी है ज्यादातर तंदरूस्त नौजवान और नवयुवतियों को आगे हम लोगों को प्रोड्यूज करना है पैदा करना है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा।

अब मैं इसी लाइन पर अपना सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके मंदिर और मस्जिद धर्म के केंद्र होते हैं उसी तरीके जो स्टेडियम्स जो होते हैं वो स्पोर्टस के केंद्र होते है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या वे ये आश्वासन देंगे कि इस वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद जो एक बड़ा महानगर है और उसमें कोई भी स्टेडियम नहीं है, एथलेटिक्स और क्रिकेट के लिए तो क्या एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम के लिए जगह एक्वॉयर करके उसमें एक स्टेडियम का डी0पी0आर0 बनवाएंगे जिसमें आई0पी0एल0 लेवल के और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच हो सके क्या माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे।

श्री चेतन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक साल में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए। बहुत सारे खिलाड़ी मेरे पास आते थे। माननीय अध्यक्ष जी जब से ये सरकार आई है हम लोगों ने क्योंकि रोजगार चाहिए था खिलाड़ी को, खिलाड़ी की जवानी चली जाती है खेल में उसको ध्यान में रखते हुए और 30 साल और 31 साल के कैरियर शुरू करना। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा सरकार में 11 सरकारी विभागों में नियुक्तियां खोल दी हैं और जो हमारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको नियुक्तियां दी जाएं। जो प्रश्न किया है मान्यवर 70 स्टेडियम अभी चल रहे हैं। 75 जिलों में से 70 जिलों में हमारे स्टेडियम हैं। जहां पर वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय कीड़ा स्थल हैं वो करीब 66 हैं जो इस समय चल रहे हैं। तरणताल की बात यदि करता हूँ तो 38 तरणताल हैं। जहां तक इलाहाबाद का सवाल है क्रिकेट का एक मैदान है अभी कुछ ही महीनों पहले बहुउद्देशीय हॉल की हम लोगों ने शुरूवात की है। बैटमिंटन हॉल है, टेबिलटेनिस का भी हॉल है वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का विचार इलाहाबाद में नहीं है।

(एक सदस्य द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप भी खेलते हो ?

श्री हर्षवर्धन वाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए कोई योजना बनेगी ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं मा0 खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ । मा0 मंत्री जी आप मेरा सवाल ले लीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में जब मा0 मंत्री जी को खेल का विभाग मिला तो आम लोगों में और सारे खिलाड़ियों में एक बड़ा अच्छा सन्देश गया कि चलिए कम से कम अब एक अन्तर राष्ट्रीय खिलाड़ी को खेल विभाग का चार्ज मिला है। आज एक साल बीत गया है लेकिन एक साल बाद भी मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में किसी नए स्टेडियम या खेलों के प्रोत्साहन हेतु किसी नई योजना का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने लिख दिया कि 19 जनपदों में छात्रावास संचालित हैं जो कि पूर्व से हैं। हम इसकी डेट नहीं पूछना चाहते कि ये कब से चले आ रहे हैं? इन्होंने लिखा कि 890 खिलाड़ियों के 44 छात्रावास 19 जनपदों में संचालित हैं। इतने बड़े प्रदेश में मात्र 19 जनपदों में छात्रावास संचालित हैं और 03 स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। मैं आपकी अनुमति से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो मात्र 19 जनपदों में छात्रावास चल रहे हैं। अगर मा0 मंत्री जी इतने ही गम्भीर हैं तो क्या प्रदेश के सभी जनपदों में इस तरह के छात्रावासों को संचालित करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे ? दूसरा, जो प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेजों की संख्या मात्र 03 है तो क्या इनकी संख्या को भी बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने पर विचार करेंगे ?

श्री चेतन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, ये जो स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके अलावा हमारे स्टेडियम हैं, स्टेडियम में बाकायदा खेल चलते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षक हैं, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं

और वहाँ पर खेल चलते हैं लेकिन ये जो हॉस्टल होते हैं, इसमें एक खेल के लिए एक ही हास्टल होता है तो इसीलिए अभी जो हैं, वह पर्याप्त हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बाकी जो स्टेडियम हैं वहाँ पर लगातार खेलों का आयोजन होता रहता है। जहाँ तक आपका सवाल आया कि मैं अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ तो आज यहाँ पर बहुत कुछ किया गया है। पहले केवल 26 खेल चलते थे, अब हमने बढ़ाकर 30 खेल कर दिए हैं और 30 खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी जाती है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने से शोर एवं व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इसमें कागज फेंकने वाला खेल बढ़वाना चाहते हो ?

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, मेरा पूरा उत्तर तो सुन लें। मेरा एक निवेदन है।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, कानपुर में आई0पी0एल0 की शुरुआत मा0 अखिलेश यादव जी ने कराई, आई0पी0एल0 चालू करवाया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने अभी आई0पी0एल0 पर ही सवाल पूछा है कि क्या इलाहाबाद में आई0पी0एल0 होगा इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ । हम यह बताना चाहते हैं कि जो कानपुर में आई0पी0एल0 होता था, आपने वह तक बन्द करा दिया। आपके आई0पी0एल0 लाने वाले जो मोदी साहब थे, वही भाग गए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ और सरकार यह बताए कि कानपुर में आई0पी0एल0 वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप यही बता दीजिए क्योंकि आप खुद क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और आप खुद ही कानपुर शहर में क्रिकेट का गला घोंट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से सरकार आई है, गॉवों की तरफ छोटे मिनी स्टेडियम खोलने के लिए मा0 मंत्री ने पूरा प्रयास किया है। हमारा जो हर्रैया विधान सभा क्षेत्र है, उसमें हर्रैया तहसील है जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ी तहसील है, उसमें 1535 राजस्व गॉव हैं। वहॉ पर एक सूजीपुर स्थान है जहॉ पर मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव था। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया और मा0 मंत्री जी से कई बार अनुरोध भी किया कि मा0 मंत्री जी उस पर क्या हो रहा है, उस प्रस्ताव में क्या हो रहा है? मा0 मंत्री जी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट में प्रस्ताव गया हुआ है। मेरा मा0 मंत्री जी से यह कहना है, मेरा प्रश्न है कि सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से वह प्रस्ताव कब तक वापस आएगा? आपने मिनी स्टेडियम की शुरुआत की और एक अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में आज आप इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं तो ये मिनी स्टेडियम कब से बनना शुरु हो जाएँगे और जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार में गया हुआ है, वह कब तक वापस आ जाएगा ?

श्री चेतन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत सरकार की योजना **खेलो इण्डिया खेलो** में हमारे पास अलग-अलग जिलों से, अलग-अलग मा0 विधायकों के 114 प्रस्ताव मिनी स्टेडियमों के लिए आए थे लेकिन उसमें

मानक कुछ बदल गए और अब दोबारा से केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं। जो हमने 114 प्रस्ताव भेजे थे वे निरस्त कर दिए गए हैं। अभी हमारे पास 4 प्रस्ताव आए हैं और जैसे ही हमारे पास प्रस्ताव पूर्ण हो जाएँगे तो ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाएँगे। क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है और माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक निवेदन है कि अगले सत्र में मैं चाहूँगा कि इसमें दो घंटे की चर्चा हो क्योंकि खेल नौजवानों से जुड़ा हुआ है और अभी जय प्रताप सिंह जी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जो ड्रग्स लेते हैं उनको भी खिलाया जाता है क्योंकि यह नौजवानों से संबंधित है इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे सदन में इसकी चर्चा हो और एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके अंदर जाए।

प्रदेश में युवाओं के विकास एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रमों का विवरण

***5-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के प्रतिभा विकास एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हैं तथा उन कार्यक्रमों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

युवा कल्याण विभाग में युवाओं के विकास एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से निम्न योजनाएं संचालित है :--

1-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (जिला योजना)-सभी आयुवर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत 05 खेल विधाओं यथा-एथलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, भारोत्तोलन तथा कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लाक एवं जनपद स्तर पर किया जाता है।

2-ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण-राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के ग्रामीण खेलों में विजयी खिलाड़ियों को इस योजना के अन्तर्गत प्रथम स्थान धारक खिलाड़ी का रु0 25,000/- द्वितीय स्थान धारक खिलाड़ी को रु0 15,000/- एवं तृतीय स्थान धारक खिलाड़ी को रु0 10,000/-की दर से पुरस्कृत किया जाता है।

3-युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन-

प्रत्येक ग्राम में युवक तथा महिला मंगल दलों का गठन किया जाता है। 14 से 35 वर्ष की आयु सीमा तक के युवा इन मंगल दलों के सदस्य होते हैं। गठित दलों का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत कराया जाता है। मंगल दलों द्वारा सामाजिक कार्यों एवं ग्रामीण खेलकूद, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत योजना, वृद्धा एवं विधवाओं को पेन्शन दिलाने में योगदान, दहेज प्रथा उन्मूलन अन्तर्जातीय एवं विधवा विवाह, प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान कार्य एवं आर्थिक कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने पर अग्रणी युवक/महिला मंगल दलों को रु0 2000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।

4-राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं के योगदान हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन-युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में जोड़ने हेतु इस कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है। इस दिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

5-जन जागरूकता कार्यक्रम-जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की ग्राम विकास हेतु जनपदों में चलायी जा रही विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण जनों को जानकारी उपलब्ध कराना है।

6-युवा उत्सव-युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें निर्धारित 18 सांस्कृतिक विधाओं में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग कराया जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में 02 परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

7-विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना-वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी 75 जनपदों में युवक एवं महिला मंगल दल में एक सर्वश्रेष्ठ दल तथा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 03 युवक एवं 03 महिला मंगल दलों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें जनपद स्तर पर रु0 5,000/- एवं राज्य स्तर पर युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु0 1,00,000 नकद (चल बैजयन्ती सहित), रु0 50,000 एवं 25,000 नकद के कुल 6 पुरस्कार जिनमें तीन पुरस्कार युवक मंगल दलों के लिये एवं तीन पुरस्कार महिला मंगल दलों के लिये होंगे।

8-'खेलों इण्डियाः नेशनल स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ स्पोर्ट्स'-भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 14-10-2017 द्वारा पुनसंरचित खेलो इण्डिया-राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम योजना लागू की गयी है जिसमें निम्न घटक शामिल किए गए हैं :--

(1) खेल मैदान विकास (2) सामुदायिक कोचिंग विकास (3) राज्य स्तर खेलों इण्डिया केन्द्र (4) वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं (5) प्रतिभा खोज और विकास (6) खेल अवसंरचना का उपयोग और सृजन/उन्नयन (7) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमियों को सहायता (8) स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस (9) महिलाओं के लिए खेल (10) विकलांग लोगों के बीच खेल का सम्बर्द्धन (11) शान्ति एवं विकास के लिए खेल (12) ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री चेतन चौहान द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने, उत्तर लंबा होने की स्थिति में)

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, उत्तर जरा लम्बा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठे। आप के पास यह उत्तर अधिकारियों द्वारा तैयार करके लाया गया होगा आपने अभी स्वयं कहा कि लंबा है और मुझे भी उत्तर लंबा दिखायी पड़ रहा हैं प्रश्नों के उत्तर प्रायः लम्बे हो रहे हैं तो कम से कम आप बैठक करके अपने विभाग को ठीक करिये कि इतने लम्बे निबन्ध लिखने की जरूरत क्या है ? (सदन में मेजों की थपथपाहट)

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने युवाओं की प्रतिभा विकास और प्रोत्साहन के लिए 2 पन्ने का उत्तर हमको भेजा है। निश्चित रूप से सरकार की युवाओं की प्रतिभा, विकास और प्रोत्साहन के लिए तमाम उसमें योजनाएं हैं। निश्चित रुप से हमारे माननीय मंत्री जी योग्य और विद्वान सरकार के मंत्री हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए सरकार के उत्तर से अपने को संतुष्ट करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के अपने-अपने आसन से बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिए, हमारे मंत्री जी वास्तव में सज्जन आदमी हैं और कोई मंत्री यह न कह पाता कि उत्तर लम्बा है। तो अब आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, वह सबके काम करा देंगे।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि गत वर्ष कितना बजट प्रस्तावित था और उसके सापेक्ष आपने कितना खर्च कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, अब उन्होंने यह भी एक प्रस्ताव कर दिया कि एक बार विधान सभा में खेलों पर ही चर्चा हो और मेरी भी बड़ी इच्छा है यहां तमाम नए खेल हैं और इधर जो राज्यपाल जी के सामने खेल हुआ था वह सीटी बजाने वाला और नाचने वाला ।

(सदन में हंसी)

चूंकि वह खेल का पीरियड होगा इसलिए हम भी नीचे आएंगे, नाचेंगे आपके साथ।

हाजी इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मैच करा दिया जाए क्योंकि माननीय मंत्री जी क्रिकेट से मुतालिक है इण्टरनेशनल खिलाड़ी हैं हम सब लोग यहां पर मौजूद हैं और सब लोग चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े अगर हम लोग भी इस तरीके से कोई व्यवस्था कर दें खेल की जैसे पिछली सरकारों में हुई है क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वयं खेल से जुड़े हुए इण्टरनेशनल खिलाड़ी हैं तो सामने वालों का विपक्ष से मैच करा दिया जाये और मैदान में भी लोग देखें, इन्शा अल्लाह यह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ।

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, यह आपका निर्णय है अगर आप बोल दें बिल्कुल खेल के मैदान में भी दो-दो हाथ हो जाने दीजिएगा।

(कुछ सदस्यों के अपने-अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिए, क्रिकेट के खेल की अनुमति हम दे सकते हैं लेकिन उसमें सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष का विभाजन नहीं होगा। बाकी जगह हम सत्तापक्ष-विपक्ष बने रहते हैं अब हर बात में बने रहें यह ठीक है और खेल मंत्री जी तैयार हैं तो आगे फिर, अब आप कृपया बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठिए, आप तो तैयार है।

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, क्रिकेट के अलावा भी और कोई खेल, फुटबॉल खेलना चाहे या कोई और खेल भी खेलना चाहे बिल्कुल तैयार हैं, आयोजन बिल्कुल अच्छी तरह से हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह विषय विचार में आ गया, हम लोग विचार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राम गोविंद जी, माननीय वर्मा जी। आप कृपया बैठें।

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या-05 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए गरीबी रेखा की आय सीमा बढ़ाने की जानकारी

***6-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गरीबी रेखा की आय सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रमशः वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्री पारिवारिक लाभ योजना संचालित है। इन योजनाओं में शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा गरीबी की आय सीमा में बढ़ोत्तरी की जा चुकी है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 25546/- की वार्षिक आय सीमा निर्धारित थी। शासनादेश सं0-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा क्रमशः उक्त योजनाओं में वार्षिक आय सीमा में संशोधन करते हुये ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी ग्रामों में खेल का मैदान बनाने की कार्य-योजना की मांग

***07-श्री देवमणि द्विवेदी-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हर ग्राम में खेल का मैदान विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बड़े शहरों में जनसंख्या के हिसाब से अनाज एवं सब्जी मण्डियों की संख्या बढ़ाने की मांग

***08-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलावार कुल कितने अनाज और सब्जी की मण्डियां हैं तथा उनमें से कितनी मण्डियां ई-मण्डियों से जुड़ी हैं और शेष कितनी रह गयी हैं ? क्या सरकार बड़े शहरों में जनसंख्या के हिसाब से अनाज एवं सब्जी मंडियों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण, कृषि विपणन मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 251 मण्डियां तथा 374 उप मण्डियां अधिसूचित हैं इनमें से 219 प्रधान मण्डी एवं 93 उप मण्डी स्थल निर्मित हैं। इन मण्डी समितियों में से निर्मित 100 प्रधान

मण्डी स्थल ई-नाम से जुड़े हुए हैं शेष 119 प्रधान मण्डी स्थल ई-नाम से जुड़े नहीं हैं। उपरोक्त मण्डी स्थलों में से 72 फल सब्जी मण्डी के ही हैं।

बड़े शहरों में जनसंख्या के हिसाब से अनाज एवं सब्जी मण्डियों की संख्या बढ़ाया जाना मण्डी परिषद् द्वारा इस विषय में निर्धारित मानकों की पूर्ति तथा प्रश्नगत स्थल पर भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के दुर्घटना उपरान्त मण्डी समिति से अनुदान दिये जाने की मांग

***09-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्य करते समय यदि कृषि कार्य में कोई किसान/खेतिहर मजदूर जल जाता है, तो मंडी समिति से अनुदान देने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अनुदान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

मण्डी परिषद् द्वारा ''समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना'' संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय घटित दुर्घटना पर आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धागा बनाने की बन्द मिलों को पुनः चलवाये जाने की मांग

***10-श्री सोहिल अख्तर अंसारी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद-मऊ, मऊ आईमा, इलाहाबाद, फतेहपुर, सण्डीला, बाराबंकी, मगहर, बहेड़ी मिल, बरेली, रायबरेली, जौनपुर तथा अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में पूर्व में स्थापित धागा बनाने की मिल जो कि कई साल से सरकारी उपेक्षा के कारण बन्द पड़ी हैं, को क्या सरकार फिर से चलाकर धागे का निर्माण करायेगी तथा यहां से दूसरे प्रदेशों को रोजगार हेतु गये बुनकरों को आकर्षित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

लगातार हो रहे घाटे के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में इस उद्योग ने व्याप्त मन्दी, विपरीत बाजारीय परिस्थितियां तथा जर्जर वित्तीय स्थिति के कारण उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर की सभी अधीनस्थ मिलें बन्द हैं तथा मिलों के श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा वी0आर0एस0 का हितलाभ प्राप्त कर लिया गया है। मिलों के चलाये जाने की कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बन्द पड़ी मिलों की परिसम्पतियों का मूल्यांकन व मशीनों की क्रियाशीलता तथा क्षमता का आंकलन एवं भूमि आदि के सदुपयोग किए जाने की सम्भावनाओं के परीक्षण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा एक कन्सलटेन्ट नियुक्त कर वर्तमान सम्भावनाओं का आंकलन करके अपनी रिपोर्ट गठित समिति से परीक्षणोपरान्त लिक्विडेशन/मा0 एन0सी0एल0टी0, इलाहाबाद से पूर्वानुमति प्राप्त कर अपने स्रोतों अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर कंपनी की वर्तमान देयताओं का अन्तिम रूप से भुगतान कर भूमि का उचित उपयोग प्रदेश में औद्योगिकीकरण के बढ़ावा हेतु किया जा सकेगा।

***11-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

12-[11वें मंगलवार के तारा0प्र0सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पिछड़े युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का विवरण

***13-श्री नफीस अहमद-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड विलरियागंज व महाराजगंज में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत गांवों व पिछड़े युवाओं को प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का वर्ष 2015-16 तक पूर्णतया क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा था। शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित उक्त योजना के लिये आवश्यक वित्तीय प्राविधान केन्द्र सरकार द्वारा ही सुनिश्चित किये जाते थे परन्तु वर्ष 2016-17 से उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित कुल भौतिक लक्ष्यों का 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित कराने का भारत सरकार द्वारा निर्णय लिय गया है। शेष 75 प्रतिशत लक्ष्य भारत सरकार द्वारा अभी भी अपने स्तर पर आवंटित किये जा रहे हैं। मार्च, 2017 में उक्त योजना के राज्यघटक के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत 04 वर्षों में (2016 से 2020) कुल 1,42,552 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रतिवर्ष के आधार पर यह संख्या 35,638 है। उक्त योजना हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु जनपद आवंटित किये जाते हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाओं एवं संभाव्यताओं के आधार पर की जाती है जो जनपद मुख्यालय, तहसील अथवा विकास खण्ड हो सकती है। जनपद आजमगढ़ में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया गया है :--

(1) डा0 बी0आर0 अम्बेडकर टेक्निकल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर।

ट्रेड-इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर।

(2) मै0 ओरियन सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड।

ट्रेड-वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रानिक्स।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 14-35 आयुवर्ग के अल्पशिक्षित एवं स्कूल ड्रापआउट युवाओं को रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्रशिक्षण सुविधा युवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा में बन्द पड़ी कताई मिल के स्थान पर कोई और उद्योग लगवाने की जानकारी

01-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बन्द पड़ी कताई मिल के स्थान पर कोई अन्य उद्योग लगवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द पड़ी मिलों की परिसम्पतियों का मूल्यांकन व मशीनों की क्रियाशीलता तथा क्षमता का आंकलन एवं भूमि आदि के सदुपयोग किए जाने की सम्भावनाओं को परीक्षण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा एक कन्सलटेन्ट नियुक्त कर वर्तमान सम्भावनाओं का आंकलन करके अपनी रिपोर्ट गठित समिति से परीक्षणोपरान्त लिक्विडेशन/मा0 एन0सी0एल0टी0, इलाहाबाद से पूर्वानुमति प्राप्त कर अपने स्रोतों अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर कंपनी की वर्तमान देयताओं का अन्तिम रूप से भुगतान कर भूमि का उचित उपयोग प्रदेश में औद्योगिकीकरण के बढ़ावा हेतु किया जा सकेगा, जिसमें उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की बांदा इकाई भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना की जानकारी

02-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ब्लाक ईसानगर में कोई सरकारी कालेज न होने के कारण शिक्षा का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा में एम0एस0डी0पी0 योजनार्गत एक नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रदान की गयी है। अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा इस संस्थान के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था, सी0 एण्ड डी0 एस0 को जारी की गयी है। वर्तमान में संस्थान के भवन के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है। क्षेत्र के युवाओं के दृष्टिगत इस संस्थान को प्रशिक्षण सत्र,

सितम्बर, 2017 से जनपदीय नोडल संस्थान लखीमपुर खीरी में संचालित कर दिया गया है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होते ही संस्थान को नवनिर्मित भवन में क्रियाशील किया जायेगा। अतः जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में आई0टी0आई0 कालेज स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूमिगत जल का दोहन करने का प्रकरण

03-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थापित मै0 कजारिया सिरेमिक्स लि0, औरियेन्ट सिरेमिक्स लि0 तथा मै0 हाईटैक पाइप लि0 आदि द्वारा भूमिगत जल का औद्योगिक उपयोग के लिये दोहन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इसके लिये सरकार से अनुमति ली है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

मेसर्स कजारिया सिरेमिक्स लि0, मेसर्स ओरियन्ट सिरेमिक्स तथा मेसर्स हाइटेक पाइप लि0 को औद्यागिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद जनपद-बुलन्दशहर में भूमि आवंटित की गयी थी। विगत कई वर्षों से तीनों इकाइयां कार्यरत है। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में निगम द्वारा जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हैं तथा आवंटियों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था स्वयं की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए सम्बन्धित विभाग से उन्हें अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करनी होती है। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के निर्देश के क्रम में सभी ऐसी इकाइयां, जिसके द्वारा भूमि जल का दोहन किया जाता हैं, उन्हें केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति हेतु मैसर्स ओरियेन्ट सिरेमिक्स द्वारा दिनांक 11-12-2017, मेसर्स कजारिया सिरेमिक्स लि0 द्वारा दिनांक 31-12-2016 एवं मै0 हाइटेक पाइप लि0 द्वारा दिनांक 25-05-2017 को आवेदन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में पावरलूम की बन्द पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित कराने की कार्य योजना

04-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत अम्बेडकरनगर जनपद का चयन पावरलूम के विशेष उत्पाद के ब्रान्ड के रूप में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पावरलूम की बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने एवं नई इकाइयां लगाने की दिशा में कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

जी हां।

जनपदवार उपलब्ध संसाधनों जैसे रा-मैटेरियल, डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं डिस्प्ले तथा मार्केटिंग से सम्बन्धित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए "SWOT" व ''गैप एनालिसिस'' के आधार पर क्रियान्वयन रणनीति की कार्य योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित कृषि विश्वविद्यालय संचालित कराने की मांग

05-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कृषि विश्वविद्यालय का भवन बनकर तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके संचालन की कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा जनपद हरदोई में कोई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

मेक इन इन्डिया योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में डिफेंस इण्डस्ट्रियल बेस बनाने विषयक

06-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा मेक इन इण्डिया योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में कई प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की डिफेंस इण्डस्ट्रियल बेस बनाने के लिये कोई खास नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

''उत्तर प्रदेश रक्षा विनिर्माण तथा एयरोस्पेस नीति'' बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन हेतु जनपद वार पात्रों की संख्या के विषय में जानकारी

07-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन हेतु जनपदवार एवं ग्रामवार पात्रों की संख्या सीमा राज्य स्तर से निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो संख्या निर्धारण का आधार क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 01 अप्रैल, 2018 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाइन आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त पात्र वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा प्रदत्त किया जाना विभाग का लक्ष्य है। इस हेतु जनपदवार एवं ग्रामवार पात्रों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में

08-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वृद्धावस्था पेंशन के कितने पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना शेष है ? क्या सभी पात्र व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेंशन स्वीकृत सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद चित्रकूट में वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र 3476 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना शेष है।

उक्त समस्त पात्र व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में किसानों के खेत की मिट्टी लेने एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को खेती करने की योजना

09-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने किसानों के खेत की मिट्टी का नमूना जांच के लिये लिया गया है एवं जांच के परिणाम के अनुसार कितने किसानों ने उस पर अमल किया है ? क्या सरकार किसानों को जांच रिपोर्ट के आधार पर खेती किये जाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (द्वितीय चक्र) में 21.34 लाख कृषकों के मृदा नमूनें ग्रिड के आधार पर जांच के लिए एकत्रित किये गये हैं। जांच परिणामों के आधार पर दी गयी संस्तुतियों पर अमल करने वाले कृषकों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

जी हां।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड से दी गयी संस्तुतियों को प्रयोग में लाने हेतु विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार (किसान पाठशाला, गोष्ठियों एवं प्रदर्शन आदि) के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र महादेवा के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में सी0सी0 रोड एवं इण्टर लांकिग, नाली निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने की जानकारी

10-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अनुसूचित बाहुल्य करियापार राउत, रेवली ग्रामों में एकीकृत योजनान्तर्गगत सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण किये जाने हेतु धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत विकास योजनान्तर्गत उपरोक्त ग्रामों का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद मिर्जापुर के वि0स0क्षे0 छानबे में उद्योग केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

11-श्री राहुल प्रकाश-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के उद्योग शून्य व अति पिछड़ा क्षेत्र छानबे में कोई उद्योग को स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' दिनांक 13 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित की जा चुकी है। निजी निवेशकों द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश करने पर उन्हें ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' में प्राविधानित सुविधायें प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांग पेंशन में नवीन पात्र आवेदकों को पेंशन प्रदान करने की जानकारी

12-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांग पेंशन में दिनांक 25-01-2018 तक ऐसे कितने नये आवेदन हैं जो जांच के उपरान्त पात्रता श्रेणी में स्वीकृत हो गये हैं तथा कितने आवेदन ऐसे हैं जिनकी जांच अभी लम्बित है ? क्या सरकार इन नवीन पात्र आवेदकों को पेंशन प्रदान करने एवं लम्बित आवेदन पत्रों की जांच पूरी करने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 25-1-2018 तक 602 नवीन आवेदकों को जांचोपरान्त दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गई है तथा 1620 नवीन आवेदकों के आवेदन-पत्रों की जांच कराई जा रही है।

जी हां।

दिव्यांग पेंशन हेतु पात्र पाये गये 602 आवेदकों को पेंशन भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 1620 नवीन आवेदन पत्रों की जनपद स्तर पर जांच पूर्ण होने एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से रिस्पान्स प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 शिवसत में निर्मित दिव्यांगों के विद्यालय का कार्य पूर्ण करने की जानकारी

13-श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के शिवसत में पैक्सफेड संस्था द्वारा निर्मित किया जा रहा दिव्यांगजनों का विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के शिवसत में पैक्सफेड संस्था द्वारा निर्मित किये जा रहे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य 30-12-2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0क्षे0 रानीगंज के जरियारी के वि0ख0 शिवगढ़ में आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जरियारी विकास खण्ड-शिवगढ़ में स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील रानीगंज में एक नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपया 200.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी सस्था, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को जारी की गयी, जिसके उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ वर्तमान में संस्थान के भवन निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति में है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि जारी होने की प्रक्रिया में है। विभाग द्वारा संस्थान के भवन निर्माण कार्य को जुलाई, 2019 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति-2017

15-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के गौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेजपुर/हथिनीखास धनश्यामपुर ग्रन्ट को औद्योगिक क्षेत्र सरकार घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम नीति-2017 के अन्तर्गत ग्रमीण क्षेत्रों में लघु औद्यागिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु ग्राम सभाओं की 10 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित कर उद्योग निदेशालय को निःशुल्क प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उस पर भूखण्डों का विकास कर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के मण्डी परिषद् में हो रही अवैध वसूली की जांच कराने एवं मण्डी परिषद् का निर्माण

16-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में 100 कि0मी0 दूर मुख्यालय पर मण्डी होने के कारण किसानों से मण्डी परिषद् अधिकारियों के द्वारा विभिन्न सड़कों पर अवैध वसूली की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा तहसील स्तर पर मण्डी परिषद् के मण्डी स्थल का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी/उप मण्डी की स्थापना के मानक पूर्ण होने तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर मण्डी/उप मण्डी स्थल के निर्माण पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

तहसील स्तर पर धौरहरा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब निर्मित है।

जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली के अन्तर्गत चल रही वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाये जाने की जानकारी

17-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के अन्तर्गत कितनी संख्या में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं ? क्या वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सरकार बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद-सीतापुर की तहसील सिधौली के अन्तर्गत कुल 5236 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है।

पात्रता की सीमा के अन्तर्गत आने वाले वृद्धजनों को पेंशन प्रदान किये जाने का विभाग का लक्ष्य है। अतः पेंशन लाभार्थियों की संख्या में अलग से वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत पुरानी मण्डी के बगल में नयी मण्डी के संचालन की जानकारी

18-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत पुरानी मण्डी के बगल में नयी मण्डी बनकर तैयार हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त मण्डी का संचालन कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां, जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय, नौगढ़ के अन्तर्गत पुरानी मण्डी के बगल में नवीन मण्डी स्थल नौगढ़ बन कर तैयार हो गया है।

निर्मित दुकानों के आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है। दुकानों को आवंटन के पश्चात् नवीन मण्डी स्थल में व्यापार स्थानान्तरित कराते हुए शीघ्र मण्डी का संचालन करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू कराये जाने विषयक

19-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना किन-किन जनपदों में लागू की गई है ? क्या सरकार मौसमीय विचलन से प्रतापगढ़ के आंवला किसानों की होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु इस योजना से प्रतापगढ़ को आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रदेश के 14 जनपदों यथा कुशीनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बहराइच, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बरेली, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, शाहजहांपुर में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2017-18 व 2018-19 में फसल केला व मिर्च को योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद शाहाजहांपुर में दीप कल्याण समिति द्वारा चलाये जा रहे वृद्धा आश्रम सम्बन्धी जानकारी

20-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा जनपद शाहजहांपुर में ''दीप कल्याण समिति'' द्वारा वनतारा, शाहजहांपुर में वृद्धाश्रम किस तारीख से चलाया जा रहा है एवं इसे सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2015 से 20-11-2017 तक कितना-कितना अनुदान दिया गया है तथा इसमें कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने वृद्धजन आश्रम में रह रहे हैं ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर की औचक निरीक्षण आख्या के आधार पर स्वैच्छिक संस्था दीपजन कल्याण समिति द्वारा जनपद शाहजहांपुर के वनतारा में दिनांक 01-05-2017 से वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है।

निदेशालय पत्र संख्या-38-46 दिनांक 19-04-2017 द्वारा संस्था को अनावर्तक मद में रु0 18,99,000/- एवं निदेशालय पत्र सं0-925-33, दिनांक 07-112017 द्वारा आर्वतक मद में

रु0 10,41,386/की धनराशि आवंटित की गयी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर की आख्यानुसार वृद्धाश्रम में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् :--

1-श्री ब्रह्मदेव, प्रबन्धक।

2-श्रीमती सुनीता, लेखाकर।

3-कुमारी रश्मि, भण्डार प्रभारी।

4-श्री यशपाल, केयर टेकर।

5-श्रीमती प्रेमवती, केयर टेकर।

6-कु0 मीना, केयर टेकर।

7-श्री गोपाल, केयर टेकर।

8-श्री रामकिशोर गुप्ता, सुरक्षाकर्मी।

9-श्री मो0 अजमेर अहमद, सुरक्षाकर्मी।

10-श्री रामकिशोर, सुरक्षाकर्मी।

11-श्री महावीर, रसोईया।

12-श्रीमती पिंकी, रसोईया।

13-श्रीमती शीतल, रसोईया।

14-श्रीमती हरीकृष्णन, सफाई कर्मचारी।

15-श्रीमती रानी, सफाई कर्मचारी।

16-श्रीमती चन्द्रावती, माली।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर की निरीक्षण आख्या दिनांक 09-10-2017 के अनुसार 51 वृद्धजन आश्रम में रह रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण दिलाने सम्बन्धी विवरण

21-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा कितने प्रशिक्षण केन्द्र किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों का प्रशिक्षण दिलाने के सम्बन्ध में चल रहे हैं तथा किस-किस केन्द्र पर 01-04-2015 से 20-11-2017 तक किन-किन युवक/युवतियों ने प्रशिक्षण लिया ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रशिक्षण केन्द्रों के ट्रेनर तथा स्टाफ तथा प्रशिक्षण के लिये शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की पूरी सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जनपद शाहजहांपुर के लिए अनुबंधित 06 प्रशिक्षण प्रदाताओं के 23 प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान में संचालित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का स्थान, उनमें प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम आदि का विवरण संलग्नक-1 पर प्रस्तुत है।

दिनांक 01-04-2015 से दिनांक 20-11-2017 के मध्य जनपद शाहजहांपुर में कुल 6,576 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेशित (इनरोल) किये गये जिनका विवरण मंत्री, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दिया गया है।

वर्ष 2015-16 में वर्ष 2017-18 तक (फरवरी, 2018) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को कुल रु0 622.63 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका वर्षवार विवरण संलग्नक† 2 पर प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को बेहतर खेती की योजना

22-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को बेहतर खेती की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

वर्ष 2017-18 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों के लिये 11115 स्प्रिंकलर सेटर वितरण की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत तालाब की योजना के अन्तर्गत 2549 खेत तालाब का निर्माण कराया जा रहा है तथा अन्य 1637 खेत तालाब का निर्माण प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भी खेत तालाबों का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त कार्यवाही विषयक

23-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसुनवाई सन्दर्भ संख्या-40015177033442 तथा मुख्य मंत्री का जनता दर्शन दिनांक 22 अगस्त, 2017, शिकायत, सन्दर्भ 151571702084925 निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 को फर्जी ढंग से अनु0 जाति धानुक का प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या शासनादेश सं0-685/26-3-2011, दिनांक 28-2-2011 में उल्लिखित नीति के अनुसार कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

---

† [देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 149-152 पर]

शिकायती पत्र में उल्लिखित श्री उमेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू निवासी ग्राम-मतुआ, परगना बालामऊ, तहसील-सण्डीला, जनपद हरदोई को निर्गत अनुसूचित जाति (धानुक) का प्रमाण-पत्र वर्तमान में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति, हरदोई के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के चोला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की जानकारी

24-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 औद्योगिक विकास लि0 द्वारा विकसित किये गये चोला औद्योगिक क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में औद्योगिक इकाईयां स्थापित कराने हेतु क्या सरकार कोई कार्य-योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

निगम द्वारा चोला जनपद बुलन्दशहर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु 10 ग्रामों की 2775 एकड़ निजी एवं ग्राम समाज की भूमि अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण हेतु चिन्हित की गयी है। इसमें से 170 एकड़ भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया है जिसमें से वर्तमान में 95 एकड़ भूमि विकसित की गयी है, जिसका कब्जा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को प्राप्त है। मौके पर किसानों के विरोध एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेशों के कारण शेष भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण इसका विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायक निवासों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की नीति

25-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय कर्मचारी लगभग 20 वर्षों से एक ही स्थान एवं एक ही शिफ्ट में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विषयक प्रश्नकर्ता का विधायक कोष्ठक नम्बर-सी0एम0ए0-00473183, दिनांक 08-05-2017 पर दर्ज पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

एक विधायक निवास से दूसरे विधायक निवास में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की विभागीय नीति अलग से नहीं है। स्थानान्तरण, सामान्य स्थानान्तरण नीति से व्यवहृत होते हैं।

शासन को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है। नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रशासनिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार विधायक निवासों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

जी, हां।

नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के चिरगांव-भाण्डेर मार्ग एवं ब्लाक बड़ागांव के बड़ागांव भसनेह मार्ग का निर्माण कराने की मांग

26-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक-चिरगांव के चिरगांव-भाण्डेर मार्ग (लम्बाई लगभग 12 कि0मी0) एवं ब्लाक बड़ागांव के बड़ागांव-भसनेह मार्ग (लम्बाई लगभग 06 किमी0) मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को नाबार्ड योजनान्तर्गत चौड़ीकरण कराते हुये सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

प्रश्नगत मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है। अतः मार्ग मण्डी परिषद् के स्वामित्व कमें न होने के कारण मरम्मत का दायित्व मण्डी परिषद् का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी तहसीलों पर आनलाइन ई-बोली लगाने की कार्य योजना बनाने की मांग

27-डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उपज के बेहतर दाम दिलाने के लिए सरकार तहसील स्तर पर आनलाइन ई-बोली लगाने की सुविधा किसानों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

भारत सरकार की ई-नाम परियोजना के अन्तर्गत 100 मण्डियों में जो विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत आती है, मैं आनलाइन बोली लगाने की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम चुल्हावली में ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

28-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम चुल्हावली में ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल कर्ज माफी के सम्बन्ध में

29-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण अभी तक माफ किया गया है तथा कितने किसानों को इसका प्रमाण-पत्र दिया गया ? जनपद-कुशीनगर एवं जनपद-कन्नौज समेत कुल कितने लघु व सीमान्त किसानों ने फसली ऋण लिया था उसमें से कितने किसानों का फसली ऋण माफ किया गया है ? क्या फसली ऋण माफी से कुछ किसान छूट गये हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक उनका ऋण माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत प्रदेश में दिनांक 8 फरवरी, 2018 तक 34.11 लाख किसानों का ऋण मोचन करते हुए उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किया गया है।

जनपद कुशीनगर एवं जनपद कन्नौज सहित प्रदेश के 66.07 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा लिये गये ऋण में से अब तक 34.11 लाख किसानों का ऋण मोचन किया जा चुका है। शेष किसानों के ऋण मोचन की कार्रवाई प्रगति पर है।

योजना क्रमिक है।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन औद्योगिक आस्थान, शिकोहाबाद का कार्य पूर्ण करने की जानकारी

30-श्री मनीष असीजा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन औद्योगिक आस्थान, शिकोहाबाद अपने तय भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष कितने प्रतिशत निर्मित हो चुका है ? क्या इस परियोजना को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? तय सीमा में कार्य पूर्ण न कर पाने की स्थिति में सरकार सम्बन्धित पक्षों की जवाब देही तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम गढ़वाल, फतेहपुर नसीरपुर तथा पटनाकर्खा की 167.578 हे0 (418.85 एकड़) निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा-4/16 तथा 6/17 की अधिसूचनायें क्रमशः दिनांक 24-12-2013 तथा 29-12-2014 को शासन द्वारा निर्गत/राजकीय गजट में प्रकाशित करायी गई थी। भूमि अधिग्रहण की यह परियोजना अधिसूचना के प्रकाशन की अन्तिम तिथि दिनांक 31-05-2017 को कालातीत हो गई है और अर्जन की कार्यवाही नहीं हो सकी, क्योंकि निर्धारित अवधि दिनांक 31-05-2017 के पूर्व तक अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के अभिनिर्णय घोषित नहीं हो सके और न ही प्रभावित भू-स्वामियों को प्रतिकर वितरित हो सका।

अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण होकर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को भूमि का कब्जा नहीं मिल सका है। इसलिये परियोजना को पूर्ण करने की समय-सीमा नहीं निर्धारित हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसागंज का कार्य पूर्ण करने की जानकारी

31-श्री मनीष असीजा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिरसागंज का कितना कार्य पूरा हो चुका है ? क्या उक्त परियोजना को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज में एक नई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपया 200.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को जारी की गयी, जिसके उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। वर्तमान तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 18 प्रतिशत के लगभग है।

प्रश्नगत संस्थान के भवन निर्माण कार्य को 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर को राजधानी दिल्ली से रेपिड रेल सेवा से जोड़ने हेतु मांग

32-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपद बुलन्दशहर के राजधानी दिल्ली से रेपिड रेल सेवा से जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय उपादेयता को ध्यान में रखकर सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

वि0स0 क्षेत्र महादेवा के वि0 ख0 कुदरहा के गाय घाट बाजार में नवीन उपमण्डी बनाने की जानकारी

33-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कुदरहा के गाय घाट बाजार में नवीन उपमण्डी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं।

किसी मण्डी की नई उपमण्डी घोषित कराने के लिये मा0 संचालक मण्डल द्वारा मानक निर्धारित हैं। निर्धारित मानक पूरे न होने के कारण विकास खण्ड कुदरहा के गाय घाट बाजार को उप मण्डी स्थल घोषित कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र महादेवा में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल निर्मित सड़कों की संख्या के सम्बन्ध में

34-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में वर्ष 2016-17 में सड़कें बनी हैं तथा वर्ष 2017-18 में मण्डी परिषद् की कौन-कौन सी सड़कें पिच कराने हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

वर्ष 2016-17 में जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में मण्डी परिषद् द्वारा नवीन सड़कें निर्मित नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में नवीन मार्गों के लिये बजट का प्राविधान नहीं किया गया था। तदनुसार वर्ष 2017-18 में कोई नवीन सम्पर्क मार्ग निर्मित नहीं किये गये हैं।

मण्डी परिषद् में सड़कों के डामरीकरण हेतु विधवाओं से प्रस्ताव लेने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र महादेवा में कन्या विवाह योजना में स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

35-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2017 से दिनांक 07-02-2018 तक जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में ऐसी कितनी दलित/बी0पी0एल0 सूची/गरीब कन्यायें हैं जिनको कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण विभाग में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना एवं मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कुल 30 गरीब परिवार के पुत्रियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा रु0 20,000/-की सहायता अनुदान तथा रु0 10,000/- की सामग्री प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कुम्हारी कला द्वारा निर्मित सामग्री की बिक्री हेतु स्टोर खोलने की मांग

36-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खादी भण्डार की भांति प्रत्येक जनपद में कुम्हारी कला द्वारा निर्मित सामग्री (मिट्टी के बर्तन/मिट्टी की मूर्तियां) की बिक्री हेतु स्टोर खोलने की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

नहीं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के तर्ज पर कार्य नहीं करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग अपने भण्डारों का संचालन भी करता है, जबकि सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भण्डारों के स्थान पर विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा लघु उद्योगों से संबंधित उत्पादों के विपणन हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत विपणन सहायता प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के माध्यम से प्रदेश में निर्मित उत्पाद के विपणन की व्यवस्था कराता है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रजापति समाज के लिये कुम्हारी कला बनाने हेतु बिना ब्याज के लेन-देन की योजना विषयक

37-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुम्हार/प्रजापति समाज के लिए कुम्हारी कला (मिट्टी के बर्तन/मिट्टी की मूर्तियां) बनाने हेतु बिना ब्याज के ऋण दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

हां

कुम्हारी कला (मिट्टी के बर्तन/मिट्टी की मूर्तियां) बनाने हेतु कुम्हार/प्रजापति समाज के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ब्याज रहित ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

विभाग द्वारा मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना कराने हेतु उद्यमियों को रु0 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष को छोड़कर अन्य आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग) को बैंकों के माध्यम से ब्याजरहित ऋण दिये जाने का प्राविधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग में कुम्हार/प्रजापति समाज के लोग भी आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा निगम द्वारा संचालित किये जा रहे शोरूम बन्द कराने की मांग

38-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या हथकरघा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा संचालित कितने शोरूम स्वयं की इमारत में है और कितने किराये की इमारत में है व किराये की दुकानों पर चलाये जा रहे शोरूम का किरायेदारी का अनुबन्ध का नवीनीकरण कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने शोरूम घाटे में है और कितने फायदे में चल रहे हैं और सरकार यह भी बतायेगी कि जो शोरूम घाटे में चल रहे हैं उनको बन्द करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

1-हथकरघा निगम की स्वयं की इमारत में संचालित बिक्री केन्द्रों की संख्या-20

2-किराये की इमारत में संचालित बिक्री केन्द्रों की संख्या-49

(अ) सरकारी संस्थाओं (नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत आदि) से कराये पर आवंटित कराये गये बिक्री केन्द्रों की संख्या 23

(ब) निजी व्यक्तियों से अनुबन्ध के आधार पर किराये पर लिये गये बिक्री केन्द्रों की संख्या 26 निजी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये 26 बिक्री केन्द्रों में से केवल 03 बिक्री केन्द्रों का अनुबन्ध नवीनीकरण सम्पन्न हुआ है। शेष 23 बिक्री केन्द्रों के अनुबन्ध नवीनीकरण के सम्बन्ध में भवन स्वामियों एवं निगम के मध्य माननीय न्यायालयों में विधिक वाद लम्बित होने एवं किराये की दरों पर सहमति न बन पाने आदि के कारण अनुबन्ध नवीनीकरण की कार्रवाई लम्बित है।

हानि में चल रहे बिक्री केन्द्र :-

1-कुल बिक्री केन्द्रों की संख्या-69

2-मामूली हानि (ATPAR) वाले बिक्री केन्द्रों की संख्या-20

3-हानि पर चल रहे बिक्री केन्द्रों की संख्या-36

बिक्री केन्द्रों को बन्द करने के सम्बन्ध में :-

निगम के अलाभकारी/विवादित बिक्री केन्द्रों को बन्द किये जाने हेतु निदेशक मण्डल की दिनांक 06-12-2017 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 फरवरी, 2018 के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त बिक्री केन्द्रों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यागों के कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिये वर्कशाप बनाने विषयक

39-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिव्यांगों हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए वर्कशाप सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु प्रचलित नियमावली, 2016 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु पात्र लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी रुपये 8000/-का वित्तीय अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

यूनीहोम-3 सेक्टर-113, नोएडा में यूनीटेक कम्पनी नोएडा से वर्ष 2012 में आवंटित फ्लैट के कब्जे के सम्बन्ध में

40-श्री संजय गर्ग-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनीहोम-3, सेक्टर-113, नोएडा में यूनीटेक कम्पनी नोएडा से वर्ष 2012 में फ्लैट आवंटन हेतु कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तथा उक्त हेतु किश्तें भी जमा की हैं, क्या उन्हें उक्त फ्लैट का कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो

कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आवंटियों को उनका कब्जा दिलायेगी अथवा जमा धनराशि वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड संख्या-जी0एच0-01, सेक्टर-113, नोएडा में मै0 यूनीटेक लि0 के पक्ष में आवंटित भू-खण्ड पर आवंटी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, जिस पर कारण फ्लैट क्रेताओं के पक्ष में उप पट्टा प्रलेख का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है।

बायर्स/फ्लैट क्रेताओं की समस्या के दृष्टिगत शासन द्वारा मा0 मंत्रि समूह का गठन किया गया है। मा0 मंत्री समूह द्वारा जनपद में बायर्स/फ्लैट क्रेताओं, बिल्डर्स तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बायर्स की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न बैठकें की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मछुआ समाज की उप जाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद आदि को अनुसूचित जाति में शामिल करने विषयक

41-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मछुआ समाज की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, मांझी, मछुआ आदि को अनुसूचित जाति में शामिल कर उनको अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, मांझी, मछुआ आदि को अनुसूचित जाति के रूप में शासनादेश संख्या-234/2016/297 सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक 22-12-2016 द्वारा परिभाषित किया गया था, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 24-01-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-14/2017/33रिट/26-3-2017-3(15)/2007, दिनांक 27-01-2017 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

प्रदेश में किसानों को सस्ती दर पर बीच उपलब्ध कराने एवं जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र में बीज विकास निगम की स्थापना कराये जाने की मांग

42-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता वाले बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत बीज विकास निगम की एक शाखा जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण निदेशक मण्डल की 55वीं बैठक में निगम के अवशेष बचे परियोजना कार्यालयों के सविलयन का निर्णय लिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की शाखा खोला जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 2017-18 पर कुल स्वीकृत धनराशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी के सम्बन्ध में

43-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि में कितना व्यय किया गया है ? क्या सरकार व्यय की गयी धनराशि के कार्य का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इण्टरवेंशन के अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह मार्च में रु0 51.53 लाख व वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 14.47 लाख आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु0 66.00 लाख व्यय किया जा चुका है। उक्त धनराशि से विकास खण्ड कर्वी के राजस्व ग्राम अकबरपुर एवं परसौंजा में क्रमशः भवानीगंज तालाब एवं सुन्दरिया तालाब का पुनर्विकास का कार्य कराया गया।

उद्यान विभाग की योजना ''पर ड्राप मोर क्राप'' माइक्रो इरीगेशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 151.76 लाख आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 78.84 लाख व्यय किया जा चुका है। उक्त व्यय की गयी धनराशि से अब तक 97 हे0 में ड्रिप एवं 633 हे0 में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की सुविधा व एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर कृषकों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों की जानकारी से लाभान्वित किया गया।

परती भूमि विकास विभाग द्वारा वाटरशेड योजना के अन्तर्गत रु0 3.50 करोड़ आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु0 69.84 लाख व्यय किया जा चुका है। उक्त व्यय की गयी धनराशि से 66 स्वयं सहायता समूहों का गठन करके 520 लाभार्थी लाभान्वित किये गये तथा 160 हे0 मृदा संरक्षण का कार्य कराया गया। 2806 मीटर के 21 कच्चे चेक डैम व 02 पक्के चेक डैम तथा 20 पक्के ड्रापस्पिलवे का निर्माण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[03 शुक्रवार के अता0 प्र0 स0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

45-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[03 शुक्रवार के अता0 प्र0 स0-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर आउटसोर्सिंग पर तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर आउटसोर्सिंग पर तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों के 5 माह का (मार्च 2017 से जुलाई 2017) तक का बकाया भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग

47-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की उपज में बढ़ती हुई लागत के मद्देनजर क्या सरकार गरीब/दलित किसानों को खेती करने के लिए अलग से किसान क्रेडिट कार्ड निःशुल्क ब्याज दर पर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है।

जनपद गाजीपुर के वि0 स0 क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत इजरी से ढड़नी नगर टूटी पटरी की मरम्मत कराने की मांग

48-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत इजरी से ढड़नी नहर की पटरी क्षतिग्रस्त होने से जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की पटरी का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग कटान प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है तथा उप निदेशक (निर्माण) की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 27-02-2018 के अनुसार क्षतिग्रस्त है।

शासन द्वारा निर्गत ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग'' अनुरक्षण नीति दिनांक 22 नवम्बर, 2013 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित प्रश्न]

प्रदेश में शादी अनुदान योजना विषयक

(1) श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना प्रदेश में बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थान पर कोई नई योजना लाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:23] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनायें पढ़ दूं उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बजट पर विचार रखेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी

पहली सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर जनपद एटा के तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रितेश पाण्डेय लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में होम्योपैथी शिक्षा में फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुरसराय मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नाहिद हसन जनपद शामली के ब्लाक ऊन के पी0डब्ल्यू0डी0 के मुख्य मार्ग के समीप स्थित नाली को रोकने के कारण ग्राम में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव जनपद चन्दौली के धानापुर विकास खण्ड गुरैनी पम्प कैनाल पर हो रहे गंगा कटान न रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश जनपद आगरा के सेवला सरायं से सरस्वती विहार के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग जनपद आगरा के इन्द्रपुरी कालोनी के जर्जर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती सुनीता जनपद गाजीपुर के

जमानिया में मुंसिफ कोर्ट निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवी सूचना श्री दिनेश चौधरी जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में शहीद स्मारक सेनापुर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में जर्जर बिजली के तारों के स्थान पर केबिल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री दलवीर सिंह जनपद अलीगढ़ के तहसील मुख्यालय गभाना को खैर से जोड़े जाने वाले कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई कानपुर स्थित राजकीय कैंसर संस्थान में पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री नरेश सैनी जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र के रायपुर में राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर जनपद सहारनपुर के गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक फोर लेन हाई-वे एवं अण्डरपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ में शिक्षकों का स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जनपद सीतापुर में चयनित आई स्पर्श स्मार्ट योजना की शेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत इन्दिरा कालोनी व बसन्त विहार के तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, अटठारहवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव खुड्डा से श्मशान घाट जाने का रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया जनपद महोबा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज चरखारी में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी ?-

1-श्री विपिन कुमार डेविड,

2-श्री पल्टूराम,

3-श्री ओमकार सिंह यादव,

4-श्री अबरार अहमद,

5-श्री पारसनाथ यादव,

6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

7-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

8-श्री जितेन्द्र वर्मा,

9-श्रीमती सरिता भदौरिया,

10-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस',

11-डॉ0 विमलेश पासवान,

12-श्री प्रभात कुमार वर्मा,

13-श्री संजय सिंह गंगवार,

14-श्री मनोज कुमार पारस,

15-श्री जटा शंकर त्रिपाठी,

16-श्री रोशन लाल वर्मा,

17-श्री सुभाष पासी,

18-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज,

19-श्री राहुल प्रकाश,

20-श्री संगम लाल गुप्ता,

21-श्री राम नरेश रावत,

22-श्री संजय गर्ग तथा

23-श्री कुलदीप सिंह सेंगर।

(सदन की सहमति से संलग्न सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद एटा के तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज के तहसील अलीगंज, जनपद एटा के तहसील मुख्यालय पर कोई मण्डी नहीं है। जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिये दूर-दराज जाना पड़ता है। सबसे नजदीक एटा मुख्यालय मण्डी की दूरी लगभग 70 किमी0 है। तहसील मुख्यालय अलीगंज में मण्डी की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में होम्योपैथी शिक्षा में फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, प्रदेश के बाहर से फर्जी शिक्षा अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से प्रवक्ता रीडर, प्रोफेसर पद पर चयनित/संस्तुत/नियुक्त आयुष शिक्षकों का शिक्षा के प्रयोजन हेतु शून्य योगदान है। प्रारम्भिक जांच में कालेजों, प्राचार्य व प्रबन्धक का अता-पता नहीं मिला। ऐसे आयुष शिक्षकों को शासन के आयुष अनुभाग-2 का संरक्षण प्राप्त है फलतः मेरिट पर जांच

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं हो पा रही है। पंचायती राज विभाग के जिला पंचायत के अनुश्रवण प्रकोष्ठ में तैनात तदर्थ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी जो गैर संवर्गीय, अवैध नियुक्तिधारी है। नियम-नियमावली व संविधान के विपरीत कार्यवाहक संयुक्त निदेशक, होम्योपैथी-निदेशालय बने हुये हैं न व्यक्ति पोषक, नियम-नियमावली, संविधान विपरीत नियमावली संशोधन अधिसूचना दिनांक 21-09-2016 के बल पर अपर निदेशक व निदेशक बनने की ताक में है। विसंगतिपूर्ण/विवादित नियमावली संशोधन अधिसूचना दिनांक 21-09-2016 की वापसी/निरस्तीकरण की मांग के प्रति भी शासन का आयुष अनुभाग-2 अगंभीर एवं उदासीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये मामले में लोकहित में त्वरित-प्रभारी कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुरसरांय मुख्य नहर के सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पारीक्षा बांध से 52 किमी0 लम्बी गुरसरांय मुख्य नहर निकलती है। जिस नहर/सहायक नहरें/माइनरों के माध्यम से क्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन 20 वर्षों से टेलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सिंचाई के अभाव में हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि खाली पड़ी है, जबकि गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा/धसान नदियों में बराबर पानी बह रहा है। गुरसरांय मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पानी की क्षमता बढ़ाया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-शामली के ब्लाक ऊन के पी0डब्ल्यू0डी0 के मुख्य मार्ग के समीप स्थित नाली को रोकने के कारण ग्राम में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्राम मछरौली ब्लाक ऊन जनपद शामली के मुख्य पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग के समीप स्थित नाली को ग्राम के मांगेराम पुत्र चन्दर ने रोक दिया है जिससे मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ग्राम के मुख्य मार्ग पर लगभग 03 फुट जलभराव हो गया है। ग्राम का जूनियर हाई स्कूल भी जलभराव के कारण बन्द हो गया है। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की सड़क को जलभराव से बचाने एवं नाली पर ग्रामवासी का अवैध कब्जा हटवाने की अति आवश्यक है। उपरोक्त समस्या से ग्राम का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त जन समस्या की और शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के धानापुर विकास खण्ड गुरैनी पम्प कैनाल पर हो रहे गंगा-कटान न रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत गुरैनी पम्प कैनाल गंगा के कटान से पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है और एक पम्प गंगा नदी में बह गया है। मात्र एक पम्प कैनाल चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के किसान परेशान है और गंगा के कटान से हो रहे नुकसान होने के कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है। लगभग 20 गांवों के किसानों की सिंचाई इसी कैनाल से होती है इन किसानों की सिंचाई करने के लिये और कोई दूसरा पम्प कैनाल नहीं है। उक्त कैनाल पर हजारों की संख्या में किसान 20 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन किया है परन्तु आज तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जिससे आये दिन किसानों की स्थिति खराब होती चली जा रही है। यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय जनता से जुड़ा हुआ है। किसान आन्दोलन करने के लिये मजबूर है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा के सेवला सरायं सरस्वती विहार के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 87-आगरा छावनी, जनपद आगरा में ग्वालियर रोड सेवला सरायं से सरस्वती विहार में डॉ0 अनिल गुप्ता के निवास तक सड़क एक दम कच्ची है। जगह-जगह गड्ढे है एवं कीचड़ भरा हुआ है। जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। इस कारण क्षेत्रीय जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। जनहित में इस मार्ग का बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा के इन्द्रपुरी कालोनी के जर्जर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, जनपद आगरा अन्तर्गत न्यू आगरा की इन्द्रपुरी कालोनी की आन्तरिक सड़कें एवं नालियां अत्यधिक जर्जर हालत में होने के कारण जलभराव एवं आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कालोनी के मार्ग अत्यधिक जर्जर हालत में है जिसके कारण आये दिन लोग चोटिल होते रहते है। जलनिकासी हेतु नालियां टूटी होने के कारण जलभराव की समस्या बनी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहती है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर पत्राचार करने के बाद भी समस्या का निराकरण न होने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन्द्रपुरी कालोनी की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-गाजीपुर के जमनिया में मुन्सिफ कोर्ट निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुनीता-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के 379-विधान सभा क्षेत्र जमानियां में मुन्सिफ कोर्ट निर्माण के अन्तर्गत मुन्सिफ कोर्ट की अत्यन्त आवश्यकता है जबकि इसके बाद के बने तहसीलों में मुन्सिफ कोर्ट बन चुके हैं। मुख्यालय से ज्यादा अधिक दूरी होने के कारण आम जनमानस को कोर्ट के कार्यों हेतु काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा मुन्सिफ कोर्ट बन जाने से छोटे-छोटे मुकदमों का निस्तारण हो सकेगा। जो जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में शहीद स्मारक सेनापुर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372-केराकत में सेनापुर गांव में अंग्रेज हुकूमत में आजादी में भाग ले रहे 23 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिये तब से यह गांव शहीद स्मारक सेनापुर गांव के नाम से जाना जाता है। जबकि यहां पर उन शहीदों की याद में केवल शिलापट्ट ही बनाया गया है। इस जगह को देखने के लिये दूर-दूर से लोग आते हैं। शहीदों की इस वीर भूमि को यादगार बनाने के लिये सौन्दर्यीकरण कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में जर्जर बिजली के तारों के स्थान पर केबिल लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र इटवा जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड इटवा तहसील मुख्यालय है। यहां पर बिजली के तारों का जाल है जो जर्जर होने के कारण आये दिन टूटते रहते हैं जिससे दुर्घटनायें भी होती रहती है। जनहित में इन जर्जर तारों के स्थान पर केबिल लगवाया जाना आवश्यक है। यहां के निवासियों द्वारा इसकी जिला स्तर पर शिकायत करके मांग भी की गयी परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है जिससे जर्जर तारों के टूटने से हो रही घटनाओं एवं ठप्प विद्युत आपूर्ति से जनमानस में आक्रोश है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इटवा में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत शामिल करते हुये जर्जर विद्युत तारों के स्थान पर केबिल लगवाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-अलीगढ़ के तहसील मुख्यालय गभाना की खैर से जोड़े जाने वाले कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में तहसील मुख्यालय गभाना को, तहसील मुख्यालय खैर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग एन0एच0-91 से खैर मार्ग एन0एच0-91 से वीरपुरा तक (लगभग 3 किमी) 3.70 मीटर चौड़ा है। शेष लगभग 11 किमी0 का मार्ग 7 मीटर चौड़ा है। यह मार्ग दो तहसीलों से जोड़ने के साथ-साथ एन0एच0-91 को खैर पलवल मार्ग से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। आंशिक हिस्से की चौड़ाई कम होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जनहित में आंशिक भाग को भी 7 मीटर चौड़ा कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे पूरा लगभग 14 किमी0 का मार्ग एक जैसी चौड़ाई का हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आंशिक भाग के चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर स्थित राजकीय कैंसर संस्थान में पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। कानपुर स्थित एक मात्र राजकीय कैंसर संस्थान में पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त करने के सन्दर्भ में है। मैं सदन का ध्यान कानपुर स्थित जे0जे0 कैंसर संस्थान जो कानपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध एक मात्र राजकीय कैंसर हास्पिटल है, उसमें आज भी पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त नहीं है। अस्पताल में एक कार्यपालक निदेशक जो कैंसर के डाक्टर के बजाय पैथालाजिस्ट है के भरोसे चल रहा है। जो मरीजों के हित में नहीं है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त संस्थान में पूर्णकालिक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति करने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र के रायपुर में राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रायपुर जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। ग्राम रायपुर के आस-पास कई गांव व छोटे मजरे पड़ते हैं। इस क्षेत्र के आस-पास 5 किमी0 तक कोई राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है। शिक्षा आत्मविश्वास विकसित करती है और अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है। राजकीय बालिका

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इण्टरमीडिएट कालेज न होने के कारण इस क्षेत्र के बालिकाओं को काफी दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। यह पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज न होने से अभिभावकों को बालिकाओं की आगे की शिक्षा मुहैया कराने में काफी दिक्कते होती हैं। ऐसे में क्षेत्र के अधिकाधिक छात्राओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। अग्रतर उच्च शिक्षा पाने हेतु यहां पर राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज का स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर के गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक फोर लेन हाई-वे एवं अण्डर-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक वाया देवबन्द में बन रहे फोर लेन हाई-वे में आवश्यकतानुसार अण्डरपास पी0यू0सी0 का जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त फोर लेन सड़क का निर्माण आगामी वर्षों में बढ़ रहे ट्रैफिक के हिसाब से किया जा रहा है। कुल 52 कि0मी0 लम्बे फोर लेन निर्माण में 752.88 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उक्त हाई-वे के ग्राम-साधारण सिर चौराहे पर सैकड़ों गांवों के गन्ना किसानों को गन्ना भी गांगनौली चीनी मिल को गन्ना ले जाने और आम आदमी, किसानों, विद्यार्थियों को रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग है। किन्तु अण्डर पास न बनाये जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। उक्त हाई-वे के नागल गांव में श्मशानघाट को जाने के लिये भी अण्डरपास नहीं बनाया जा रहा है। एक तरफ उपशा ने मनमाने ढंग से नागल के सीड़की की तरफ छोटे-बड़े आठ अण्डरपास लगभग 3 कि0मी0 में बना दिये वहीं दूसरी ओर देवबन्द तक 18 कि0मी0 में एक भी अण्डर पास मार्ग नहीं दिया गया जो कि सरासर गलत है। ग्राम-खजुरवाला में नियम विरुद्ध अण्डरपास बनाया गया है। ऐसे में ग्राम-साधारणसिर चौराहे पर बड़ा अण्डरपास बनाये जाने तथा नागल से देवबन्द की बीच में आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण कराकर अण्डरपास बनाये जाने की कार्रवाई किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय, जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद-सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक वाया देवबन्द में बन रहे फोर लेन हाई-वे में ग्राम साधारणसिर चौराहे पर तथा नागल से देवबन्द के बीच में आवश्यकतानुसार अण्डरपास का निर्माण जनहित में कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

अमीनाबाद इण्टर कालेज लखनऊ में शिक्षकों का स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीतराम वर्मा-

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज में वर्ष 2000 में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद पर कतिपय शिक्षक नियुक्त किये गये हैं। इन शिक्षकों का कार्य एवं व्यवहार बहुत अच्छा है तथा इनकी दीर्घकालीन सेवाओं के दृष्टिगत इनका स्थायीकरण/विनियमितीकरण किया

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाना आवश्यक है। इन शिक्षकों को नियुक्ति नगर निगम लखनऊ द्वारा की गई थी तथा इनके वेतन का भुगतान नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जाता है। अमीनाबाद इण्टर कालेज पर वेतन वितरण अधिनियम, 1971 लागू नहीं है।

मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बिन्दु पर वक्तव्य की मांग करता हूं कि नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज में वेतन वितरण अधिनियम, 1971 लागू न होने के कारण नगर निगम द्वारा नियुक्त शिक्षकों (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक) का स्थायीकरण/विनियमितीकरण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा अथवा नगर निगम लखनऊ (नगर विकास विभाग) द्वारा किया जायेगा।]

जनपद-सीतापुर में चयनित आई स्पर्श स्मार्ट योजना की शेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में चयनित आई स्पर्श स्मार्ट योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम नीरा नगर, खपूरा, पोखरा कलां में आवंटित 50 प्रतिशत धनराशि का कार्य जैसे गेट, बाउण्ड्रीवाल, इण्टरलॉकिंग, नाली, पुस्तकालय आदि का आधा काम पूर्ण होकर शेष कार्य लम्बित पड़ा हुआ है। अवशेष राशि निर्गत न होने के कारण जो कार्य आधे कराये गये है उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। अवशेष राशि का धन आवंटन किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अवशेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत इन्दिरा कालोनी व बसन्त विहार के तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर सदर के इन्दिरा कालोनी व बसन्त बिहार के तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है जिससे उनके संरक्षण हेतु तालाब की बाउण्ड्री एवं पथ-वे बनाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव-खुड्डा से श्मशान घाट जाने का रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुरकाजी के गांव खुड्डा में भूमिया खेड़ा मन्दिर से श्मशान घाट तक का रास्ता जिसकी लम्बाई लगभग 600 मी0 है उस रास्ते का निर्माण जनहित में आवश्यक है क्योंकि रास्ता न होने के कारण शवों को ले जाने में काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-महोबा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज चरखारी में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, चरखारी, जनपद महोबा में विभिन्न विषयों के 13 अध्यापक, 1 क्लर्क एवं 6 चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है। विद्यालय में लगभग 2000 छात्रायें पढ़ने आती है। शिक्षकों एवं सहायक स्टाफ की कमी के कारण छात्राओं को बहुत असुविधा होती है। इस क्षेत्र में कोई अन्य बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्र की छात्रायें इसी विद्यालय में पढ़ने आती है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में सभी कक्षायें संचालित नहीं हो पाती है। छात्राओं को अच्छी शिक्षा के लिये दूर जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है तथा जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही है। कालेज में स्टाफ की कमी पूरा करना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गयी सड़क यथा रूदौली मार्ग से डेहवा मार्ग एन0एच0-28 से गुलचप्पा सम्पर्क मार्ग सहित आधे दर्जन मार्ग रूदौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पड़े हुए इन मार्गों पर आने-जाने में कठिनाई हो रही है इन मार्गों की तत्काल मरम्मत किये जाने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है। रूदौली क्षेत्र के पुनीकापुरवा, खरगीकापुरवा, चैनकापुरवा व सुनवा की बस्तियों में सी0सी0 मार्ग व इण्टर लॉकिंग का कार्य भी जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत कराये गये हैं जो अत्यन्त घटिया है। चैनकापुरवा में वर्तमान समय में काम चल रहा है जिसकी गुणवत्ता निम्नकोटि की है। मण्डी परिषद् की अधिकारियों से मेरे द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया। रूदौली विधान सभा क्षेत्र में निर्मित मण्डी परिषद् की सड़कों का मरम्मत कराये जाने तथा चैनकापुरवा, मजरे सैदपुर के कार्य की गुणवत्ता को ठीक कराये जाने की तत्काल कार्रवाई कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय मैंने उठाया था आपने कहा था कि बाद में अवसर देंगे। मान्यवर, यह सुल्तानपुर की घटना है।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए बाद में तय हो गया था कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी वाला कार्यक्रम हो जाये।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सुन लें, दो मिनट लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

उस पर उत्तर भी दिला देंगे यह तय हो गया था, माननीय संजय जी से तय हो गया था आपसे भी कि माननीय मुख्य मंत्री जी का हो जाये उसके बाद विधिवत् उठा लेंगे फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर भी दे देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

अब बजट पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

[12:24] वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा में हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2018-19 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस पर सामान्य चर्चा चल रही है और मैंने इन बजट प्रस्तावों पर जो चर्चा यहॉ पर अब तक हुई है उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण को बड़ी तन्मयता के साथ सुना। मुझे लगता है कि पहली बार इस सदन की तीन दिन की छुट्टी करवाकर अच्छी भावना के साथ उन्होंने तैयारी करने का प्रयास किया था, लेकिन वह आधी-अधूरी रह गयी। जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं वह सत्य से परे हैं और वास्तविकता से कोसों दूर हैं। हर व्यक्ति जानता है कि हमारी सरकार ने 19 मार्च को शपथ ग्रहण किया था और वर्ष 2017-18 का जो बजट प्रस्तुत हुआ था इस सदन में वह जुलाई में हुआ था। उस सबके बावजूद एक वर्ष के अन्दर, एक वर्ष से भी कम समय में लगभग आठ-नौ महीने के दौरान जो कार्य बजट पारित होने के बाद जिस तत्परता के साथ सरकार आने के बाद प्रदेश के अन्दर हुआ है, उसकी जो प्रगति है वह काफी सन्तोषजनक है। हम लोगों ने नौ महीने के दौरान जो कार्य किया है वह पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार को एक वर्ष का पूरा कार्यकाल बजट प्रस्तुत होने के बाद मिलने के बावजूद उन्होंने जो धनराशि विकास के लिए या गरीब कल्याण की जो योजनायें थीं, विभिन्न प्रकार की शासन की जो योजनायें होती हैं, विभागों से सम्बन्धित जो मद होते हैं, अनुदान होते हैं उन सब में खर्च करने के बजाय पी0एल0ए0 में ज्यादा डालने की व्यवस्था होती थी, बन्दरबाट करने की गलत परम्पराओं की शुरूआत हो गयी थी। पहली बार हुआ है कि बजट समय से पहले से प्रस्तुत हुआ और हम लोगों ने यही आग्रह किया था कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में मार्च के अन्दर ही बजट और उसकी अनुदान मांगों को पारित करवाकर के विभिन्न विभागों को बजट का आवंटन हो जाये और मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में जो बजट पिछली बार में खर्च हुआ था, अगर उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो मात्र नौ-दस महीने के दौरान सरकार ने बजट पारित होने के बाद जो कार्य किया है उसमें आवंटन के साथ-साथ खर्च की जो राशि है वह पिछले वर्ष से गत वर्षों की तुलना में चौदह फीसदी ज्यादा है (सतापक्ष की ओर मेजों की थपथपाहट)। प्रदेश के अनुसार ही हम लोगों ने बजट का स्वरूप भी रखा। हमारी सरकार जब आयी थी तब भी

† दिनांक 13-3-18 की कार्यवाही से।

मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, इसका बजट भी इसी हिसाब से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट दो लाख करोड़, ढाई लाख करोड़ का नहीं हो सकता। अगर 22 करोड़ जनता को समग्र विकास की ओर अग्रसर करना है तो हमें विकास की योजनाओं के साथ-साथ गरीब कल्याण की उन योजनाओं को उसी त्वरित गति से आगे बढ़ाना होगा और गत वर्ष हम लोगों ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था वह 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें जो धनराशि खर्च हुयी है, जो विभिन्न विभागों के मद हैं इस 17-18 मार्च तक कृषि में जो धनराशि खर्च हुयी है वह 97. 53 प्रतिशत, पंचायती राज में 77.96 प्रतिशत, ऊर्जा में 93.99 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 63. 36 प्रतिशत, गृह विभाग में 99.54 प्रतिशत, ग्राम्य विकास में 74.18 प्रतिशत, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण में 78.88 प्रतिशत, खाद्य एवं रसद विभाग में 100 फीसदी धनराशि खर्च हो चुकी है और वह विभिन्न मदों में जारी भी हो चुकी है। वन विभाग में 98.13 फीसदी, आयुष में 92.43 प्रतिशत, पशुपालन में 85.68 प्रतिशत, महिला कल्याण में 99.71 प्रतिशत । यह विभिन्न विभागों की जो धनराशि विभिन्न मदों में सरकार ने जो जारी की है और मेरा विश्वास है कि 31 मार्च तक पहली बार हो रहा है कि जब सरकार ने यह व्यवस्था दे दी है कि कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 में जमा नहीं होगी और शतप्रतिशत जिन कार्यो के लिये आवंटित हुई है वहॉ पर खर्च होगी नहीं तो वापस आ जायेगी, हम उसे लैप्स मान लेंगे । शासन की कार्य पद्वति कैसी होनी चाहिये, यह हम लोगों ने इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और इसलिये मैं कह सकता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष थोड़ा आकंड़ो को सही कर लेते और सही तथ्यों को सदन में रखते तो मुझे लगता है कि उनकी भी गरिमा बढ़ती और लोग उनके भाषण को विश्वसनीय भी मानते । लेकिन मुझे लगता है कि जो आकंड़े दिये गये हैं इन सभी आकंड़ों को अगर एक बार वह पुनः देख लेंगे तो अच्छा होगा । वैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविन्द जी बोलते ज्यादा हैं लेकिन करते कम हैं और इसलिये उनकी जो बोलने की आदत है, कभी-कभी उनको इन आदतों के कारण आइना दिखाना पड़ता है कि वास्तविक और सही तथ्य क्या हैं । इसलिये मैनें सदन के समक्ष यह बॉतें रखी हैं । सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय अपने आय-व्यय को प्रदेश की जनता के सामने रखते समय सही बॉतों का ध्यान रखा है और खासतौर पर हमें प्रसन्न्ता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वित्तीय अनुशासन को बनाये रखते हुये अपनी सभी कार्य योजनायें बनाई हैं । हम अपने स्वार्थो के लिये उत्तर प्रदेश को बैंकरप्ट स्टेट नहीं बना सकते और इसलिये एफ0आर0वी0एन0 की जो सीमा उत्तर प्रदेश की है उसके अंदर ही हम लोगों ने अपने सभी आय व्यय को लिया है अगर विकास की योजनाओं को ऋण की आवश्यकता पड़ी है तो हम लोगों ने उस एक्ट का पूरा पालन किया है और उस अनुशासन को बनाये रखते हुये ही इस कार्य को किया है । हमारी जगह तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96, 29.8 प्रतिशत जो हमारी एफ0आर0वी0एन0 ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश को लोन लेने की हमारी जो सीमा है वह भी 20.5 प्रतिशत के अंदर ही है, उससे काफी नीचे अभी भी हम लोग हैं । तो माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कहना कि हम लोगों ने भारी ऋण लिया है हम लोग विकास की योजनाओं को बाधित कर दिये हैं मुझे लगता है कि यह कपोल कल्पना मात्र है । और दूसरा बहुत सारी बातों पर उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार ने कोई भी योजना अपने स्तर पर, पहले जो आरोप लगाया गया कि विभिन्न विभागों के बजट कम कर दिये गये हैं। मुझे लगता है कि यह भी सच नहीं है। हमारे जो

फोकस एरियाज थे, उनको ले करके हमने पर्याप्त धनराशि दी है और मैं उसकी तरफ अगर बताऊँ तो हम लोगों ने पहले ही इस बात को कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत और मजहब को संतुष्ट करने के लिये नहीं आयी है, बल्कि हम लोग प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करने के लिये आये हैं (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) और इसलिये योजना का जो केन्द्र बिन्दु है, वह प्रदेश का किसान है, प्रदेश का नौजवान है, प्रदेश की बहन-बेटियॉं हैं, प्रदेश का हर तबका है और इसलिये विकास के भी फोकस प्वाइंट हम लोगों ने तय किये हैं। फोकस सेक्टर के अनुसार हम लोगों ने धनराशि भी आवंटित की है। अगर हम विद्युत विभाग की तरफ देखें, मुझे लगता है कि बिजली से इन लोगों को ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो यह लोग बिजली नहीं देते थे, प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को इन्होंने विद्युत से वंचित करके रखा था। हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के अन्दर विद्युत वितरण की एक समान व्यवस्था प्रारम्भ की, इस दौरान प्रदेश के अन्दर, जहॉं जिला मुख्यालयों पर, अगर वहॉं का फीडर विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम है तो हम लोगों ने वहॉं पर 23 से 24 घण्टे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों और बुन्देलखण्ड में 19 से 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति और शेष प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति करने की जो वचन-बद्धता दोहराई थी, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अपनी उस वचन-बद्धता पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति कर रही है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अन्दर लगभग 62 हजार मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सौभाग्य योजना कि हर गरीब परिवार को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन मिले। विद्युत विभाग ने अब तक इसके लिये 32 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य भी पूरे प्रदेश में किया है। लोकतंत्र में शासन की कार्य-पद्धति, पारदर्शी तरीके से दिखनी चाहिये, उसमें सुचिता होनी चाहिये और हमारी सरकार ने इस कार्य को किया है। हम लोगों ने कैम्प लगा करके विद्युत कनेक्शन बॉंटे हैं और कैम्प लगा करके एक व्यवस्था दे दी गयी है, सप्ताह में अब हर फीडर में, सब स्टेशन में भी इस प्रकार की कैम्प की व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों ने सभी माननीय जन प्रतिनिधियों को इस बारे में कहा और इसलिये अभी प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है, 62 हजार से अधिक मजरें अभी भी ऐसे हैं, जिनमें विद्युत नहीं पहुँची है। हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है और इसलिये जो 2018-19 का हमारा बजट है इसमें हम लोगों ने 29,883.05 करोड़ रूपये की व्यवस्था विद्युत विभाग के लिये की है और इसमें खास तौर पर जो पिछले गत वर्ष की तुलना में 54 फीसदी अधिक है, यानी 54 फीसदी अतिरिक्त हम बजट दे रहे हैं, बढ़ोत्तरी कर रहे हैं तब भी आरोप लग रहा है कि हमने कटौती की है। लोक निर्माण विभाग में 22 प्रतिशत अधिक हम लोगों ने बजट बढ़ाया है। सिंचाई की परियोजनाओं में, सिंचाई की ढेर सारी ऐसी योजनायें हैं, जो योजनायें वर्षों से लम्बित पड़ी हुयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार इस बात को कहते हैं कि डब्लिंग फार्मर्स इन्कम के जिन महत्वपूर्ण मुदों को प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, उसमें सिंचाई एक कम्पोनेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार सहयोग करना चाहती है और इसलिये हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में 54 फीसदी की बढ़ोत्तरी सिंचाई के मद में भी किया है कि जिससे हर खेत तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। कृषि और उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों पर जिसमें कृषि है, उद्यान है, खाद्य

प्रसंस्करण है, पशुधन है, डेयरी विकास है, सहकारिता है इन सब पर हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस बजट में की है। ग्राम्य विकास के लिए गत वर्ष की तुलना में 28.80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है तो पंचायती राज में भी गत वर्ष की तुलना में 16 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में 17.30 प्रतिशत और नगर विकास में भी हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अन्दर 99 सिटी का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है और उन 99 सिटी में से 10 सिटी अकेले उत्तर प्रदेश की हैं जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में हम विकसित करेंगे और वह कार्ययोजना हमारी लागू हो चुकी है। शिक्षा विभाग में हम लोगों ने 68 हजार 263.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए भी गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हम लोगों ने की है। अनुसूचित जाति का जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन है इसमें गत वर्ष की तुलना में हम लोगों ने 1824 करोड़ रुपए अधिक इस मद में दिये हैं जिसमें उन छात्रों को जो विशेष प्रावधान उनकी स्कालरशिप इत्यादि के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 73.83 करोड़ रुपए अधिक धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। यानी कि कटौती कहीं नहीं हुई है, हॉ कटौती वहॉ जरूर हुई होगी जिसमें सरकार का धन कुछ चन्द लोगों की जेब में चला जाता था और वह लोग कौन हैं इसे हर व्यक्ति जानता है। उस मद में कटौती जरूर की है और उस पर प्रहार करने में हम लोगों ने कोई संकोच भी नहीं किया है। क्योंकि करप्शन और क्राइम दोनों पर हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत् कार्य करना प्रारम्भ किया है हमारी सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी और हम लोग इस अभियान को आगे भी जारी रखेंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष का यह कहना कि केन्द्र की योजनाओं को ही आपने अपने साथ जोड़ा है, राज्य ने अपनी तरफ से कोई भी योजना लागू नहीं की। मुझे बड़ा अफसोस है उनके इस भाषण को सुनकर और मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि जो भाषण वह पढ़ रहे थे उसको उन्होंने स्वयं ही लिखा है या कहीं से लिखवा कर लाये थे। हो सकता है कि लिखवा करके लाये हों और अचानक यहॉ देखा हो और बोलने में भूल गये होंगे क्योंकि जब लोग बड़ा-बड़ा भाषण पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कभी-कभी कि क्या बोलना है क्योंकि जो लिखा होता है उसी को इमला की तरह बॉचना होता है तो जो उनका वाचन हो रहा था वह वाचन इसी प्रकार से हो रहा था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि राम गोविन्द जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं झूठ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कभी-कभी भाषण उनको झूठ बुलवा देता है और झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति थी वह उनके भाषण में भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोई योजना घोषित ही नहीं की है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र और प्रदेश मिल करके व्यवस्था का संचालन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमें उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को धन्यवाद् देना चाहिए कि उसने इस बात को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में प्रदेश में आई और प्रचण्ड बहुमत के साथ आई और आज केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं एकसाथ मिल करके चल रही हैं तो उसका लाभ कैसे मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका एक उदाहरण है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2014 से 2017 तक आप लोग 50 हजार आवास भी नहीं बना पाये और अकेले एक वर्ष के दौरान मा0 अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 31 मार्च तक हमारी सरकार 8 लाख 85 हजार गॉव के गरीबों को एक-एक आवास देने में सफल रही है। 8 लाख 85 हजार आप नोट कर लीजिए और मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम्य विकास मंत्री होंगे तो नेता प्रतिपक्ष को

कुछ प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत ग्रामीण आवास का उद्घाटन कराने के लिए जरूर लेकर जायें। जरूर उनको लेकर जाएं और साथ-साथ बलिया में उनके विधान सभा क्षेत्र में लेकर जाएं, वैसे अपने विधान सभा क्षेत्र में वह जाते नहीं हैं। अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के विधान सभा में कुछ गरीबों की झोपड़ियां आग से जल गई थी। मुझे समाचार मिला, तो मैंने प्रयास किया और वहां के जिला प्रशासन से कहा कि वहां के लोकल विधायक को लेकर जाइये जिससे वहां गरीबों में राहत और सहायता कार्य हो जाए। जानकारी करने पर गॉव के लोगों ने कहा कि नेता जी अब तो चुनाव के समय आएंगे, नेता जी को इस समय कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा कि माननीय सांसद जी से ही वितरित करवा दीजिए। कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि जाकरके बाटें, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गयी है कि प्रशासन अपने हाथों से फोटों खिचवाने के लिए नहीं जायेगा, बल्कि जनप्रतिनिधियों के हाथों जनता को अनुदान मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया है, हम लोग अपने पराये में नहीं बांटते। जनप्रतिनिधि के सम्मान का मतलब है, लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान, लेकिन वह जाते ही नहीं है। मैं बाढ़ के समय भी गया था उनके क्षेत्र में, तब भी नेता जी गायब थे। उस समय मैं सोचता था कि नेता जी अपने ह्वाइट हाऊस में मुझे भी लेकर जाएँगे, कुछ जलपान कराएँगे, लेकिन वह गायब हो गये। खैर हमें गरीबों को राशन वितरित करना था, वहॉ पर राहत सामग्री देनी थी। राहत सामग्री दे करके मैं चला गया था, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रमों में जाना था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने 3 लाख 60 हजार से अधिक आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृत जारी कर दिये हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी 31 मार्च तक 8 लाख 85 हजार आवास बन जाएंगे और मैं चाहूँगा कि अगर जहॉ कहीं भी कोई माननीय विधायक और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जाना चाहेंगे तो उनके हाथों कुछ गरीबों के आवासों का उद्घाटन जरूर हो जाए, क्योंकि इससे जनता में एक अच्छा संदेश जायेगा। और भी बहुत सारी योजनाएं है, इतना बड़ा प्रदेश है, स्वच्छ भारत अभियान में, इसमें भी नेता प्रतिपक्ष कहेंगे कि गरीबों का अपमान हो रहा है। वह बोल सकते हैं, क्योंकि आप किसी की जिह्वा को पकड़ नहीं सकते हैं और वे बोलेंगे, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब स्वच्छ भारत अभियान इस देश के स्वस्थ भारत अभियान का हिस्सा बन रहा है और एक स्वस्थ भारत का अभियान एक समृद्ध भारत का अभियान बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए, हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिल करके कार्य-योजना तैयार की है। पहली बार हो रहा है प्रदेश के अंदर एक वर्ष के दौरान 37 लाख से अधिक गरीबों के शौचालय बनाये गये हैं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

शौचालय का भी उद्घाटन करेंगे क्या? हम तो चाहेंगे, हमारे पंचायतीराज मंत्री अगर होंगे तो मैं कहूँगा कि लोगों को लेकर जाएं, एक फंक्शन कराकर कुछ गॉवों में एक साथ उद्घाटन करवा दें। यह तो अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर जनप्रतिनिधि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 37 लाख से भी अधिक गरीबों को एक-एक शौचालय बनाकर दिया गया है। 8 जिले हमारे अब तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 19 हजार से भी अधिक गॉव पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यह केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाने के बाद ही हो पाया है कि जो 8 लाख 85 हजार आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास

मंत्रालय ने बनाये हैं। इन सबमें एक-एक शौचालय भी हम मनरेगा के अंतर्गत दे रहे हैं। यह सब उसी योजना के हिस्से हैं। इसलिए हम लोगों ने केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू किया है। हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि केंद्र की अनेक योजनाएं, बिजली की योजना, सौभाग्य योजना। पहले गरीबों को बिजली का कनेक्शन 20-25 हजार रूपये देने पर भी नहीं मिलता था। शहर हो या गॉव, हमारी सरकार ने इसको लागू किया है। आज हर जगह हम लोग हर गरीब को कैम्प लगा करके विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। भारत सरकार पैसा दे रही है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर मजरे, हर गॉव तक, जितने हमारे राजस्व गॉव थे, उन सबको हम लोगों ने विद्युतीकरण से आच्छादित कर दिया है। अब हमारे जो छोटे-छोटे मजरे पड़े हुए हैं, 62 हजार से भी अधिक मजरे अभी भी ऐसे हैं जहॉ पर आजादी के बाद से कभी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है उन तक विद्युतीकरण के एक लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। भारत सरकार की योजना नहीं होती तो क्या राज्य सरकार के पास इतना पैसा था कि राज्य सरकार अपने बल पर करती, लेकिन अगर हो रहा है तो वह भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। प्रदेश के अंदर 8 ऐसे क्षेत्र थे जहॉ माननीय विधायकगण लगातार मॉग करते थे कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष 06 मेड़िकल कॉलेज को हम पूरा करेंगे और 08 मेडिकल कॉलेज हम प्रदेश की जनता को दे रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल हमारा होगा, जमीन हमारी होगी, 20 प्रतिशत धनराशि हम देंगे बाकी 80 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार उसमें देने जा रही है। उसकी कार्य-योजना स्वीकृत हो चुकी है और बहुत शीघ्र उस कार्ययोजना को भी हम लागू करने जा रहे हैं। अगर हम भारत सरकार की योजना को प्रदेश की योजनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे तो विकास अधूरा रह जायेगा और फिर वही स्थिति होगी जो इससे पहले होता रहा है क्योंकि पहले ये लोग केन्द्र की योजनाओं को नहीं लेते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने आवास नहीं बन पाये। प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जो इज्जतघर का निर्माण होना था इसलिए नहीं बन पाये थे क्योंकि प्रदेश सरकार को संकोच होता था कि हम भारत सरकार की योजनाओं को ले लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि हमें नुकसान हो जाये। ढ़ेर सारी ऐसी योजनायें हैं जिन योजनाओं में हम भारत सरकार की योजनाओं के साथ में जोड़ करके और अधिक से अधिक लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमने वो किया है। लेकिन राज्य सरकार ने भी अपनी योजनायें घोषित की हैं और उन योजनाओं में अगर मैं आपको बताऊँ, राम गोविन्द जी थोड़ा आप नोट कर लेते तो अच्छा रहता क्योंकि आपका जो भाषण लिखा होगा उसमें सम्भवतः कुछ और होगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

आप जो कह रहे हैं उसको तो हम लोग सुन ही रहे हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, नहीं आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अपना नोट मुझे भिजवा दीजियेगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं जो बोलूँगा वह तो प्रिंट होकर आ जायेगा। आप विधान सभा की कार्यवाही अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हॉ, रख लेना चाहिए ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आये। (हँसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

हॉ, यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है और हम लोगों ने अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति बनायी है प्रदेश के अन्दर। आज अगर निवेशकों और उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ा है तो इस बात को ले करके कि सरकार जो कहेगी उसको करेगी और हम लोगों ने 1400 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए अलग से व्यवस्था करके रखा है, नये बजट में इसका प्राविधान हुआ है। पहले से शासन की जो नीतियॉ थी, हम लोगों ने नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने यह पॉलिसी बनायी थी हम इसको लागू नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा कि पॉलिसी अगर स्टेट गवर्न्मेण्ट की थी तो स्टेट गवर्न्मेण्ट की पॉलिसी मानी जायेगी और इस पॉलिसी के अन्तर्गत अगर किसी उद्योगपति ने हमारी सरकारों से एम0ओ0यू0 किया था और उसको लागू करना है तो हम उसको लागू करेंगे, 1400 करोड़ रुपये उसके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था किया है। (मेजें थपथपायी गयी।) इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए यानि स्टार्टअप के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में, हमारा जो युवा है जो अपना स्वयं का कार्य करना चाहता है उसको बढ़ावा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। सरकार का विजन ही नहीं था, सरकार उधर सोचती भी नहीं थी। मैं आई0आई0टी0 कानपुर में गया था वहॉ के युवाओं से मिला। उनके पास आईडियाज हैं अलग-अलग सेक्टर्स में अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन छोटी सी पूँजी में प्रदेश में बेहतर कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है। उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लिया जा सकता है लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 250 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए पहले से हम लोगों ने व्यवस्था यहॉ पर की है। 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' में हम लोगों ने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने नेता प्रतिपक्ष और उनके नेता को, विपक्ष के सभी साथियों को, अपने मा0 सदस्यों को भी आमंत्रित किया था, सबको बुलाया था लेकिन चूँकि इन लोगों को अन्य कार्यों से फुर्सत नहीं होती इसलिए इस प्रकार के किसी रचनात्मक कार्यों में बहुत रूचि नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस से इनको कोई मतलब नहीं था। कहते थे कि वह कोई अपने घर में मनाता था वह पर्याप्त है। उनको प्रदेश से मतलब नहीं है। सरकार करे यह उनको अच्छा नहीं लगा। कहा वह तो पहले से मनाया जाता था। सरकार के स्तर पर क्या पहल हो पाई? आपने सरकार के स्तर पर क्या किया? नहीं हो पाया। हम लोगों ने 24 जनवरी को प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया। 68 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया (मेजों की थपथपाहट)और स्थापना दिवस केवल एक औपचारिकता न बन जाय। हम लोगों ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की एक विशिष्ट योजना उत्तर प्रदेश में लागू की। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारी मंशा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश का जो हस्तशिल्पी है, उत्तर प्रदेश का जो यहॉ पर जिन लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। आज ही नहीं वर्षों से। हम यह नहीं कह सकते कि हमने किया है। वर्षों से, आजादी के समय, आजादी के पहले उत्तर प्रदेश देश के अंदर MSME सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में नम्बर एक पर था। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को, यहॉ के नौजवानों को, यहॉ के सामान्य नागरिकों को अपने ही जनपद में, अपने ही गॉव में रोजगार मिल जाता था। लेकिन समय के साथ उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया। हतोत्साहित किया गया। कम पूँजी में ज्यादा रोजगार। हमें केवल उसकी नैटिंग करनी थी, उनकी

डिजाइनिंग करनी थी, उनको तकनीक देनी थी और उसकी ब्रांडिंग करनी थी। उसकी मार्केटिंग के लिये सपोर्ट करना था, सरकारों ने नहीं किया और इसलिये हम लोगों ने यह योजना चलाई कि औद्योगिक विकास के लिये जो MSME में छोटे छोटे क्लस्टर होने चाहिए वह उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद हैं। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग, अलीगढ़ में हार्ड वेयर का कार्य कितना अच्छा होता है। पूरे देश और दुनिया के अंदर कहीं भी ताले मिलेंगें अलीगढ़ के ताले मिलेंगें। लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं, बनता है अलीगढ़ में। भदोही का कालीन और केवल आप अपने बलिया के ही लिट्टी चोखा को ही आप थोड़ा ब्रांडिंग कर दिये होते (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आपने नहीं किया। फुर्सत ही नहीं थी आपको।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसमें बाटी चोखा हो गया है। पूरा प्रदेश और देश में। फाइव स्टार में भी लोग उसको परोस रहे हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपने नहीं किया। सरकार ने किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने नहीं किया तो किसने किया। आप तो एक साल से है और आपने कर दिया। हम तो कर ही रहे हैं। हम तो जब आपको बुलाते हैं तो आप आते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहॉ बाटी-चोखा होता है। सभी सदस्य हमारे खाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप बाबा हैं, प्रणाम है आपको।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं किया। उसकी ब्रांडिंग भी नहीं कर पाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक मिनट बैठ जायं तो मैं बता दूँ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

जब मैं बोल लूँगा उसके बाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक मिनट, आप हमारा आग्रह तो मान लीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

भदोही का कालीन।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आग्रह नहीं मान रहे हैं, एक मिनट।

श्री योगी आदित्यनाथ-

कन्नौज का इत्र। आपको फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन उसकी भी ब्रांडिंग नहीं कर पाये। फिरोजाबाद का कॉच का उद्योग। पता नहीं आप चूड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। (सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट) लेकिन फिरोजाबाद की चूड़ी की ब्रांडिंग नहीं कर पाये। कितना अच्छा कॉच का उद्योग है फिरोजाबाद में और ऐसे ही हर जनपद में कुछ न कुछ है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम चूड़ी पहनते नहीं हैं पहनवाते हैं। जो काम नहीं करते हैं उनको चूड़ी पहनवाते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपने चूड़ी स्वीकार की ना। चलिये इसी बात के लिये मैं आपको मुबारकवाद देता हूँ। लखनऊ का चिकन की कारीगरी और प्रदेश के हर जनपद में कुछ न कुछ है और हमारी सरकार ने उसके लिये 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के लिये प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये अपने युवाओं को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिये, आत्मनिर्भर बनाने के लिये 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। मैट्रो लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी हम लोगों ने, क्योंकि अब अलग-अलग मेट्रो नहीं बनेगीं, अब 'यू0पी0 मेट्रो कारपोरेशन' हम लोग गठित कर चुके हैं और इसकी डी0पी0आर0 आदि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कोरीडोर रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानि जो रेपिड रेल की योजना है, एक घंटे में आप दिल्ली से मेरठ पहुँच सकते हैं, चालीस मिनट का समय लगेगा, 32000 करोड़ रुपये की योजना है प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है कि मेरठ को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। (मेजें थपथपाईं) और हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। रीजनल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हवाई जहाज से जोड़ने की व्यवस्था, आजमगढ़ को भी जोड़ रहे हैं हम लोग, सभी को आपस में जोड़ रहे हैं, इलाहाबाद को भी जोड़ रहे हैं, पीछे उज्ज्वल रमण सिंह जी परेशान हैं पता नहीं इलाहाबाद का नाम है या नहीं, इलाहाबाद का नाम भी है, हर कमिश्नरी मुख्यालय को पहले चरण में जोड़ने की व्यवस्था, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। एक्सप्रेस वे, बड़ा ढोल पीटते हैं कि हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, अब तक पूरा नहीं हो पाया, धनराशि हम लोग दे रहे हैं पॉच सौ करोड़ रुपये हम लोगों ने इस बजट में दिया है तब वह एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

पिछले वर्ष भी धनराशि दिए थे, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई जन-सुविधा नहीं। यही आधे अधूरे कार्य यह लोग किए हैं। केवल ढोल पीटने का कार्य करते हैं बाकी कुछ नहीं किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने अपने स्तर पर की है। कहते हैं इतनी कम धनराशि क्यों की है आप लोग चिन्ता मत करिए पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनायेंगे, बलिया को भी जोड़ रहे हैं उसमें, चिन्ता मत करिए, वाराणसी बलिया भी जुड़ेगा। प्रश्न आपने उठाया था, हम लोगों ने कहा, इलाहाबाद को भी जोड़ने जा रहे हैं, इलाहाबाद को हम लोग दोनों एक्सप्रेस-वे से जोड़ने जा रहे हैं पूर्वांचल से भी और बुन्देलखंड से भी...

(मेजें थपथपाई गईं)

बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी हम लोग धनराशि की व्यवस्था किए हैं और सिंचाई की जिन योजनाओं के लिए वर्षो से, अध्यक्ष जी, कितना बड़ा अनर्थ किए यह लोग, 15 वर्षों में यह थोड़ा भी ध्यान दिए होते तो प्रदेश का किसान खुशहाल होता। सिंचाई की जिन योजनाओं के लिए धनराशि हम लोग अपने बजट में दे रहे हैं मध्य गंगा नहर योजना द्वितीय चरण की जो योजना है इसमें 1701

करोड़ रुपये हम लोगों ने इसके लिए उपलब्ध कराया है। सरयू नहर राजकीय परियोजना, इसके लिए 1614 करोड़ रुपये, अर्जुन सहायक परियोजना 741 करोड़ रुपये, कनहर सिंचाई परियोजना 500 करोड़ रुपये, बाण सागर परियोजना 127 करोड़, सिंचाई की जो अन्य योजनायें हैं उसमें 2215 करोड़, और बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए भी एक हजार चार करोड़ की व्यवस्था, हम लोगों ने बजट में, अपने राज्य सरकार के मद से की है,जो हमारी राज्य सरकार की योजनायें है उनसे हमने की है। हम लोगों ने तय किया है सिंचाई विभाग की और बाढ़ नियंत्रण की स्थाई समिति की बैठक 11 वर्षों के बाद मैं लिया हूँ दो बार, 11 वर्षों तक किसी सरकार को इतनी फुरसत नहीं थी कि वह प्रदेश के अन्दर बाढ़ नियंत्रण से संबंधित स्थायी समिति की बैठक ले सके।

(शेम-शेम की आवाजें)

सड़क सुरक्षा से संबंधित रोज एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं। टैक्निकल फाल्ट सड़क बनाने में है या लोगों को ट्रैफिक के रूल्स की सही जानकारी नहीं है, किन कारणों से यह होता है इसके लिए कभी फुर्सत नहीं हुई पिछली सरकारों को, हम लोगों ने इसको किया है, अभी बैठक किया हूँ अभी फिर एक सप्ताह के अन्दर हम लोग फिर से बैठक लेने जा रहे हैं। मौतें किसी की भी हों, वह कोई भी हो, व्यापक जनहानि है। हम सबकी संवेदना उनके साथ जुड़नी चाहिए और प्रयास होगा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोका जाना चाहिए, कौन से सुधार हो सकते हैं, कौन से कार्यक्रम बन सकते हैं, उसके लिए उस प्रकार की कार्ययोजना हम बना रहे हैं। गरीबों की बात बहुत करते हैं बहुत ज्यादा बातें होंती हैं। लेकिन गरीबों के खाद्यान्न को ही हड़प जाते हैं लोग। माननीय अध्यक्ष जी, जब पहले चरण में सत्यापन की कार्यवाही हुई है तो 30 लाख राशन कार्ड फर्जी पाये गये थे और 37 लाख ऐसे परिवार पहले चरण में पाये गये, जिनके पास अपना राशन कार्ड नहीं था, जिसमें एक लाख अन्त्योदय और 36 लाख पात्र गृहस्थी के थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी को हम लोगों ने राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है। अभी जो बनटांगिया गांव की चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने मान्यता दी है, 23 गांव को दे चुके हैं, 5 गांव गोण्डा के हैं, वहां भी मैं इस महीने के अन्त में जाने वाला हूं या फिर अप्रैल प्रथम सप्ताह में जाकर के उनको भी राजस्व गांव का दर्जा देंगे। बाढ़ से, अग्निकाण्ड से जो गरीब की झोपड़ियां जल जाती थीं, उन गरीबों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार एक सामान्य अनुदान दे देती थी। यदि किसी गरीब की झोपड़ी उजड़ जाती थी तो मात्र 4 हजार रुपये का उसको अनुदान मिलता था, हम लोगों ने व्यवस्था की है, एक नयी आवास योजना प्रदेश के अन्दर लेकर आ रहे हैं ''मुख्य मंत्री आवास योजना''। उन सभी गरीबों को जो किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाते हैं, जो किसी अन्य अग्निकाण्ड के शिकार हो जाते हैं या फिर जिनको कभी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, ऐसे सभी गरीबों को प्रदेश सरकार की तरफ से एक लाख 20 हजार रुपये आवास के लिए हम लोग उपलब्ध करायेंगे और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। अध्यक्ष जी, यह लोग बहुत छिपे हुए रूस्तम हैं, अपने घर के सारे छुट्टा पशुओं को सड़कों पर छोड़कर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई कल्पना कर सकता है कि क्या कोई बछड़ा 9 महीने में इतना बड़ा हो जाए कि वह किसानों की पूरी फसल को नुकसान पहुंचा दे। कई जगह पकड़े गये, हम लोगों ने कहा जाने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इस समस्या का समाधान हम लोग निकालेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे तमाम मा0 विधायकों ने इसमें रूचि ली। हम लोगों ने बजट में भी व्यवस्था की है कि निराश्रित गोवंश के

लिए भी हम लोग एक-एक गो अभ्यारण्य हर जनपद में बनाने की कार्रवाई करेंगे और विभिन्न जनपदों में यह कार्य प्रारम्भ भी हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिए हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है। मत्स्य पालन कल्याण फन्ड के लिए हम लोगों ने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है। डेयरी विकास के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है और चीनी उद्योग के लिए भी। देश और प्रदेश दुनिया में चीनी उद्योग के लिए माना जाता था। मुझे उस दिन सुनकर अफसोस हो रहा था मा0 राम गोविन्द जी कहते थे कि हम लोग संपत्ति को बेच रहे हैं। हम लोगों के रहते प्रदेश की कोई संपत्ति नहीं बिकेगी, मैं इस बात को कह सकता हूं। हम संपत्ति बेचने नहीं आये हैं, लेकिन हां यह सच है कि आप लोगों ने प्रदेश की चीनी मिलों को बेचा है। क्या यह सच नहीं है?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

लगाया है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लगाया नहीं, बेचा है। आपने अपने भाषण में कहा है, आपने कई चीनी मिलों को बन्द किया है और औने-पौने दामों में बेचा है। प्रदेश के किसानों के साथ इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। हम लोग प्रदेश के अन्दर चीनी मिलें लगा भी रहे हैं। पिपराइच में भी एक चीनी मिल लग गयी है और मुण्डेरवा में 29 तारीख को चीनी मिलों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। रमाला की चीनी मिल के बारे में एक्सटेंशन के कारण भी उसकी हुई है, मोहद्दीनपुर की चीनी मिल के बारे में हम लोगों ने कार्यवाही प्रारम्भ की है और अन्य चीनी उद्योग के बारे में भी जो कुछ हो सकता है, हम लोगों ने भी इस बात की परमीशन लेने के लिए गन्ना विभाग से कहा है, डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, गन्ना किसानों के हित से और चीनी मिलों के हित से भी, लेकिन उस सबके बावजूद रिकार्ड मात्रा में हम लोगों ने गन्ना मूल्यों का भुगतान किया है और जहां पर नहीं हो पाया है वहां पर लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में गन्ना किसानों का जमा मूल्य का भुगतान हो। पहली बार प्रदेश का चीनी मिल मालिक कह सकता है कि प्रदेश के अन्दर सरकार के स्तर पर उनका कोई भी उत्पीड़न नहीं हुआ है। कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है नहीं तो पहले क्या होता था कि एक-एक कुन्तल में और मॉलेसिस में तो एक-एक लीटर में आप लोग दाम बांध देते थे। यह पहली बार हो रहा है कि वह पूरी तरीके से स्वतंत्र हो करके प्रदेश के विकास की तरफ अपने ध्यान को फोकस कर रहा है। अब तक लगभग 27 हजार करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले वर्ष से लेकर अब तक हम लोगों ने इस सरकार में कराया है और पैसा किसानों के खाते में गया है। किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना उपलब्ध कराया जा रहा है। नयी चीनी मिलें भी लगाई जा रही हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य में भी किये हैं और हर जनपद में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की स्मृति में एक नगर पंचायत को हम आदर्श नगर पंचायत बना सकें, इस कार्ययोजना को भी हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है और उसके लिये हमने अलग से धनराशि की व्यवस्था की है। साथ ही साथ बिना भेदभाव के अन्त्येष्टि स्थलों के लिये भी धनराशि दी जा सके, इसके लिये भी हम लोगों ने बजट में प्रस्ताव किया है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) महिला एवं शिशु कल्याण योजना में 'शबरी संकल्प योजना' के लिये भी हम लोगों ने 524 करोड़ रूपये दिये हैं। कुपोषण से मुक्ति बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब कन्याओं की शादी, प्रदेश के अन्दर कोई भी

गरीब कन्या दहेज के अभाव में शादी के बगैर न रहे, परिवार के लोग चिन्तित न हों, इसके लिये 35 हजार रुपये प्रति शादी प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है और प्रदेश के तमाम जनपदों में हमारे जनप्रतिनिधियों ने यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है और शेष जनपदों में भी यह कार्यवाही चल रही है। समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छा काम इस मामले में किया है। काफी बड़ी संख्या में शादियाँ हो चुकी हैं और काफी बड़ी संख्या में आगे भी होंगी। स्कूलों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के लिये भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। पहली बार यह व्यवस्था की गयी है। मा0 राम गोविन्द जी, आप तो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं। क्या कारण थे कि आपके मंत्री रहते हुए बच्चे स्कूल छोड़ने लग गए थे और क्या कारण है कि हमारी सरकार आने के बाद बच्चे बड़ी मात्रा में स्कूल आने प्रारम्भ हो गए हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) कुछ तो कारण होगा कि बच्चों की संख्या में एक वर्ष में ही 18 लाख की वृद्धि हो जाए, समय पर यूनीफार्म मिली, समय पर बैग और बुक्स मिले। पहली बार गरीब का बच्चा भी जूता पहन सकता है। वह मोजा और जूता पहन करके जा सकता है। क्यों मनोज पाण्डेय जी, आपने भी तो अपने क्षेत्र में यह किया होगा? यही नहीं, इस वर्ष हम लोगों ने स्वेटर भी दिया है। पहली बार गरीब का बच्चा भी स्वेटर पहन सकता है और यह प्रदेश में पहली बार हुआ है। नये सत्र में पहली अप्रैल से, पहली अप्रैल को तो रविवार पड़ेगा तो 02 अप्रैल से 'स्कूल चलो अभियान' चलेगा। मैं तो आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि पक्ष तो जायेगा ही जायेगा, लेकिन मैं आप सभी को आमंत्रित करूँगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो 'स्कूल चलो अभियान' चलाया जायेगा तो उसमें यह प्रयास होना चहिये कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो स्कूल जाने से वंचित रह जाए। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) हम हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे और सरकार इस बात को कह सकती है कि हर बच्चे को हम दो यूनीफार्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे और सभी सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे और एन0सी0ई0आर0टी0 के नये पाठ्यक्रम के साथ हम लोग उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पब्लिक और कान्वेन्ट स्कूल पीछे छूटेंगे और बेसिक शिक्षा के विद्यालय आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे जिलों में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने विद्यालय गोद लिये कि नहीं, लेकिन इधर के हमारे तमाम मा0 विधायकों ने एक-एक, दो-दो, तीन-तीन विद्यालय गोद लिये हैं, अच्छा काम किया है। बहुत सारे विधायकों ने विद्यालय गोद लिये हैं और बहुत अच्छा काम किया है। कल मैं फिरोजाबाद में था। फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा के लगभग सभी विद्यालयों को पूरी तरीके से उसमें नया बदलाव आया है यह आपको देखने को मिलेगा। कोई सरकार ने पैसा नहीं लिया विधायक निधि का इस बार मुझे पैसा मिला तो मैंने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को कहा मैंने कहा कि बेसिक शिक्षा के विद्यालय में फर्नीचर में इसको लगा दो हमने पैसे के लिए व्यवस्था की फर्नीचर बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भी लगे इस दृष्टि से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप गरीब की बात करते हैं और गरीबों का ही हमेशा शोषण करते हैं। गरीबों का कार्य सही मायने में बिना भेदभाव के कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है । बजट में इसका प्राविधान भी किए हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय यह लोग गरीबों की चर्चा करते हैं तो इनसे पूछा जाना चाहिए मिट्टी पर रायल्टी किसने लगाई थी और 10 वर्षों तक प्रदेश की जनता का शोषण मिट्टी के नाम पर करते रहे। प्रदेश की जनता का जितना शोषण इन लोगों ने करवाया है, किया है मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को मिट्टी में रायल्टी से मुक्त कर दिया है। प्रदेश की जनता से

मिट्टी के नाम पर कोई रायल्टी हमारी सरकार नहीं लेगी। हमने तो ईट भट्ठे वालों को आह्वान किया है ईंट भट्ठा के जो व्यवसायी हैं उनसे भी कहा कि ईंट के दाम वह कम करें हम उनको भी मिट्टी में रायल्टी फ्री कर देंगे। ईंट के दाम कम होंगे तो गरीब के लिए वह सुविधा होगी हमारे विकास की योजनाएं आगे बढ़ेंगी। हम लोगों ने यह व्यवस्था भी की है मिट्टी पर रायल्टी बहुजन समाज पार्टी ने लगाई थी और उसकी आड़ में दोनों दल हमेशा प्रदेश की जनता का शोषण करते रहे हैं। हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि जो गरीब जो दलित जो वंचित गांव में जिस जमीन पर है अगर वह आरक्षित भूमि नहीं है यानी जिस भूमि पर जिसकी नवैयत बदल नहीं सकती उस प्रकार की भूमि नहीं है तो उस भूमि का पट्टा हम उसके मकान बनाने के लिए उस गरीब को ही उपलब्ध करवाएंगे यह निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जहॉ पर वह आरक्षित भूमि पर कब्जा किया हुआ है उसको सुरक्षित रूप से एक अच्छी जमीन का पट्टा उसको उपलब्ध कराकर उसको मकान बनाने की कार्यवाही भी हमारी सरकार करेगी इस दिशा में आप लोग 12 -15 वर्षों तक क्या कर रहे थे। यह लोग शोषण करते थे लेकिन इस बात को मानना कि प्रदेश के अन्दर जितने बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है यह कब्जा हटेगा हर हाल में हटेगा और हर हाल में उन कब्जों से मुक्ति दिलाने की कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। यह गरीबों की बात करते हैं अफशोस है 1525 से अधिक ऐसे गांव हैं जिन गॉवों में आजादी के बाद कोई सुविधा नहीं मिल पाई । जो वन्य गांव हैं इन गांवों में तो वोटिंग राइट तक नहीं था आज भी तालाब का पानी लोग पीते हैं कोई पक्का मकान वहॉ पर नहीं है। बिजली नहीं है सड़क नहीं है हमारी सरकार उनको सभी योजनाओं से आच्छादित कर रही है। युद्धस्तर पर कार्य प्रारम्भ हुआ है हम लोग उसको वहॉ तक पहुँचाएंगे। यही नहीं देश के अन्दर देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ जो सैनिक शहीद होता है हम लोगों ने तय किया है दो प्रकार की योजनाएं लागू की हैं एक अप्रैल 2017 से लेकर अब तक जितने भी जवान देश की सीमा पर शहीद हुए हैं उन शहीद जवानों के परिवार के एक आश्रित को हम प्रदेश के अन्दर नौकरी देंगे । साथ ही साथ शहीद गांव बनाकर गांव की सड़क को बनाना गांव को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करना गांव का तोरण द्वार उस शहीद के नाम पर बनाना मूर्ति को स्थापित करके हम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। यह कार्य प्रमुखतः के साथ प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है और इसीलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष से कहना है कि, ***''हम तो अभी इसकी तस्वीर सुधारने में लगे हैं, आप लोग हैं कि आग लगाने में लगे हैं, मजहब किसी को इसकी इजाजत नहीं देता, हम हैं इस आग को बुझाने में लगे हैं''*** (**सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपायी गयीं**) और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो केन्द्र की योजनाओं को और प्रदेश की योजनाओं को, (**इसी मध्य नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी सीट पर बैठे-बैठे यह कहा कि ये बहुत बढ़िया हो गया कि आग लगाने वाले आग बुझाने की बात करने लगे**) इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वास्तविक तस्वीर सामने आनी चाहिए और वह हम लोगों ने किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने ''उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट'' भी किया है। एक बहुत ऐतिहासिक इवेन्ट था उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और देश की दृष्टि से भी। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इण्डिया के विजन की बात करते हैं तो नव भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास दिखना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास अन्तिम पायदान तक खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और उस अन्तिम पायदान पर पहुँचे

हुए व्यक्ति के लिए प्रदेश का युवा पलायन करे, प्रदेश के नौजवान को देश के सामने जा करके हीन भावना का सामना करना पड़े ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति बनायी गयी है प्रदेश के अन्दर। वह कहीं जाता था अपनी पहचान छुपाता था और इसलिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिए अलग-अलग पॉलिसी बनानी पड़ी। पिक एन्ड चूज की प्रथा समाप्त हो, हमने पॉलिसी बनायी है, औद्योगिक विकास की अलग बनायी है, टैक्सटाइल की अलग बनायी है, फूड प्रौसेसिंग की अलग बनायी है, एवियेशन की अलग बनायी है, फोकस सेक्टर की अलग बनायी है, अलग-अलग पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की हैं और फिर देश के, चोटी-चोटी के उद्योगपतियों को और अन्य उद्योगपतियों को हम लोगों ने बुलाया और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के बारे में लोगों का परसेफ्शन बदला है। यह है टीम स्पिरिट। यही है एक टीम वर्क। हर एक व्यक्ति ने उसके साथ जुड़ करके अपने आप को जोड़ा है। हर एक मंत्री, हर एक विधायक हर एक ने उसको अपने आप को जोड़ा है और उसका परिणाम ही है कि यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट सफलतम इन्वेस्टर्स समिट था देश के अन्दर का और उसने एक मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पहली बार 4 लाख 68 हजार करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में। पहले तो लोग कहते थे क्या होगा, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में। स्वभाविक रूप से जो पहचान इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बनायी थी तो वे लोग यही सोचते थे कि वही होगा तो उनकी सोच ऐसी थी। लेकिन हम लोगों ने इस तस्वीर को बदला है। मेहनत करनी पड़ी है, परिश्रम करना पड़ा है। एक-एक व्यक्ति लगा है, अपने अनुसार मेहनत की है औद्योगिक विकास मंत्री पूरे देश के अन्दर गयें हैं, वित्त मंत्री अपने तरीके से कार्य योजना बनाये हैं, अलग-अलग मंत्री अपने अनुसार पॉलिसी तैयार करने के बाद उस सेक्टर के जो भी उद्यमी थे उनके साथ एक संवाद स्थापित किया। पहली बार हुआ है कि वह उद्यमी पहली बार इस बात को संतुष्ट होकर करता था कि साहब पहली बार हो रहा है कि हम लोगों से संवाद बनाया जा रहा है। मंत्री के स्तर पर, मुख्य मंत्री के स्तर पर, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर और नहीं तो इससे पहले केवल उनसे कमीशन लेने के लिए ही लोग संवाद करते थे, प्रदेश में निवेश के लिए नहीं करते थे और उस मानसिकता को बदला गया, परसेफ्शन बदला प्रदेश का। आज देश का हर चोटी का उद्योगपति भी इस बात को कहता है, दुनिया का बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी कहता है कि उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा स्थल है(**सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपायी गयीं**) क्यों, क्योंकि इस प्रकार का माहौल किया गया था, आज उनको सुरक्षित वातावरण हम दे रहे हैं। आज इसके लिए हमने एक पालिसी तय कर दी है कि अगर आप उस पालिसी के दायरे में आते हैं तो आप आईये आपको शासन सुविधा देगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पसन्द और नापंसद होती थी। हमने पसन्द और नापसन्द की दुर्व्यवस्था को दरकिनार करके पॉलिसी तय की है। अलग-अलग सेक्टर की पॉलिसी तय हुई, पॉलिसी के अनुसार उद्यमी अब निवेश के लिए आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस महीने हम 25000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को पहली बार क्रियान्वित करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले महीने फिर इसी प्रकार के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ायेंगे। यह प्रस्ताव प्रदेश के विकास के साथ-साथ प्रदेश के यूथ के लिए है, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आवश्यक है। यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश के अंदर जिलों को हम लोग 'वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट' के अंतर्गत भारत सरकार की योजना के साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ, प्रधानमंत्री स्टैण्ड अप योजना के साथ, स्टार्ट अप योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, यह ढ़ेर सारी योजनायें हैं इनके साथ हम प्रदेश के लोगों को

जोड़ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हमारा औद्योगिक विकास मंत्रालय एवं इससे जुड़े हुये हमारे माननीय मंत्री और अधिकारीगण सभी मिल करके आने वाले तीन वर्ष के दौरान प्रदेश के बीस लाख यूथ को सीधे-सीधे नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं। जितने निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आये हैं, अगर इन सबको हम प्रदेश के अंदर लागू करवाने में सफल हो जाते हैं तो तैंतीस लाख से अधिक लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार पायेंगे। यह प्रयास पहले क्यों नहीं किये गये, क्योंकि पहले लोगो की हवेलियां बनती थी, उनके बैंक बैलेन्स बढ़ते थे, विदेशों में उनके एकाउण्ट बढ़ जाते थे, तमाम अन्य चीजें उनकी बढ़ जाती थी। वह स्वयं अमीर होते थे, लेकिन प्रदेश गरीब हो जाता था। आज यह नहीं है, आज तस्वीर बदली है और उसी तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग आये हैं। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट ने जहां यह चीजें साफ की हैं, वहीं साथ ही साथ नौकरी के अवसर बढ़ाये हैं। हम लोगो ने प्रदेश के अंदर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उच्चतर चयन सेवा आयोग का गठन कर दिया है, अन्य तमाम आयोगों के गठन या तो पूरे हो गये हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं। लेकिन उसमें आप देखिये, हर क्षेत्र में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके छोड़ा है कि जीवन भर उन नौजवानों को कुछ लोगो के पाप की सजा मिल रही है। सचमुच हम देखते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ। शिक्षा मित्रों के साथ यह लोग ईमानदारी बरते होते तो आज एक लाख से अधिक शिक्षा मित्र सड़को पर नहीं होता। इन लोगो ने उनके साथ भेदभाव किया है, इन लोगो ने उनके साथ विश्वासघात किया है। साढ़े तीन हजार रूपये प्रतिमाह का मानदेय उनको मिलता था, हम लोगो ने उनका मानदेय बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया है। हमारी सहानुभूति उनके साथ में हैं, लेकिन उनके जीवन के साथ इन लोगो ने खिलवाड़ किया है। पुलिस की भर्ती आप देख लीजिये, हमारा युवा सड़को पर दौड़कर प्रैक्टिस करता है, फिजिकली वह अपने आपको फिट करता है लेकिन जब भर्ती आती थी तो फिर कुछ न कुछ उसमें शुरू हो जाता था। आप तो बलिया वालों के साथ भी न्याय नहीं करा पाये, आप जौनपुर वालों के साथ न्याय नहीं करा पाये। बलिया और जौनपुर से अच्छा नौजवान कहां मिल सकता था। लेकिन आप लोगो ने उनकी भर्ती में योगदान नहीं दिया है। एक लाख बांसठ हजार सब इन्सपेक्टर, पुलिस कान्स्टेबल और फालोवर्स के पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी क्योंकि न्यायालय को मालूम था कि जो लोग सत्ता में हैं उनकी नीयत साफ नहीं है जिससे यह लोग प्रदेश के साथ भेदभाव करेंगे और कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बीस हजार की भर्ती पर रोक लगानी पड़ी न्यायालय को। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पर न्यायालय को रोक लगानी पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि चार लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती के अधियाचन हम लोग जारी कर चुके हैं और इन पदों पर प्रदेश के योग्य लोगो को मेरिट के आधार पर हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप फोर की नौकरियों में हम लोगों ने इन्टरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी है। मा0 अध्यक्ष जी, आरक्षण खत्म नहीं किया है, आरक्षण दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ेगी तो अति पिछड़ी और अति दलितों के आरक्षण पर भी विचार करेंगें। चिंता मत कीजिए। एकाधिकार समाप्त करेंगें। घबराईये नहीं। हर गरीब हर दलित हर वंचित जिसको अधिकारों से आप लोगों ने वंचित किया है, हमारी सरकार उनको सम्मान दिलायेगी। (सत्तापक्ष द्वारा मेंजों की थपथपाहट)। उसके लिए हम लोग कमेटी गठित कर रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद जिन लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर के सम्मान मिलना चाहिए था, वे वंचित हैं। उनका इस्तेमाल किया गया है, उनका शोषण किया गया है। शासन की योजनाओं से उनको वंचित किया गया है। आज

उन्हें सम्मानजनक ढ़ग से उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम इस कार्य को करेंगे। नौकरी लेकर के आए हैं और नौकरी देंगें भी। पूरे प्रदेश के अन्दर देंगें, बिना भेदभाव के देंगे। ग्रुप-3 और ग्रुप-4 की नौकरी जिसमें यह लोग भेदभाव करते थे। जिसमें इन लोग द्वारा लेन-देन होता था। कोई सोचता था कि यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा में 40 लाख से लेके 60 लाख तक भर्ती करने के लिए पैसे लिये जायेंगें। वह सब गलतफहमी के शिकार हैं, वह सब जेल जायेंगे। पूरी जांच तो होने दीजिए और पारदर्शी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं लागू होंगी और अगर किसी ने भेदभाव किया प्रदेश के नौजवानों के साथ तो न केवल उसको हम जेल भेजेंगे, उसकी सम्पत्ति भी कुर्क करने का कार्य भी करेंगे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा 'भारत माता की जय' के नारे लगाये गये)।

कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। मैं आश्चर्यचकित था कि केन्द्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई। 2014 में आने के बाद सरकार ने बिना भेदभाव के राज्यों का आवंटन बढ़ाया। आवास योजना का रहा हो, ओ0डी0एफ0 का रहा हो, बेसिक शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य सेवाओं का रहा हो या फिर किसी भी अन्य योजना का। विद्युतीकरण का हो, ग्राम्य विकास का हो। विद्युतीकरण की स्थिति यह थी कि यह प्रस्ताव ही नहीं भेजते थे। ग्राम्य विकास की स्थिति यह थी कि कई वर्षो से और यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही नहीं, मैं गोरखपुर से एक सांसद के रूप में भी था। मैं इस बात को सोचता था कि हमेशा वहां पर हमारी भारत सरकार में इस बात को लेकर के अक्सर हम लोग वहां मंत्रियों से लड़ते थे कि प्रदेश को पैसा मिले, पता लगता कि अभी तक अपनी कार्य योजना बनाकर नहीं भेजी है। पिछले कार्यों का ब्यौरा नहीं भेजा है। यह इनकी स्थिति थी। यह लोग एन0ओ0सी0 नहीं भेजते थे। कोई नई कार्य योजना नहीं भेजते थे क्योंकि पैसा डायवर्ट हो जाता था और उसका परिणाम यह है कि यह लोग कहते है कि केन्द्र सरकार भेदभाव कर रही है। केन्द्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया हैं। केन्द्र सरकार की वहीं योजनाऐं हैं। जो आवास की योजना प्रदेश सरकार के लिए थी, इन्होंने नहीं बनाया। हम लोगों ने अपील की वे सारे-के-सारे आवास हमें मिले। दो साल के आवास प्रदेश सरकार ने एक साल में बनाकर तैयार कर दिये। हमारा कौशल था हम पैसा ले लिये। आपके पास कौशल नहीं था तो आप लोग नहीं ले पाये। हां, हम लोगों ने किया। प्रदेश में डेढ़ सौ लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस मिलनी थी। 75 जिलें है हर जिलें में दो-दो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स होती। उसमें वेन्टीलेटर भी है, उसमें सभी सुविधाएं हैं। 2014 में भारत सरकार देना चाहती थी लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया। देश के अन्दर यह पहली बार हो रहा है, जब कोई सरकार अपनी पार्टी के नाम पर योजना चला रही थी।

मान्यवर, यह पहली बार हो रहा है देश के अंदर जब कोई सरकार अपनी पार्टी के नाम पर योजना चला रही थी। सरकार पार्टी की नहीं होती है सरकार सरकार होती है। सरकार को उस लेवल से ऊपर उठकर काम करना होगा। लेकिन समाजवादी के नाम पर योजनायें चलाना, यह सब क्या है। आप प्रदेश के साथ मजाक कर रहे हैं। और इसलिए आप केंद्र की उन योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। इनको लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि केंद्र सरकार की योजनायें बड़ी हो जायें और इनकी योजनायें छोटी पड़ जायें। कहीं केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता को मिल जाये तो फिर ऐसा न हो कि जनता फिर उनसे सवाल पूछे कि भई, केंद्र की योजनाओं में यह लाभ मिल रहा है और इसमें यह प्राविधान है आपकी योजनाओं में तो कम ही लोगों को लाभ मिल पा रहा है। इन्होंने उसको लागू नहीं

किया। लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने नहीं आने दी। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस से कितने लोगों की जान बची होती अगर 2014 से 2017 के बीच यह लोग लाये होते। जब हमारी सरकार आयी तो 150 लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंसेस उपलब्ध हुयीं। रेस्क्यू वेन, महिलाओं के कल्याण के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए हर जिले में लागू होनी थी। मात्र 15 जिलों में लागू हुयी। भारत सरकार पैसा देना चाहती थी। महिला और बाल विकास विभाग बराबर कह रहा था इनको कोई फुर्सत नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर हर जिले में रेस्क्यू वेन चल रहा है। प्रदेश के अंदर और भी योजनायें हैं। गलती आपकी है। केंद्र सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार भरपूर पैसा देना चाहती थी। आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाये। आप करना ही नहीं चाहते थे। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की हैसियत चार गुनी बढ़ी है। निश्चित रूप से प्रदेश में बढ़ी है। पता नहीं आप खेतीबाड़ी पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि अब तो आप मालदार हो गये हैं। हमें नहीं लगता कि आप खेती में जाते होंगे। आज अगर आप देखेंगे कि पहली बार गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदेश के किसानों के लिए 1735 रूपये हम लोगों ने घोषित किया है। 10 रूपये अतिरिक्त देंगे और 5500 केंद्र पूरे प्रदेश में स्थापित करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक किसान को हम लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित करने जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय 2016-17 की तुलना में 2017-18 में चार गुना से अधिक हुआ है। आप लोग आड़तियों के माध्यम से खरीदते थे हमारी सरकार ने किसानों से सीधे खरीदा है और हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर पहली सरकार है जो इतनी बड़ी मात्रा में 50 लाख मी0टन का हम लोगों ने आंकड़ा दे दिया है कि यहाँ तक हम लोग लेंगे। क्योंकि यहाँ तक हमारे पास गोदाम मौजूद हैं। और अगर नहीं होंगे तो भी अगर किसानों के पास गेहूं होगा तो भी हम किसान से खरीदेंगे। किसी को निराश नहीं होने देंगे। किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में संतोषजनक और सम्मानजनक दाम उसको मिलना है। आपके समय में किसान को 900 और एक हजार रूपये भी नहीं मिल पाता था। आज उसे समर्थन मूल्य के बराबर और उससे ज्यादा दाम मिल रहा है। 1735 रूपये, और इस बार 110 रूपये प्रति कुंतल बढ़ाया है। और 10 रूपये अतिरिक्त राज्य सरकार उनको देगी। 120 रूपये प्रति कुंतल प्रत्येक किसान को गत वर्ष की तुलना में अधिक दाम दिये जा रहे हैं। तब भी आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। धान 43 लाख मी0टन किसानों से लिया गया। पैसा 24 घण्टे के अंदर किसानों के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिया गया। यानी जिस बात के लिए आपको विपक्ष में रहकर धन्यवाद देना चाहिए था कि किसानों के बारे में कार्य हो रहा है। धन्यवाद देने के बजाये आप लोग उस मुद्दे को छूना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि किसानों से आपको कोई मतलब नहीं है। और किसानों के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हैं। आपने बहुत सारे अन्य मुददों की बात की। एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट की बात की। एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट के बारे में आपने चर्चा की थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हमारे पास प्रदेश के अंदर 653 नगर निकाय हैं। जिसमें 16 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकायें हैं। 438 नगर पंचायत हैं। इन सभी में फेज वॉईस हम लोगों ने एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाने का फैसला लिया है, लेकिन एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का प्रदेश सरकार कोई पैसा नहीं ले रही है। यह सब फ्री में लगेगा और एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाने के बाद बिजली की उससे जो बचत होगी उस बचत की राशि से ही वह लोग सात वर्ष तक मेंटेनेंस करेंगे तथा पूरी व्यवस्था को भी देखेंगे। पूरा शहर, हर गांव, हर नगर निकाय जगमगाता हुआ दिखाई देगा। हम लोग कई शहरों में लगा चुके हैं और यह प्रक्रिया

लगातार आगे बढ़ रही है। मान्यवर, यह घोटाला नहीं है। यह प्रदेश की समृद्धि का आधार हैं। प्रदेश में ऊर्जा की बचत है और प्रदेश में ऊर्जा की जो बचत होती है वहीं हम लोग गांव में देते हैं। मान्यवर, शहरी क्षेत्र में बिजली की बचत पर बात हो रही है और उसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे रहे हैं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि एक वर्ष में कोई कार्य ही नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आप यहां भाषण दे सकते हैं भाषण देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिरे से नकार दें और फिर आपने कहा कि ''एकलव्य का अंगूठा'' याद करिए गोरखपुर में अखिलेश निषाद को गोली से आपकी सरकार ने मारा था किसी और ने नहीं मारा था। जब निषाद जाति के लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे तो उसको मरवाने का काम किसी और ने नहीं किया था वह आपकी सरकार ने किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। ''एकलव्य का अंगूठा'' उधर काटा जाता है। इधर नहीं। इधर तो एकलव्यों के उत्थान के लिए कार्य होता है। ''मछुआ आवास'' यहां से बनाएं जाते हैं। उनके लिए विशेष कार्य योजना लेकर के हमारी सरकार आ रही है और यह पहली बार हो रहा है जब श्रृंगवेरपुर के विकास के लिए भी हमारी सरकार एक योजना के साथ आ रही है और वहां पर पर्यटन विभाग ने विशेष योजना भी प्रारम्भ कर दी है जिसका कार्य वहां पर चालू हो गया है। आप लोग समाज को बांटना चाहते हैं। अभी भी विभाजनकारी मानसिकता से आप लोग उभर नहीं पाए हैं। मैं आश्चर्य करता हूं कि पशु पालन विभाग ने पता नहीं क्यों राम गोविन्द जी से किसी आरोग्य मेले का उद्घाटन नहीं कराया है और मैं कहूंगा कि उनको ले जाकर के उद्घाटन कराना चाहिए। वह जिस परम्परा से आते हैं वह ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उनको व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा है। अपने व्यावहारिक ज्ञान से भी आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप बलिया में जाईये अपनी विधान सभा क्षेत्र में किसी पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन करिए। यह बहुत अच्छे मेले हैं। पशु पालकों से जुड़े हुए जितना भी पशुधन है उसके लिए उसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोगों ने कमिश्नरी हेड क्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों पर फिर ब्लॉक मुख्यालयों पर तथा न्याय पंचायत पर इसको लगाने की एक नई परम्परा की शुरूआत की हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसमें जाइए और उन सब कार्यो को आगे बढ़ाईए। कहते हैं कि कर्ज माफ नहीं किया है। मान्यवर, कभी-कभी सदन में हमें सच भी बोल लेना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं आपसे इस बारे में फिर अपील करूंगा कि अच्छा होता कि आप सही तथ्यों को रखते क्योंकि सरकार तो कार्य योजना बनाएगी। उसको लागू करने का कार्य तो हम सबको मिलकर करना होगा और अगर आप सही जानकारी देंगे तो प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। बहुत बार होता है कि जनता में जागरूकता का अभाव। वह विकास की योजनाओं से वंचित हो जाते हैं अगर पब्लिक में अवेयरनेस हो, पब्लिक में जागरूकता हो तो विकास की योजना को उन तक लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान्यवर, इसी दृष्टि से चर्चा के लिए सदन बुलाया जाता है कि हम इस पर चर्चा करें।

यह कहना कि किसी सदस्य के पास कोई सुझाव नहीं। हम लोगों ने कई बार इस बात की अपील की कि सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हर एक सदस्य के पास अपने क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपना एक नया आइडिया होता है, उसका एक नया नजरिया होगा और उस नए नजरिये के साथ प्रदेश के अंदर हम उस प्रकार योजनाएं लागू करेंगे। उस नजरिये को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए चर्चा के लिए सदन बुलाया जाता है, आरोप-प्रत्यारोप के लिए नहीं। और विरोध के लिए विरोध हो इस बात के लिए चर्चाएं नहीं

होती हैं। हमने एक सार्थक पहल की है। आपके पास अच्छे आइडियाज होंगे तो हम अवश्य स्वीकार करेंगे। सरकार के अच्छे कार्यक्रम हैं उनको आप स्वीकार करिए, अपने क्षेत्र में आप लागू करिए। अपने क्षेत्र में उसे लागू करेंगे तो आप ही को उसका लाभ होगा। अगर आप नहीं करना चाहेंगे, तो हमारे मंत्रीगण जाकर उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर लेंगे। हम लोग चाहेंगे की आप लोग यह सब करना चाहेंगे तो अच्छा होगा। इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए और प्रदेश के विकास के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और इस दिशा में बेहतर प्रयास प्रदेश के अंदर किया गया है। महोदय, चूंकि इसी सप्ताह हम लोग यूपीकोका पर चर्चा करेंगे, तो उस दिन हम लोग कानून-व्यवस्था पर विस्तृत ब्यौरा रखेंगे। लेकिन प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से चोटी के उद्योगपतियों ने और दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में जो विचार रखे हैं वह प्रदेश के परसेपशन को प्रदर्शित करता है कि प्रदेश में व्यापक सुधार हुआ है और व्यापक सुधार की उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश के अंदर बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है। इसलिए कानून-व्यवस्था के बारे में जो चीजें हैं, वह सामने आ चुकी हैं। उस पर भी हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। डार्क जोन के बारे में, जो प्रदेश के अंदर 172 विकास खण्ड थे, नलकूप के कनेक्शन नहीं मिलते थे। सन् 1994 में एक शासनादेश जारी कर दिया गया उसके बाद से ये बंद हो गया। तब संभवतः आप माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी सत्ता में थे या नहीं थे।(नहीं थे) माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस समय 194 डार्क जोन पर कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी। (श्री पारसनाथ यादव का कुछ बोलने का प्रयास करने पर) यह किसानों के लिए नहीं था। यह उन उद्योगों के लिए था जिनमें जल की खपत ज्यादा होती है जैसे पेप्सी है, कोला है, ये जो उद्योग लगाए जाते हैं उनमें व्यापक पैमाने पर जल की आवश्यकता होती है। इन डार्क जोनों में उन उद्योगों को न लगाने की बात थी। ये उसके लिए नहीं था कि आप किसानों को नलकूप के कनेक्शन ही न दें। मशीन चलाने के लिए कोई रोक नहीं थी, मैंने पूरा शासनादेश देखा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि 1994 में दिए गए एक गलत आदेश ने प्रदेश के 172 विकास खण्डों के किसानों को पूरी तरह से तबाह-सा कर दिया। डीजल से वह चलाता था, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता था। ट्यूबवेल पर रोक लगे, ऐसी बात नहीं है। वह डीजल से चलाता था और पम्पिंग सेट डीजल से चलाने पर उसको 25रू0 प्रति यूनिट पड़ता था और बिजली से 80 पैसे से कम उसे पड़ जाता था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने उन क्षेत्रों में भी विद्युत के कनेक्शन सभी लोगों को उपलब्ध करवाए हैं क्योंकि किसान उसके दायरे में नहीं आता था और किसानों की बात करने वाले, बड़ी-बड़ी ढींगे हांकने वाले लोग कहते थे कि हम किसानों के हितैषी हैं। उन क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने अपनी योजना लागू की और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर बहुत कुछ कार्य इस दौरान हुआ है, हो रहा है और आगे होने जा रहा है। महोदय, तीन सिटी में हम लोग मेट्रो लेकर आ रहे हैं, तीन सिटी में तत्काल मेट्रो की कार्य-योजना स्वीकृत करने के लिए हम लोग भारत सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं उसकी डीपीआर बना चुके हैं। कानपुर, आगरा और मेरठ में 33 हजार करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। हम लोग इस कार्य-योजना को तत्काल लागू करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ इन कार्यों के साथ अपने आपको जोड़ रही है साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि विभिन्न योजनाओं में जो कार्य हमारे यहाँ हुए हैं, 01 लाख 60 हजार किलोमीटर सड़कों

को गड्ढा-मुक्त करने के बाद नवीनीकरण की कार्यवाही हमारी प्रारम्भ हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर अन्य कार्य-योजनाओं को भी लागू करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारम्भ किया है। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ चेक आए हैं, महोदय, मैं देख करके यह ताज्जुब करता हूँ कि यह 2015-16 के हैं और 2015-16 के जो चेक हैं, उस समय आपकी ही सरकार थी और बलिया जिले के ही हैं और किसी जिले के नहीं हैं, बलिया के हैं और सिकन्दरपुर तहसील से जुड़े हुए हैं, उसमें किसानों को जो मुआवजा मिलना था तो किसानों को जो उस समय मुआवजा मिलता, उसमें पहले यह हुआ कि इनको बेयरर चेक दे दिए जायें और बेयरर चेक की जो कीमत थी, वह थी 7038/- रूपये, 7038/- रूपये का वह चेक था लेकिन जब इसमें कहा गया कि जो भी पेमेंट होगा, वह एकाउण्ट पेयी होगा और आर0टी0जी0एस0 से उसके एकाउण्ट में भेजिए, उसको काट करके फिर 3600/- रूपये कर दिया गया। यानी इसका मतलब वह 7038/- रूपया उस किसान को नहीं मिलता, वह कुछ लोगों को मिलता, किसी पार्टी के वर्कर्स को मिलता और इस प्रकार के 01 नहीं, 03-03 चेक मेरे पास हैं, हम इसकी जॉच भी करवायेंगे, यह हर जिले में हुआ होगा। यह प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है, प्रदेश के किसानों के साथ, प्रदेश के गरीबों के साथ और उन किसानों के साथ किस प्रकार का अन्याय होता रहा है कि अगर आप बेयरर चेक देंगे तो उसमें एमाउण्ट ज्यादा होगा, लेकिन जब भारत सरकार ने कहा कि नहीं, कोई भी पेमेण्ट होगा, मुआवजा होगा, वह मुआवजे की राशि किसान के एकाउण्ट में सीधे जानी चाहिए, यह डी0वी0टी0 के माध्यम से होना चाहिए, आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से होना चाहिए तो अब उसकी राशि काट करके आधी कर दी गयी और यह लगातार इस प्रकार की स्थिति हुई है, यह हर किसान के साथ हुई है। प्रदेश के अन्दर शोषण का एक नया ताण्डव इन लोगों ने शुरू किया था, वे लोग आज यहॉ पर शराफत और ईमानदारी का पाठ हम लोगों को सिखाने आते हैं और इसलिए महोदय, आज के इस अवसर पर जो विभिन्न विभागों ने एक वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है, उसको और भी बेहतर करने की दिशा में हमारी यह सरकार और हमारे सभी माननीय मंत्रीगण पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के अन्दर वित्तीय अनुशासन को बनाये रखते हुए, प्रदेश के हर तबके के लोगों के लिए अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ । (मेजें थपथपाई गईं) जिस दिन इन्होंने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया था, देश के अन्दर की जो टॉप की 03 न्यूज थीं और जिसमें सबसे अच्छे रिएक्शन थे, उनमें से उत्तर प्रदेश का बजट भी था। (मेजें थपथपाई गईं) बिना भेदभाव के यह कार्य सरकार कर रही है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ, मुझे केवल दो मुद्दों पर इस बात को कहना है। हम लोगों ने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर एक एण्टी करप्शन पोर्टल का गठन किया है और मैं चाहूँगा कि करप्शन के मुद्दे पर सरकार ने जीरो टॉलरेन्स की जिस नीति के तहत् कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, हम लोग इस बात को देखें, बार-बार कहने के बावजूद भी क्योंकि पुराने जो संस्कार हैं, वह अचानक जायेंगे नहीं, उनको दुरूस्त करने के लिए, शोधन करने के लिए नयी प्रक्रिया के तहत् यह एण्टी करप्शन पोर्टल हम लोग लॉच कर चुके हैं।

कहीं भी कोई ऐसी वारादात होती है, उसकी वीडियो, उसकी आडियो उससे जुड़े हुए कोई प्रमाण दें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार करप्शन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ हमारी सरकार पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी। प्रदेश की जनता का सुरक्षा का वायदा देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और सुशासन के मन्त्र को सबका साथ और सबके विकास के अभियान के

साथ लागू करना चाहती है। साथ ही साथ एक अन्य जो मुद्दा आता है वह है अक्सर हमारे माननीय सदस्य इसकी चर्चा करते हैं, मोरंग, बालू और गिट्टी के दाम पर बोलते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि यह समस्यायें किसने पैदा कीं हैं क्योंकि इस समस्या को मैं तो बार-बार पिछली बार भी कहा था कि प्रदेश के अन्दर खनन से जितनी आय नहीं होती थी उससे ज्यादा आपके खनन मंत्री की आय हुआ करती थी। यह प्रदेश की सच्चाई है, वास्तविकता है और अध्यक्ष जी मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार तमाम अवरोधों के बावजूद क्योंकि प्रदेश की छवि ही ऐसी बना दी थी, कभी हाईकोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट कभी एन0जी0टी0 यह लगातार इसको अवरूद्ध, उसमें उनके स्टे होते थे, उनकी रोक होती थी उन सबके बावजूद हम लोग अब तक पिछले वर्ष प्रदेश की जितनी आय थी उसकी लगभग दुगुनी आय प्रदेश की हो चुकी है और हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक खनन चाहें वह बालू हो, मोरंग हो, गिट्टी हो उसका दाम 2016 के दाम से कम होते हुए दिखाई देने चाहिए, किसी भी स्थिति में हम इसको प्रदेश के अन्दर लागू करने जा रहे हैं। इस बात को हम पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अन्दर लागू करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर हो सकता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए कुछ मित्रों को सरकार की उपलब्धियां अच्छी नहीं लग रही होंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सरकार अच्छा कार्य करेगी तो कहीं ऐसा न हो कि फिर बाद में बेरोजगारी की नौबत आ जाये और मुझे लगता है कि गलत फहमी के शिकार न हों। इस बात को देखें हम लोग तो केवल एक बात कह सकते हैं कि -

"चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है"

(सत्ता पक्ष द्वारा वाह-वाह की आवाजें)

और मैं इसी के साथ ही अपने वित्त मंत्री जी को प्रदेष के हर तबके को ध्यान में रखकर एक बेहतर बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ प्रदेश के अन्दर प्रदेश की जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं सभी पक्षों से अपील करूंगा कि इस बजट को पास कराने में वह सभी लोग अपना सहयोग करें, जिससे समय पर इस बजट को हम जारी भी कर सकें और अगले वर्ष जब हम लोग नया बजट प्रस्तुत करेंगे तब तक जो आज मैंने 97 फीसदी, 98 फीसदी या 99 फीसदी की बात की है तब हम लोग आयेंगे तो 100 फीसदी बजट हमारा जनता के हित में प्रदेश के विकास में खर्च हो सके, आपने भी बड़ी सौहार्दता के साथ बड़ी उदारता के साथ मुझे समय दिया, बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाये गये)

(श्री राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो स्पष्टीकरण नहीं होता है, आप तो वित्त मंत्री जी से पूछेंगे।

[1:58] श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं उनसे तो स्पष्टीकरण होगा, लेकिन नेता सदन बोले हैं और बिल्कुल असत्य बोलें हैं जिसका कोई सत्य से लगाव ही नहीं है। जो माननीय अखिलेश यादव के शासन काल के कार्य थे, उसी

को अपना कार्य बता रहे हैं। हमारा काम शुरू हुआ था, अधूरा रह गया था उसी के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि क्षेत्र नहीं जाते हैं, यह बात नेता सदन ने सही कहा, जो इन्होंने आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप पर आरोप किसी ने नहीं लगाया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिस दिन आग लगी थी हमारे क्षेत्र में मैं संजोग से माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में था (हंसी) और जब हमको पता लगा तो हमने डी0एम0, एस0डी0एम0 और तहसीलदार और अपने भाई और अपने बेटे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाकर के सारी मदद की और एक दूसरी बात इन्होंने की। कि जब बाढ़ के क्षेत्र में हमारे यहां गए थे तो मैं इनके साथ नहीं था। मैं उसमें का मंत्री रहा हूँ, मैं वो राजनीति करने वाला आदमी हूं। जो जनता के दुःख दर्द में साथ रहता है। ये हमारे क्षेत्र में थे दूसरी तरफ और मैं था अपने क्षेत्र में दूसरी तरफ जहॉ दौड़-भाग करके लोग गिर रहे थे, लोग अपने सामान को ले लेकर भाग रहे थे, मैं नॉव में बैठकर के देख रहा था और ये देखने तक नहीं गए कि वहां कैसा कट रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने असत्य प्रलाप किया है और सदन की गरिमा को इन्होंने गिराया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ये भूल जाते हैं कि ये यही कह चुके हैं कि ये कलयुग है। माननीय अध्यक्ष जी, नेता विपक्ष को माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि पहली बार इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जितना विश्वास पूरे देश के लोगों ने व्यक्त किया मान्यवर, और वो काम जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 और 22 फरवरी को यहां पर इन्वेस्टर समिट करने के बाद जो लांच किया था वो पूरी तरीके से अंजाम पाने जा रहा है मान्यवर, और जैसा कि कहा गया कि 25 हजार करोड़ के जो एम0ओ0यू0 थे उसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया है। मान्यवर डिफेन्स कोरिडोर उसी आधार पर मिला मान्यवर, रेलवे का जो कारखाना है उसी आधार पर मिला। मान्यवर, और मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल को बजाए इसके जो खड़े होकर के अपना बंदरबांट करने लगे उनको ये बधाई देना चाहिए अपने मुख्य मंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में यह सब हुआ बधाई देना भूल गए। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी को ये बधाई दे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं बधाई ही दे रहा हूँ मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई, कि जो पांच साल में हमारे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने काम किया। उसी को वो अपना काम बता रहे हैं, क्योंकि अपने एक साल में अपने बजट से एक भी काम शुरू नहीं किया। आगे आपने जो कहा था कर्ज माफी में जो सिकन्दरपुर का दिखलाया। ये तो आपके ही कर्ज माफी में 3 रुपया, 4 रूपया मिला। कोई भी बात कहते हैं तो कहते हैं कि पहली बार यहां माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे क्या उन्होंने कुछ नहीं किया, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे कुछ नहीं किया, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया, माननीय अखिलेश जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आपने किया, क्योंकि आप इस सदन में पहली बार यहां आए हैं। इसलिए सदन में पहली दफा की बात कहते हैं इसलिए कि इनको पीछे के मुख्य मंत्रियों के काम की जानकारी तो है नहीं न पढ़ते हैं और न लिखते हैं, केवल पूजा-पाठ या भाषण। जब पूजा-पाठ करते हैं तो भाषण

सत्य होना चाहिए। जितना भी मुख्य मंत्री जी ने बोला है सब असत्य पर आधारित बात इन्होंने कहा है।

फतेह बहादुर बाबू, पूजा-पाठ मैं खुद करता हूँ । आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, जब तक जिन्दगी रहेगी, तब तक पूजा-पाठ करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द जी, आप इधर बोलिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

लेकिन ऐसा पूजा-पाठ नहीं, असली ईश्वर में विश्वास करने वाला पूजा-पाठ करूँगा।

श्री फतेह बहादुर-

लेकिन नेता सदन मत कहिए, अलग से कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब नेता विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं होता है तो ये एक ही राग अलापने लगते हैं ताकि जब कल के अखबार की खबर छपे तो ये कुछ कह सकें और कम से कम जाकर दिखा सकें। यह अपने नम्बर बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं।

[02:05] श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के डा0 कमल मलिक जी अपनी बात 5 मिनट में कहें।

श्री कमल सिंह मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बजट सत्र में बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मा0 वित्त मंत्री जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार के सभी मा0 मंत्रीगण को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा है। यह बजट उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए बनाया गया है। यह बजट सभी वर्गों के हितों के लिए बना है। चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे प्रदेश का मजदूर हो, चाहे प्रदेश का गरीब हो, चाहे प्रदेश का दलित हो, चाहे प्रदेश का अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो। यह सारे वर्गों के हितों का बजट है। हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से हमारे मा0 नेता सदन और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोग प्रत्येक बेरोजगार के लिए योजना लेकर आए हैं। हम प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार देंगे। हमारी सरकार ने यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट, 2018 आयोजित करके प्रदेश की खुशहाली का काम किया है। मेरे सामने बैठे हुए हमारे अति सम्मानित मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य साथियों ने इसका विरोध किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रतिपक्ष का धर्म है कि वह सत्ता पक्ष के समक्ष वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करे। हम उनका सम्मान करते हैं। वैसे भी स्वस्थ लोकतन्त्र की कल्पना बिना प्रतिपक्ष के नहीं की जा सकती। मैं हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर तहसील से आता हूँ । गढ़मुक्तेश्वर मेरा विधान सभा क्षेत्र है। जैसा उसके नाम से ही विदित है और मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम आने से ही सृष्टि के आदिकाल का इतिहास हमारे सामने आ जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह वह स्थान है जहाँ सृष्टि के आदिकाल में भगवान शंकर के गणों की मुक्ति, सगर के पुत्रों की मुक्ति हुई थी। मेरा विधान सभा क्षेत्र एन0सी0आर0 क्षेत्र में होते हुए भी वह कृषि बहुल क्षेत्रों में आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के

90 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है लेकिन मेरे यहाँ एक सिम्भावली शुगर मिल है। वहाँ के भ्रष्ट तन्त्र के द्वारा हमारे किसानों का कई बार शोषण भी होता है। मैं अपने मा0 गन्ना मंत्री जी से कहूँगा कि जहाँ आज प्रदेश की सभी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं। मेरी मिल का पेमेण्ट बहुत पीछे है। सरकार इसकी चिन्ता करके, उन पर कार्रवाई करके हमारे गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान दिलाया जाए। आज जहाँ गन्ना किसानों का रकबा 30-35 परसेण्ट बढ़ा है, आज जहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज लगभग 70-80 परसेण्ट बढ़ी है तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि मेरे यहाँ गंगा और यमुना के दोआबे की भूमि के कारण गन्ना बहुत होता है। हमारे यहाँ गन्ने का वर्तमान सीजन बहुत टफ सीजन है, आने वाला सीजन और टफ होगा। मैं सरकार से और मा0 गन्ना मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ गन्ने की एक और मिल लगाने की कृपा करें। मेरा विधान सभा क्षेत्र एन0सी0आर0 में होते हुए मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ है। आज हम अगर एन0सी0आर0 से जुड़े उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को देखेंगे और एन0सी0आर0 क्षेत्र के हरियाणा क्षेत्र को देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ विकास की नयी योजनाएँ लेकर आए मैं इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों को जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है तथा अपने सभी माननीय मंत्रीगण का और उनके विभागों के सभी कर्मचारियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ । जिनके कारण से हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता में यश मिला है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को सरकार को जिन्होंने हमारी पहचान गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लगाया जाने वाला जो धार्मिक मेला था जिसे भगवान कृष्ण के कार्यकाल में जिसे प्रारम्भ किया गया। मान्यवर, जिस पहचान को लेकर हम प्रत्येक सरकार में प्रमाणित कराने के लिए घूमते थे। हमारी उस पहचान को राष्ट्रीय मेला घोषित करने का काम किया है मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन्होंने हमें हमारे जरा सा आग्रह पर गढ़मुक्तेश्वर के अंदर जहाँ पर पूर्व में कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी 50-50 किलोमीटर तक कहीं भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए जाना पड़ता था। आज उन्होंने हमें उच्च स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए ट्रामा सेन्टर देने का काम किया है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऊर्जा मंत्री जी को, उच्च शिक्षा मंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और गढ़मुक्तेश्वर को भी उसमें शामिल किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, 5 मिनट का समय दिया था आप 8 मिनट बोल गए हैं।

डॉ0 कमल सिंह मलिक-

मान्यवर, एक मिनट के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को व सरकार को जिन्होंने हमारी वैश्विक वैदिक पहचान को पुख्ता करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर को वैदिक सिटी बनाने का निर्णय लिया है। मान्यवर, मैं ऐसी सरकार को, इस सदन को सब को जिन्होंने मुझे धैर्य से सुना उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ । एक श्लोक के माध्यम से इस बजट के सार को आपके सामने रखना चाहता हूँ । इस बजट का सार है :-

''सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।'' भारत माता की जय हो।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें नेता विरोधी दल आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी के द्वारा रखे गये बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत, आभारी हैं। मान्यवर, जैसा कि शुरूआत में ही बजट पर चर्चा करते हुए माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि यह बजट किसान विरोधी है, यह बजट नौजवान विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित विरोधी है। मान्यवर, पूरा प्रदेश टकटकी नजरों से देख रहा था जब उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित के लिए माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश की नजर थी कि बजट में कुछ न कुछ इस तरह की योजनायें संचालित करने का प्राविधान होगा जिससे गॉव, गरीबों में खुशहाली आएगी लेकिन मान्यवर, इस बजट से पूरी तौर पर निराशा ही हाथ लगी। हम लोग सोचते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गॉव, गरीब और किसान तथा महिलाओं को समाजवादी पेंशन देकर उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं के लिए काम किया था हम सब की नजर थी कि माननीय योगी जी की सरकार उस समाजवादी पेंशन को लागू करने का काम करेगी लेकिन मान्यवर, समाजवादी पेंशन का कोई जिक्र नहीं आया और इतना ही नहीं मान्यवर, यहॉ जितने माननीय विधायक आए हैं सब गॉव से आते हैं आज बड़ी तेजी से पूर्वांचल के जनपदों में गंभीर बीमारियॉ कैंसर और किडनी से लेकर लीवर सिरोसिस (इसी मध्य 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुये) आदि बीमारियॉ फैल रहीं हैं। आज गरीब इलाज के लिए बड़े-बड़े कालेज और आयुर्विज्ञान संस्थान में जाता है और वहॉ का संस्थान उसे 3 लाख, 5 लाख का इस्टीमेट प्रस्तुत करता है। मान्यवर, जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अगर 5 लाख का के0जी0एम0सी0 का या संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान का इस्टीमेट था तो पूरा का पूरा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार इस्टीमेट के सापेक्ष धन स्वीकृत करने का काम करती थी लेकिन यहॉ बड़ी-बड़ी बातें कीं गई, गरीब की बातें की गयीं लेकिन आप खुद देख लें यह हमारा बजट है जो इलाज के लिए सरकार को देना चाहिए जिस गरीब के पास कहीं पर भी पैसे का इंतजाम नहीं है आज इस बजट में सरकार ने कहीं पर कोई प्रस्ताव नहीं किया है। आज बड़े जोर-जोर से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गरीब कन्याओं की पढ़ाई के रास्ते बनाने के लिए कन्या विद्या धन योजना का प्रावधान किया था। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर असेवित विद्यालय बनाने का काम हो, चाहे कन्या विद्या धन के माध्यम से बड़ी तेजी से ग्रामीण शिक्षा में जागरूकता पैदा करने का काम हो लेकिन आज इनकी सरकार में कहीं पर भी कन्या विद्या धन जैसी योजना आज संचालित करने का काम नहीं हो रहा है। एक तरफ आप डिजीटल इण्डिया की बात करते हैं आप हिन्दुस्तान की तरक्की, उत्तर प्रदेश की खुशहाली की बात करते हैं वहीं पर दूसरी तरफ किसान के बेटे के हाथ में कैसे लैपटॉप आये, आपने अपने संकल्प-पत्र में कहा था कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होगी तो आप गरीब किसान के बेटे को लैपटॉप देने का काम करेंगे। आज आप अपने संकल्प से पूरी तौर पर मुकर गए हैं, आप अपने संकल्प-पत्र के वादे से मुकर गए हैं, एक साल हो गया, किसान के बेटे और बेटियों को, गांव में पढ़ने वाले लोगों को आपने कहीं पर लैपटाप देने का काम नहीं किया। आप कौशल विकास की बात करते हैं, आप हुनरमंद नौजवान तैयार करने की बात करते हैं आपने उस दिशा में कौन-सा काम किया? अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, मुख्य मंत्री जी के बोलने में

पूरी हताशा झलक रही थी, निराशा थी बात-बात पर हमारे नेता विरोधी दल के सही कहे हुए शब्दों पर वह आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। क्या आप इतिहास के पन्नों से उसको मिटा सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया, हिंदुस्तान का इतिहास का सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे बनाकर के माननीय अखिलेश यादव ने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था। यह बात हम नहीं कहते यह बात को पूरा देश स्वीकार करता है कि वह ऐसा एक्सप्रेस-वे था जिसमें आज देश का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान का वहीं पर अभ्यास हुआ। पूरा का पूरा देश और उत्तर प्रदेश उसका साक्षी बना था। आप इन्वेस्टर्स समिट की बात करते हैं आज इस इन्वेस्टर्स समिट में जो महिन्द्रा कंपनी के मालिक थे उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को राज्य की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता उत्तर प्रदेश को एक देश के समान देखा जा सकता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स में बोलते-बोलते कहा था कि उत्तर प्रदेश से मेरी मां आती है, उत्तर प्रदेश से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और उत्तर प्रदेश को मैं इसलिए बहुत चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश दुनिया का और देश का एक ऐसा राज्य है जहां 100 नम्बर की सेवा संचालित है यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने करने का काम किया था। यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने 100 नम्बर की सुविधा दी थी। कोटक महिन्द्रा से लेकर के एच0सी0एल0 के शिव नादर ने जो हमारे संस्थान बन रहे हैं जो आई0टी0 संस्थान बन रहा है, इतना ही नहीं जो डॉ0 त्रेहान ने हमारे इसी लखनऊ के अंदर सबसे बड़ा मेदांता अवध भी बनाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। मान्यवर, कैंसर संस्थान हो, या किसानों के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब कोई किसान खेत में काम करते-करते किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव की सरकार ऐसे किसान को पांच लाख रूपये आर्थिक सहायता देने का काम कर रही थी। हम सोचते थे कि आप पिछड़ो के लिए, दलितों के लिए, छात्र और नौजवानों के लिए आप कोई योजनाएं लाएंगे लेकिन मान्यवर, इनके बजट में कहीं कोई इस तरह की योजना नहीं है। हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल ने सही कहा कि पूरा का पूरा प्रवचन है, हताशा है, निराशा है और बात-बात पर नेता सदन को इतनी जल्दी धैर्यता नहीं खो देनी चाहिए। बात-बात पर कहते हैं कि हम जांच कराएंगे हम तो चाहते हैं कि जांच हो, आप कब तक जाति विशेष के नाम पर हमको कोसते रहेंगे आप कौन-सी बातें आकर सदन के अंदर कहते हैं। आपकी देश की सरकार 4 साल की हो गयी आप तो टू-जी स्पैक्ट्रम की भी जांच करा रहे थे, मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो आरोपी थे आज वह बाइज्जत बरी हो गए आप कौन-सी जांच करा रहे हैं। आपके राज में पूरे देश ने देखा अब तो छोटी-मोटी डकैती की बात कहां है बड़े-बड़े बैंक लूटने वाले आज देश से फरार हो जा रहे हैं यह आपकी व्यवस्था है। आज पूरे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, आपके एम0एल0ए0 से लेकर सब जानते हैं, बातें जब होती हैं मान्यवर, तहसीलों का भ्रष्टाचार, थानों का भ्रष्टाचार हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार न फैला हो। किसानों के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादवजी ने नहरों का पानी फ्री किया था। अभी एक नेता बोल रही थीं कि हमें तकलीफ होती है कि इटावा को माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। अरे अभी आपको पहली बार सदन में आने का अवसर मिला है, आप किस पर क्या बात बोल रही हैं। बोलते-बोलते आप कहां भूल जा रही हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का इस देश के अन्दर लोकतंत्र और देश की सेवा में बहुत बड़ा योगदान है मान्यवर और आप कहती हैं कि उनसे देश की पहचान, आपको उनके नाम से इतनी बड़ी आपत्ति है। वर्ष

1967 से लेकर के 2018-2019 चल रहा है, पूरे देश के अंदर उंगलियों पर गिने हुए लोग होंगे जो इतने बड़े अनुभव के नेता होंगे, उनका देश की सेवा में इतना बड़ा योगदान होगा। मान्यवर, आज पूरी तरह से हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। अगर नेता विरोधी दल की बात पहले ही बजट सत्र में मान ली गयी होती तो आज देश आपको आइने में न दिखता। नेता विरोधी दल बार-बार कहते थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून नहीं जंगलराज में तब्दील हो गया है, हताशा है, निराशा है जनता में। आप हमारे नेता विरोधी दल का माखौल उड़ाते थे, लेकिन जब फूलपुर और गोरखपुर का परिणाम आ गया तब पूरे देश ने देख लिया कि आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी कहां है। आप इंतजार करिये 2019 का। आप कहते हैं कि एक साल नई मिसाल। हम जैसे लोग और उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि एक साल में आप की बुझ गई मशाल। अब आपके पास कुछ कहने के लिए और करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आज उत्तर प्रदेश में उप चुनाव हुआ। उस उप चुनाव में जनता का जनादेश आ चुका है। गोरखपुर का जनादेश आ चुका, फूलपुर इलाहाबाद का जनादेश आ चुका। आज जनता बदलाव के रास्ते पर चली गयी है। इतनी जल्दी एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने जनता का इतना विश्वास नहीं खोया था, जितना बड़ा विश्वास योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्दर खोने का काम किया है। आज नौजवान को रोजगार नहीं, आप बार-बार कहते हैं कि जांच करायेंगे, आप क्यों नहीं यू0पी0एस0सी0 की जांच कराते, कौन रोक रहा है आपको जांच कराने से। आपकी दिल्ली में सरकार और उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार है। जांच करानी है तो आप गड्ढा मुक्त सड़कों की जांच करा लीजिए। आप के डिप्टी सी0एम0 को इलाहाबाद में टहलने नहीं दे रहे थे लोग। आपके डिप्टी सी0एम0 जिस रास्ते से जाते थे रास्ता रोक लेते थे नौजवान। जहां आपके डिप्टी सी0एम0 सभा करते थे उन पर नौजवान हमलावर होकर के अपनी बात रखने का काम कर रहा था। आज पूरी तौर पर नौजवान आपकी सरकार में घुटन महसूस कर रहा है। आज आपने रोजगार के रास्ते बन्द कर दिये हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आप जांच कराइये, गठन से लेकर अब तक जांच करा लीजिये और बताइये कौन-कौन जाति के लोग कब-कब अध्यक्ष बने, उन जातियों के अध्यक्षों के कार्यकाल में किन-किन जातियों की नियुक्ति हुई। मान्यवर, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। पूरा का पूरा पता हो चुका है। हर एक जांच के नाम पर केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। इनकी पूरी की पूरी पोल मान्यवर खुल चुकी है। जनता याद कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को।

मान्यवर, बस दो मिनट। प्रदेश के अन्दर माननीय अखिलेश यादव जी ने 200 बेड अस्पताल बनाने का कार्य किया था। लेकिन मान्यवर, हमने पिछले बजट भाषण में अनुरोध किया था स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वह अस्पताल किसी पार्टी का अस्पताल नहीं है, वो जनता के हित के लिए अस्पताल है। मान्यवर, हमने अनुरोध किया था उस अस्पताल को सुचारू रूप से संचालन के लिए, लेकिन किसी भी डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो पायी है, एक साल सरकार को बीत गया है। हमने अनुरोध किया था कि हमारे क्षेत्र के अन्दर डिग्री कॉलेज है। बिल्डिंग बनते-बनते इतना समय हो गया, उस कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए हमने अनुरोध किया था, लेकिन प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पायी है। आज तक एक भी काम इस एक साल की सरकार में नहीं हो पाया है मान्यवर।

आज सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है । अगर रत्ती भर इस सरकार में लिहाज होता तो इस अकड़ता के साथ यहॉ मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं होता बल्कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके निश्चित तौर पर जनता के कल्याण के लिये, किसानों के कल्याण के लिये कुछ योजनायें चलतीं । हम अपनी बात को अपने नेता विरोधी दल माननीय राम गोविन्द चौधरी की बात से जोड़ते हुये कहना चाहता हूँ कि इनका बजट बजट नहीं है, बल्कि यह चूँ-चूँ का मुरब्बा है, किसानों के साथ छलावा है, नौजवानों के साथ छलावा है और पूरी तरह से इनके बजट से उत्तर प्रदेश में उदासीनता का माहौल बना है नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सरकार पूरी तरह मौन है और जॉच के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है । इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के कथन से अपने को सम्बद्ध करते हुये इस कटौती प्रस्ताव को बल देता हूँ और आपने बोलने का समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूँगी कि मौजूदा सरकार द्वारा जो बजट पेश हुआ है, उस पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया। इस बजट पर जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि यह चूँ-चूँ का मुरब्बा है मैं यही कहना चाहूँगी उस बात को बल देते हुये, कि जिस तरह से यह बजट पेश किया गया तो इस बजट में कहा गया इस सरकार के द्वारा भी कई बार कहा गया कि यह सरकार महिलाओं के लिये उनकी सुरक्षा के लिये कटिबद्ध है । शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिये कटिबद्ध है। किसानों के प्रति उनकी भलाई के लिये कटिबद्ध है लेकिन यदि हकीकत में देखा जाय तो यह सरकार जब आती है और जब बजट इनका पेश होता है, इनका एक बजट पहले भी पेश हो चुका है, उस बजट का पैसा पूरी तरह खर्च नहीं होता है तब तक पता चलता है कि दूसरा बजट आ गया । इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी तरह से जनता को जिस तरह यह बजट झूठ का पुलिन्दा है उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है । मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलावा और मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता हासिल की है उसी तरीके से यह सरकार इस सदन में भी जो कहते हैं कि हम महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा करने वाले हैं और इसी सदन में पहली बार सत्ता हासिल करने के बाद सरकार का बजट जब पेश हुआ था और जब सदन चला तो यहीं के एक माननीय विधायक की जुबान फिसल जाती है तो कहॉ यह बात सार्थक होती है कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले हैं । मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की बात करने वालों को यह शोभा नहीं देता क्योंकि अगर यह सरकार महिलाओं की हितैषी होती तो निश्चित तौर से जो हमारी पूर्व की माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में महिलाओं के लिये समाजवादी पेंशन थी जिससे कि महिलायें सुदृढ़ हो सकें, जिससे कि वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें । अगर यह वाकई में महिलाओं की हितैषी सरकार होती तो समाजवादी पेंशन को मिटाने और उसे रोकने का काम नहीं करती । मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको समाजवादियों के नाम से इतनी ही आपत्ति है तो आप उसका नाम बदल देते, उसका नाम परिवर्तित कर देते तो मैं भी समझती कि हॉ आप कहीं न कहीं महिलाओं के हितैषी हैं । पर यहॉ पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस योजना को ही खत्म कर दिया । आये दिन हम अखबारों और टी0वी0 चैनलों के माध्यम से यह देखते हैं और यह जानकारी हासिल होती है कि आज प्रदेश के इस हिस्से में कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार और

दुष्कर्म जैसे काम हो रहे हैं, मासूम बच्चियों को इसका निशाना बनाया जा रहा है, कानून व्यवस्था के नाम पर यह सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है । कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती हम लोगों को आये दिन टी.बी. चैनलों और अखबारों के माध्यम से जो जानकारी हासिल हो रही है, वह नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक, अब समाप्त करें।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

दो मिनट अधिष्ठाता जी, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि किसानों की हितैषी अपने आपको जो सरकार कहती है, यह कहीं से किसानों की हितैषी नहीं है क्योंकि ऋण माफी के नाम पर भी यहाँ किसानों को छलने का काम किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

पिंकी जी आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठें।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ । कि आपने मुझे वर्ष 2018-19 के बजट पर अपना विचार रखने का मौका दिया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2018-19 का जन-कल्याणकारी बजट माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद व बधाई देती हूँ। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित और विकासपरक बजट है जो सभी वर्गों और प्रदेश के चौमुखी विकास पर दृढ़ संकल्पित है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व की सरकारों में अकर्मण्यता के कारण उत्तर प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा था। परन्तु आज मुख्य मंत्री योगी जी व वित्त मंत्री जी के सफल एवं संगठित प्रयास से प्रदेश को एक विकासोन्मुखी बजट मिला है, जिससे प्रदेश के विकास के रथ को पुनः एक बार गति देने का कार्य किया गया है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2018-19 का बजट चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सिंचाई हो, बिजली हो, मेट्रो हो, सड़क हो, लघु एवं मध्यम उद्योग हो, चाहे वह किसान हो, देश का कर्णधार युवा वर्ग हो, कन्या हो या फिर विधवा महिला हो, दिव्यांगजन के उत्थान की बात हो या फिर गरीबों के आवास और शौचालय की बात हो, इन सभी को 2018-19 के बजट में एक अच्छी धनराशि व योजना के साथ इनके सफल क्रियान्वयन करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और श्रम मंत्री, आदरणीय मौर्या जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से अब न केवल गरीब की कन्या का सामूहिक विवाह होगा, चाहे वह किसी धर्म और मजहब की हो बल्कि प्रदेश में जितने भी रजिस्टर्ड लेबर हैं उनके भी पुत्र और पुत्रियों का सामूहिक विवाह कराने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, वह अत्यन्त ही सराहनीय है।

श्री अधिष्ठाता-

डॉक्टर साहब, बैठिये।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह सभी बातें दर्शाती हैं कि यह बजट कितना संवेदनशील और आम जनमानस की पीड़ा के करीब है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र की दो समस्यायें बताती हूँ ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिए।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

जी, मान्यवर, मैं मिर्जापुर जनपद की मझवॉ विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लिये सिंचाई हेतु पहाड़ी ब्लाक के दाती ग्राम सभा में अपरखजुरी से जमतुआ बंधी को जाने वाली नहर में से एक माइनर का कार्य 1988 में शुरू किया गया था। यह चार कि0मी0 का माइनर है, इसमें दो कि0मी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन दो कि0मी0 कार्य अभी भी बाकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ । कि इस कार्य को पूर्ण करा करके रामदाती, बंधुआ, गौरा, गोपालपुर, मदनपुर आदि गॉवों में सिंचाई के लिये पानी दिलाने का कार्य करें, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब मा0 सदस्य रत्नाकर मिश्र जी।

श्री रत्नाकर मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जैसे हुये हैं, और प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे हुये हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हुये हैं, एक दिन भी उनकी मॉ सरकारी बंगले में नहीं गई और न ही उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग किया, उसी छोटे से कमरे में आज भी उनकी मॉ जीवन व्यतीत कर रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता अपने परिवार को नहीं दी। ऐसे संत महापुरूष युगों के बाद पाये जाते हैं। यह हम लोगों का सौभग्य है। आज जो सपा-बसपा का गठबंधन हुआ है, बहन मायावती के साथ तो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भाई का फर्ज निभाया, उनको मुख्य मंत्री बनाया, आज वह जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं। लेकिन उसने बहन होने का एक दिन भी फर्ज नहीं निभायी और बुआ-भतीजा बनकर सपा से गठबंधन कर लिया है। मुख्य मंत्री के द्वारा जो माननीय वित्त मंत्री, मा0 श्री राजेश अग्रवाल जी ने बजट प्रस्तुत किया है और बिजली के लिए जो बजट दिया है जिससे हर घर रोशन हो सके। यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी से ज्यादा है, जिससे किसानों को बिजली के अभाव से मुक्त करके असिंचित भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह योजना के लिये 2800 करोड़ रूपये की सहायता की गई है। सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 21 करोड़ रुपए, फसली ऋण हेतु सब्सिडी योजना के तहत् 200 करोड़ रुपए दिये। प्रयाग-कुम्भ को यादगार बनाने के लिए सरकार ने इस मद में 105 करोड़ रुपए दिये हैं। ऐसे मेले से पहले 14 शहरों को कुम्भ नगरी से हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त 100 किलोमीटर की परिधि में आने वाले प्रमुख तीर्थ स्थल भी यातायात से जोड़े जायेंगे। मा0 राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट लाया गया है इतना अच्छा बजट कभी आया नहीं था इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री रत्नाकर मिश्र-

मा0 अधिष्ठाता जी, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, माँ विन्ध्यवासिनी नगरी में विन्ध्याचल देश विदेश में विख्यात मन्दिर है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा की कटान से क्षेत्र उजड़ता जा रहा है इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि रामगंगा घाट से एस0पी0 बंगला तक गंगा के किनारे रोड बनवाने की कृपा करें, जिससे कटान भी खत्म हो जायेगा और जाम भी खत्म हो जायेगा तथा पर्यटक भी बढ़ेगा। वर्तमान सरकार का ध्यान पर्यटकों की ओर है इसलिए मैं सरकार का ध्यान पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अयोध्या, काशी, मथुरा आदि के साथ माँ विन्ध्यवासिनी धाम की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ क्योंकि उत्तराखण्ड के अलग होने के बाद प्रदेश में विन्ध्य धाम ही परिपूर्ण है, इसलिए सरकार इसे पूर्ण रूप से विकसित करे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूँ । मान्यवर, मैंने सदन में नेता विरोधी दल के भाषण को बड़ी गम्भीरता से सुना। ऐसा लगता है कि जैसे राम चरित मानस में एक चौपाई लिखी गई है वह उनके भाषण को दिखा रही है ''जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी।।'' निश्चित रूप से हमारे नेता विरोधी दल द्वारा सकारात्मक पहल होनी चाहिए थी, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ और योजनाएं आई हैं उनका गुणगान गाना चाहिए लेकिन वह उसके एवज में नकारात्मक बात करते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो साहसी कदम उठाये हैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट पेश किया है, इसके लिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूँ ।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, चूँकि कोरम पूरा नहीं है इसलिए सदन नहीं चल सकता है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मात्र 37 मेम्बर सदन में उपस्थित हैं इसलिए कोरम के अभाव में सदन नहीं चल सकता है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को और मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मद शुभारम्भ के वक्त कोरम देखा जाता है, अगर मद चलता रहता है तो कोरम की बात नहीं उठती है यह मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ ।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट जो मा0 वित्तमंत्री जी द्वारा पेश किया गया है इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं लायी गयी हैं निश्चित रूप से यह बहुत ही कल्याणकारी हैं और इससे आज प्रदेश में खुशहाली का वातावरण पैदा हो गया है। यह इस तरह का बजट आया है कि इससे लोगों में एक आशा जगी है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी इसी प्रदेश के रहने वाले थे इसलिए सभी को लगता है कि आने वाले समय में राम राज्य भी आयेगा, इस तरह का यह बजट प्रस्तुत हुआ है। 4 लाख 28 हजार

करोड़ का यह बजट है इस बजट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इसको बढ़ाया गया है, हर क्षेत्र के विकास की बात सोची गई है, सभी के कल्याण की बात सोची गई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे नेता विरोधी दल कह रहे थे कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं है। मैं आपके माध्यम से मा0 नेता विरोधी दल को भी बता देना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं और निश्चित रूप से एक व्यवस्था हमारे माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि हमारे नेता की तुलना हमारे नेता से नहीं हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके नेता जो थे वह भी टेण्डर नहीं करते थे, वह सीधे टेण्डर देते थे, सीधे ठेका देते थे और उसमें पहले से ही पता हो जाता था कि किसको ठेका मिलने वाला है और उसका पैसा पहले से ही फिक्स हो जाता था, लेकिन हमारे नेता ने इस सबको दरकिनार किया है और ई-टेण्डर की व्यवस्था को लागू किया है। ई-टेण्डर के माध्यम से साफ-सुथरी व्यवस्था है। अब कोई पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है। जनता का पैसा है अब जनता के काम में लगता है, दूसरे काम में नहीं लगता है, यह हमारे नेता का काम है। इसलिए हमारे नेता की तुलना किसी और नेता से कैसे हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने पहले जैसा कहा था उसके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मा0 राजीव गॉधी जी ने जो कहा था उसका भी संज्ञान लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि केन्द्र से एक रूपया चलता है तो वह 15 पैसा ही पहुँचता है लेकिन हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी यदि एक रूपये देते हैं तो वह एक-एक रूपया जनता तक पहुँचता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, चूंकि आज समय कम है लेकिन मैं आपसे अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूँ । हमारे क्षेत्र से लगे हुए सिकन्दरा क्षेत्र से कामराज कैनाल योजना । जिस कामराज कैनाल योजना के माध्यम से अगर उसका द्वितीय चरण चालू करा दिया जाए, तो उसके माध्यम से सिकन्दरा ही नहीं भोगिनीपुर सहित कानपुर देहात के सारे के सारे क्षेत्र में में जब पाईप लाईन के माध्यम से पानी मिले, तो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुँचाने का, निश्चित रूप से हर किसान को पानी पहुँच जायेगा। हमारा विधानसभा क्षेत्र बुंदेलखण्ड से लगा हुआ है, और यमुना की तलहटी में आता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिए, नाहिद हसन जी आप अपनी बात रखिये।

श्री विनोद कुमार कटियार-

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखण्ड विकास निधि का अगर कुछ अंश हमारी विधान सभा क्षेत्र को भी मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारी विधान सभा क्षेत्र जो 403 विधान सभाओं में सबसे पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र है, उसका भी उत्थान हो जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में

मुक्ता नगर और मूसा नगर हमारे, क्षेत्र में चपरघटा जैसे ऐसे पाँच स्थान है, भूमि सागर तालाब, जिसको पर्यटन के हिसाब से अगर डेवलप कराया जाए तो निश्चित रूप से कानपुर देहात नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि वहां पर निकलने वाली रास्तों से चाहें कलकत्ता की तरफ जाएं, चाहें लखनऊ से झांसी की तरफ जाएं, निश्चित रूप से वह बीच में पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट के समर्थन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने नेता विरोधी दल के समर्थन में जो बजट हमारे विधान सभा में पेश हुआ है उस बजट पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ । माननीय जिन योजनाओं को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में व्यर्थ बताकर वास्तव में उन व्यर्थ योजनाओं को याद कर कर-कर आज प्रदेश के गरीब किसान, युवा महिलाएं और छात्र यादकर उनको याद कर रही हैं जो हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी, सरकार ने कार्य किया था, उनको वित्तमंत्री जी ने व्यर्थ बताकर जो शेरों-शायरी के अंदाज में अपने बजट भाषण को पेश किया है, मेरे नजरिये में यह प्रतीत होता है कि पूत के पाव पालने में ही दिखने लगे हैं। बजट में शामिल किसी भी योजना से यह प्रतीत नहीं होता कि यह बजट प्रदेश की जनता को राहत पहुँचाने वाला है। यदि आज मँहगाई की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था को देख जाए तो यह बजट हमारी पूर्ववर्ती सरकार के सामने कहीं नहीं टिकता। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जैसे-जैसे मैं बजट भाषण को सुनता गया, वैसे-वैसे मुझे बजट की कमी और उनके द्वारा जनता पर उठाये जाने वाले कहर का एहसास होता गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में प्रदेश को जी0एस0टी0 व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बताते हुए इस बात का कतई कोई जिक्र नहीं किया कि जी0एस0टी0 के कारण छोटे व्यापारी, उद्योगपति व अन्य व्यापारी तथा कृषि यंत्रों पर लगी जी0एस0टी0 से परेशान किसान एवं व्यापारियों को जो परेशानी हुई उससे वित्त मंत्री जी बिल्कुल अन्जान हैं और महोदय, न ही उन्होंने किसी राहत व उपाय की घोषणा की है। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में इन्वेस्टर्स समिट को प्रदेश सरकार की एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जिसमें करोड़ों-करोड़ रुपया एड़वरटीजमेंट में लगाया गया, इस आयोजन के प्रचार-प्रसार में लगाया गया और व्यर्थ में खर्च कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, गॉवों में रहने वाली जनता का प्रदेश है। यह अच्छा होता कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स समिट के बजाय किसान समिट का आयोजन करती।

श्री अधिष्ठाता-

नाहिद हसन जी, अब समाप्त करिये।

श्री नाहिद हसन-

क्योंकि यह प्रदेश 80 प्रतिशत किसानों व किसानों से जुड़े मजदूरों का या किसानों से जुड़े व्यापारियों का प्रदेश है। माननीय अधिष्ठाता जी, वित्त मंत्री जी ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर खुद अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप अपने क्षेत्र की बात कहकर समाप्त कीजिए।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, शामली से जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जिले में 5-5 इन्काउण्टर कर दिये गये जिसमें कि 3 में जिनके ऊपर कोई केस नहीं था उन लोगों के इन्काउण्टर

किये गये। माननीय अधिष्ठाता जी, अगर उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उठाकर देखी जाए, पहली बात तो उन परिवारजनों पर दबाव बनाकर न तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जा रही है और जिन लोगों के इन्काउण्टर किये हैं उन पर 5-5, 10-10 गोलियॉं मारी गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी एक्सपर्ट है तो इनको आप ओलम्पिक में भेजिये क्योंकि रात के 12.00 बजे के अँधेरे में यह एक ही टॉंग पर 8-8, 10-10 गोलियॉं कैसे मार देते हैं या तो इनको आप ओलम्पिक में भेजिये या यहॉं पर इनको कोई न कोई पुरस्कार दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये, अभी बहुत से सदस्य बोलने के लिए हैं।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अधिष्ठाता जी, दलितों पर, पिछड़ों पर पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, दो-दो, तीन-तीन रात तक उनको थाने पर बिठाया जाता है और बोली लगाकर उनको छुड़ाया जाता है। मेरा आरोप है कि भा0ज0पा0 के समय में जिस तरीके का भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन ने किया है उस पर लगाम लगायी जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । बजट पर चर्चा आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं अपने को बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय लालजी वर्मा जी, उप नेता उमाशंकर जी से सम्बद्ध करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बजट पूर्णतया काल्पनिक है, व्यवहारिक में यह बजट जनहित में नहीं है। प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। बजट आय-व्ययक का स्रोत होता है लेकिन इस बजट में आय के स्रोत का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि अनुत्पादक कार्यों में खर्च दिखाया गया है जो जमीन पर नहीं बल्कि कागजों पर दिखायी देता है। मान्यवर, इस सरकार ने वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार, अपराधमुक्त प्रदेश बनायेंगे लेकिन यह असत्य निकला, थोथा निकला। आज भी जिले, ब्लाक, तहसीलों और थानों में भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहा है यहॉं तक कि किसी जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आमतौर पर हमारे जिले में जनता और पुलिस में टकराव की स्थिति, प्रशासन और जनता में टकराव की स्थिति हर वक्त बनी रहती है। साथ में हमारे जिले में डकैती, छिनैती, बलात्कार और लूट की घटनायें प्रतिदिन चलती रहती है और पुलिस जनता की बात को सुन भी नहीं रही है। इस तरह से यह दुःख की बात है कि हमारे जिले में जो जिला योजना की बैठक हुई थी और जो धन पास हुआ था इस बजट में उसका कोई उल्लेख भी नहीं हुआ है। सरकार ने जो वायदा किया था कि हमारी सड़कें गड्ढामुक्त होंगीं जब कि हमारे जिले में मात्र 20 परसेन्ट गड्ढामुक्त हुईं और वह भी एक महीने के बाद फिर गड्ढा में तब्दील हो गयीं। 80 प्रतिशत सड़कें आज भी गड्ढा में पाई जा रही हैं। विशेषकर हमारे लालगंज विधान सभा में जो हमारा ठेकुआ ब्लाक, लालगंज और पल्हना ब्लाक में जो सड़कें हैं मुख्य रूप से विशेषकर जो मछुवारों से फेटी होते हुए साथ ही गुसांई की बाजार से पन्द्रहा रोड ज्युली बाजार से बीकापुर तक तमाम ऐसी सड़कें आज भी जर्जर बनी हुई हैं। रोज आये दिन घटनाएं घटती रहती हैं और बहुत से लोगों की उसमें मौत भी हो गई। बिजली की व्यवस्था के लिये हमारे मुख्य मंत्री विद्युत वितरण खण्ड

तृतीय मुख्यालय आजमगढ़ से लालगंज में मुख्यालय को बनाया जाये। शिक्षा क्षेत्र में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाय।बिजली के मसलों पर आज भी हमारे यहां बहुत दिक्कत है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

बिजली के मसले पर आज भी हमारे यहॉं बहुत दिक्कत हैं।

श्री अधिष्ठाता-

पासवान जी इनको बोल लेने दीजिये। संगीता जी अपने क्षेत्र की बात कह लीजिये। बाकी सब तो आ गया है।

डा0 (श्रीमती) संगीता बलवंत-

सर्वप्रथम 22 करोड़ देवतुल्य नागरिकों वाले देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बजट चर्चा के दौरान आपने मुझे बोलने का जो सुअवसर दिया है उसके लिये मैं आपको कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यहॉं जो 2018-2019 का बजट आया हुआ है वह बजट मातृशक्ति को समर्पित है। उस बजट को देखा जाय तो वह जो देश के भविष्य नौनिहाल हैं उनके लिये समर्पित है। यह 2018-2019 वाला बजट राष्ट्र के कर्णधार युवाओं के लिये समर्पित है, अन्नदाता किसानों के लिये समर्पित है, बेरोजागारों के लिये समर्पित है। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2018-2019 वाला जो लोक कल्याणकारी बजट है उसको देखकर हम यह कह सकते हैं कि इस बार का बजट काफी लोक कल्याणकारी है और मैं यह कहना चाहूँगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो दल बैठा हुआ है, या जो व्यक्ति मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन है, वह व्यक्ति सत्ता के सुख के लिये नहीं बल्कि जनता के सुख के लिये मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन है।(मेजों की थपथपाहट) 2018-2019 के बजट को देखकर यह कहने में कोई भी अतिश्योक्ति नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगी कि पूर्व के वक्ताओं ने 2018-2019 के बजट की एक -एक उपलब्धि को गिनाने का काम किया है। उपलब्धियों को गिनाने की पुनरावृत्ति न करते हुए मैं मात्र एक उपलब्धि इस सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो यह सिद्ध करने के लिये काफी होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वह किस तरह से गरीबों के लिये काम करना चाहते हैं। मैं बता दूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वनवासी (मुसहर) समाज की काफी संख्या है और केवल मेरे विधान सभा में ही नहीं पूरे प्रदेश में वनवासियों की संख्या काफी अधिक है और इस बार के बजट में, मैंने भी अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी को इस हेतु पत्र लिखा था कि वनवासी समाज के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, और मुख्य मंत्री आवास योजना के अतिरिक्त उन्होंने केवल वनवासी समाज के लिये 200 करोड़ रूपये का प्राविधान आवास के लिये किया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार मॉंग हो रही है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। हमारा विधान सभा क्षेत्र वहॉं पर कव्य ऋषि की भूमि है, वह जमदग्नि ऋषि की भूमि है, वहॉं पर नागा बाबा की भूमि है, मौनी बाबा की भूमि है। उस मनीषियों और देवतुल्य भूमि पर हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की, छात्रों की, जनपदवासियों की मॉंग है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

डा0 संगीता बलवन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ-

चमन के खोखले घट बेवजह आवाज करते हैं

योगी खामोश रहकर भी जनजन पर राज करते हैं

बजट विकास का आयाम के शिखर पर जाएगा

जनता खुशहाल रहे, योगी जी यही प्रयास करते हैं।।

श्री अधिष्ठाता-

हसन जी आप तो बोल चुके हैं,आप क्यों खड़े हैं। अब एक-एक मिनट कैलकुलेट करके फिर बोलेंगे कि बकाया है?अब और किसी विषय पर बोल लीजिएगा।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, लिखकर दे दें जो रह गया है वह सम्मिलित करा दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है लिखकर दे दें सम्मिलित हो जाएगा।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा करने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्।मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । मान्यवर, यह बजट पूर्णतया सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य, स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी बजट पेश किया गया है। इसमें विपक्ष ने तमाम तरह की फब्तियॉ कसी हैं किसी ने इसको किसी शब्द से नवाजा, किसी ने चूँ-चूँ का मुरब्बा करके नवाजा है, लेकिन मैं कहता हूँ इससे पारदर्शी बजट, इससे अच्छी पृष्ठभूमि वाला बजट, पेश हो नहीं सकता था। मैं तो इसे फूलों का गुलदस्ता कहुँगा, इसमें तरह-तरह के फूल हैं खुशबू बिखेरने वाले, समाज के तमाम वर्गों का इसमें समावेश किया गया है, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है,महिलाओं की सुरक्षा की बात कहीं गई है,तो वहीं पर हम किसानों की भी बात लेकर आए हैं। जहां हम बुन्देलखंड के विकास की बात करते हैं, वहीं हम पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे,पूर्वांचल को भी हम मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, इसका जीता-जागता उदाहरण यह है कि अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसी का प्रतिफल है,जो उत्तर प्रदेश में यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट किया गया, उसमें देश और दुनिया के बहुत बड़े-बड़े उद्योग व्यवसायी आए थे और ऐसे बहुत सारे एम0ओ0यूज साइन किए गए, चार लाख सड़सठ हजार करोड़ के एम0ओ0यूज0 साइन किए गए जो यह दर्शाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिक घरानों की रुचि बढ़ी है, आज उत्तर प्रदेश में विश्वास जागा है आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भाव मन में पैदा हुआ है। मान्यवर, कोई भी उद्योग लगाने के लिए जो चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वह यह है कि हमें वहां पर सुरक्षा मिले,हमें वहां पर मूलभूत ढांचा, यानि इन्फ्रास्ट्रक्चर मिले,जिसमें बिजली मिले, सड़कें मिलें, पानी मिलें यातायात के तमाम साधन मिलें। जो बजट हमारा बनाया गया है वह इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हम सुरक्षा को, अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करें, हम लोगों ने बहुत से सुधार के बजट में

प्राविधान किए हैं। स्वाट टीम को, एन्टी रोमियो दल को, एन्टी भू माफिया फोर्स को ऐसे बहुत सारी फोर्सेज को हम लेकर आए हैं जिससे प्रदेश की जनता तो सुरक्षित महसूस करे ही,इसके अलावा औद्योगिक घराने अगर हमारे यहां औद्योगिक व्यवसाय के लिए आते हैं,तो उनको भी एक प्रोटेक्टिव एटमॉसफियर मिले,एक सुरक्षा का भाव मिले। दूसरी चीज जहां तक बिजली की बात आती है माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पचास हजार मजरों में हम बिजली दे चुके हैं। 25 लाख गॉव के उपभोक्ताओं को हम बिजली दे चुके हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। 24 घंटे बिजली देने के लिए जो कभी सपना हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में बिजली की चर्चा नहीं हो रही है।इससे पहले एक वर्ष पहले तक हर जगह त्राहि-त्राहि मची हुई थी और यह कहा जाता था कि बिजली मिलती नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मेजर साहब बैठिए अब।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

लेकिन आज हमें सुखानुभूति है। बिजली एक ऐसा विषय है जिसमें हम सुख की अनुभूति तो कर रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वहीं पर पानी के लिए हमने ग्रामीण पेयजल योजना के लिए डेढ़ सौ करोड़ का प्राविधान किया है। सड़कों के लिए, आपने देखा हमारे एक मित्र साथी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट पढ़कर सुना दिया। विभिन्न सड़कों के लिए, कई राजमार्गों के लिए हमने प्राविधान किया है जिससे जो भी लोग, जनता हो, चाहे बाहर के औद्योगिक घराने हों, वह आएं तो उन्हें सुरक्षा का भाव महसूस हो कि यहां पर यातायात के साधन हैं। सड़कों के अलावा बहुत सी मेट्रो परियोजनायें हैं..

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें।

(श्रीमती साधना सिंह का नाम पुकारा गया।)

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

इससे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण हो रहा है अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। जहां तक हमारे क्षेत्र के विकास की बात है फर्रुखाबाद से मैं आता हूँ । इसे पांचाल नगरी कहा जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फर्रूखाबाद क्षेत्र से आता हूं, पांचाल नगरी कहा जाता था। वहां पर महाराजा द्रुपद का शासनकाल रहा, वहां पर द्रौपदी के स्वयंवर का स्थान आज भी है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आलू बहुतायत मात्रा में पैदा होता है। कोल्ड स्टोरेज की समस्या का समाधान नहीं है। हमारी सरकार ने 549 रु0 आलू का समर्थन मूल्य दिया है, अगर हमको आलू किसानों को खुश रखना है तो मैं सरकार से निवेदन जरूर करूंगा कि कोई ऐसा खाद्य प्रसंस्करण यूनिट अवश्य वहां लगायी जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे आलू किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा, विषय यह है कि हमारे यहां राम नगरिया का मेला लगता है जैसे इलाहाबाद में कुम्भ का मेला लगता है, अगर वहां के लिए कोई बजट आवंटित हो जाए तो जो

कल्पवास करते हैं उनको बहुत सुविधा मिलेगी, उनको बहुत आसानी होगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती साधना सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई। वर्ष 2018-19 का यह बहुत अच्छा बजट है, गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सबके लिए लाभकारी है। इस बजट से सारे लोग आनन्द और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा बजट आया है, जिसमें सारे वर्ग को लगा कि यह सरकार हम सबकी है। इतनी अच्छी बिजली जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे मिल रही है, जिसमें सारे वर्ग अपने आपको खुशहाल महसूस कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अभी पिछले कुछ सप्ताह पहले ही होली बीती है। हमारे क्षेत्र की महिलायें बाजार में हमसे मिलीं, मैंने पूछा कहां जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि साधना जी बधाई हो, आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपकी सरकार इतनी अच्छी बिजली दे रही है कि बिजली की वजह से हम सबका धान की सिंचाई में डीजल नहीं लगा और जो डीजल का पैसा बचा, जो धान की अच्छी खरीद हुई और जो तत्काल पैसा मिल गया, उस पैसे की वजह से बहुत अच्छी होली मनाई जा रही है। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग बाजार में अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए निकले हैं। सरकार को महिलाओं ने बधाई दी और उन महिलाओं की तरफ से हम आप सबको बधाई देते हैं कि कम से कम पचासों हजार रुपया, जिसके पास 2 बीघे, 3 बीघे या 2 एकड़ जमीन है तो पचासों हजार रुपये की डीजल में बचत हुई। हम आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देते हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी सड़कें रहीं, जो गड्ढ़ामुक्त हुईं। हम सरकार को बधाई देते हैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि जो आपने मिट्टी की रायल्टी खत्म करके किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को राहत दी है, हम आपको बहुत बधाई देते हैं। जो आपने सरकारी जमीन का पट्टा कराने की घोषणा की, जनप्रतिनिधि को जाकर कराना है, हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं।

आदरणीय अधिष्ठाता जी, महिला हूं, दो मिनट बोल लेने दीजिए, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। हम सब महिलायें हैं, पहली बार जीतकर आयी हूं, कम से कम कुछ समय दे दीजिए, आप ही लोगों से सीखना है। आप लोग तो 8-8, 9-9 बार जीतकर आये हैं, हम लोगों को तो आप ही से सीखना है और हम बधाई देना चाहते हैं अपनी सरकार को कि जिन नवजात शिशु उनकी माताओं के सम्पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, शबरी पोषण, मोबाइल एप कुपोषण मुक्त गांव, बचपन दिवस, ममता दिवस और लाडली दिवस हमारी सरकार ने महिलाओं और बेटियों पर ध्यान दिया है, शिक्षा पर ध्यान दिया है। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सामूहिक विवाह कराये, ऐसा विवाह दिखाई दिया कि एक गरीब की बेटी का इतना बढ़िया पण्डाल लगा, इतना बढ़िया हमारी सरकार ने बराती और घराती के लिए भोजन की व्यवस्था की, गिफ्ट की व्यवस्था की, हम लोगों ने भी गिफ्ट दिया और इतना अच्छा लगा कि हमारे गरीबों की बेटी का भी हाथ पीला हुआ। हम सब अपने क्षेत्र की तरफ से अपनी सरकार को बधाई देते हैं और अपनी सरकार से एक आग्रह करते हैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पंडित दीनदयाल नगर का नाम पड़ा है और आदरणीय दीनदयाल जी की डेड बॉडी मेरे विधान सभा क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर हत्या करके फेंकी गयी थी और उनके नाम पर मेरी

विधान सभा का नाम रखा गया है और मेरी विधान सभा क्षेत्र में चन्दासी एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है, जो कि ओवर ब्रिज की मांग, फ्लाई ओवर की हम मांग सरकार से रखते हैं। बचपन में एक सर्कस देखा करते थे आज वह सर्कस समाप्त हो गया । सर्कस में देखते थे कि कभी साइकिल को हाथी चलाकर जा रहा होता था तो हम लोग कहते थे कि यह संभव नहीं लग रहा है कि कहीं से यह कपड़े का बनाया गया है। लेकिन एक दो बार देखने के बाद यह महसूस हुआ कि वह सर्कस ही देश से समाप्त हो गया। लेकिन जो प्रदेश में सर्कस दिखाई दे रही है हाथी साइकिल पर बैठकर उसे हाथ से चलाते हुए जा रहा है यह भी सर्कस समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक कहावत है कि स्वर्णमयी लंका न मिलेवा अवधपुरी की धूल मिले सोने में कांटे चुभते हैं मिट्टी में हैं फूल खिलेबा-मिट्टी में हैं फूल खिलेबा । जय हिन्द जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। पासवान जी दो मिनट में अपनी बात रखें।

डा0 विमलेश पासवान-

अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपने मुझे अपना उद्गार प्रकट करने का अवसर दिया बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ । श्रीमन् लोकशाही में जनता ही जनार्दन होती है और जनता कब किसके सिर ताज बांध दे कब किसको अर्स से फर्श पर गिरा दे यह सिर्फ जनता ही जानती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो खूबसूरती है चुनने की जब जब चुनाव आए जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट देकर अपने उद्गार का उद्बोधन किया है । श्रीमन् गत 2017 के चुनाव में जिस प्रकार से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश जो आबादी में पूरे देश में सबसे ज्यादा है और यहाँ की आबादी ही यहाँ की शक्ति है। जिस आबादी में 60 फीसदी भागीदारी युवाओं की हो उनकी कहीं न कहीं अनदेखी और कहीं न कहीं उनको ठेस पहुँचाने का कार्य पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है। एक छोटा सा शेर मैं पढ़ूँगा कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। क्योंकि जिस प्रदेश में 60 फीसदी भागीदारी युवाओं की आबादी की हो वह आबादी छली गई हो उनके सपनों के पंखों को काटा गया हो और युवाओं को रोजगारपरक व्यवस्था न दी गई हो तो यह मैंडेट हमारी सरकार को मिली है इसके लिए हम तहे दिल से इस 22 करोड़ की आबादी वाले भारी भरकम प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। श्रीमन् भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2018-19 लोक कल्याणकारी है यह गांव गरीब किसान युवा और महिलाओं के सशक्तीकरण पर आधारित है। अन्त्योदय ग्राम सभाओं के चयन से गांव की सड़कें, बिजली, विद्यालय व अस्पताल विकसित होंगे। अन्त्योदय योजना से समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से मुख्य समग्र ग्राम विकास की योजनाएं ला रही है उससे अन्त्योदय का लाभ साकार होगा। अन्त्योदय का शाब्दिक अर्थ है गरीबी उन्मूलन जबकि दूसरी सरकारों में ऐसे विचार देखने तक नहीं मिलते थे। बजट के अन्तर्गत गरीब समाज के सशक्तीकरण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना से गैस, शौचालय का निर्माण के साथ साथ सौभाग्य योजना व घर घर विद्युतीकरण किया जा रहा है। इससे कहा जा सकता है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है और हर गरीब परिवार के सिर पर छत हो इससे हर गरीब परिवार गौरव के साथ जीवन यापन कर सके। श्रीमन् मैं बांसगांव विधान सभा क्षेत्र

से आता हूँ । जो कि गोरखपुर जनपद का अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र के नौजवान रोजगार परक व्यवस्था व माहौल न होने के नाते पलायन पर मजबूर रहते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को उनके सपनों को पंख मिलें यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं सृजित हों और हमारी महिलाएं हमारी बच्चियाँ इण्टरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई कर सकें इसलिए यहाँ राजकीय महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना हो। मेरे क्षेत्र के ब्लाक कौड़ीराम में बहुत सारे बंधे हैं जो बाढ़ में बह गए थे उनके तटबंधों की मरम्मत के लिए खासतौर से सरकार की प्राथमिकता जाए।

(इस समय 3 बजकर 09 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारा कौड़िराम चौराहा जो एक कस्बा भी है, एन0एच0-29 यहाँ से होकर जाता है। यहाँ पर शुलभ शौचालय न होने के नाते महिलाओं और बच्चियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि एन0एच0-29 का डायवर्जन उस कस्बे से हो रहा है तो वहाँ पर पहले से एक चुंगी पड़ी है तो वहाँ पर एक बड़ा शुलभ शौचालय बनाया जा सकता है, क्योंकि उस कस्बे की आबादी लगभग 25000 है और उसके साथ हमारे गगहा ब्लाक में गम्भीरपुर गाँव है। वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर के पड़ा हुआ है, परन्तु पर्याप्त संख्या में डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इंस्ट्रूमेंट्स और तकनीकी सुविधाओं के अभाव में वह स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं चाहूँगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाए। कुशवासी क्षेत्र जो लगभग 32 गाँवों की आबादी से परिपूर्ण है और जिसकी आबादी लगभग 01 लाख 20 हजार है। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था हेतु जो उपकेन्द्र है वह दूसरे फीडर सेवई से फीड होता है जो लगभग 20 किमी0 दूर है। मैं चाहता हूँ कि कुशवासी क्षेत्र जो 32 ग्रामसभाओं से आच्छादित है और लगभग 01 लाख 20 हजार ग्रामवासी यहाँ पर रहते हैं, उनका अपना अलग विद्युत फीडर होना चाहिये और वह फीडर मलवा में बनवाया जाए या कुशवासी क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल में बनवाया जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बाँसगाँव जहाँ पर 90 प्रतिशत लोगों की आय का स्रोत खेती है तो यहाँ पर जब भी रबी या खरीफ की तैयार फसल को काटने का समय आता है तो यहाँ पर अक्सर फसलों में आग लग जाया करती है इसलिये मैं चाहता हूँ कि हमारे बाँसगाँव विधान सभा में एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाए जिससे इस प्रकार की कोई प्राकृतिक घटना घटने पर तुरन्त उस आग को बुझाकर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझसे रह गयी है वह यह है कि हमारी विधान सभा का जो कौड़ीराम ब्लाक है, यहाँ पर अभी पिछली बाढ़ में किसानों का काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर अइमा, कतरारी, बेला ऐसे गाँव हैं जहाँ हमेशा बाढ़ आती है और यह गाँव पूरी तरह से पानी से घिर जाते हैं। यहाँ पर बेला के पास एक पुल बनना निश्चित है, मैं चाहूँगा कि यह सरकार उसके प्रति संवेदनशील हो। मा0 नेता सदन द्वारा मुझसे पूर्व में कही गयी बातों से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष-

मा0 दुर्गा प्रसाद यादव जी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । मा0 नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार

रखे, जो भाषण दिया, उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बजट पेश किया है वह दिशाहीन बजट है और इसमें कोई तत्व नहीं है। इनका जो पिछला बजट था और उसमें जो योजनाएं थीं उनका कुछ पता नहीं चला कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। इन्होंने लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गढ्ढामुक्ति का जो नारा दिया है तो करीब 20 प्रतिशत ही गढ्ढामुक्ति का कार्य हुआ होगा और आप देख लीजिये कि वह कार्य खत्म हो गया। इसमें पैसे का बंदरबॉट किया गया है। इसी तरह से मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में जो योजनाएं लागू हुई थीं और जो परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं, आज वह अधूरी पड़ी हुई हैं। उसके लिये इस सरकार ने आज तक कोई बजट नहीं दिया है। यह सरकार गॉव के विकास कार्यों के लिये बजट देने का नाम नहीं ले रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गयी थी। मा0 अखिलेश यादव जी ने उसकी घोषणा की थी, परन्तु जमीन का कुछ विवाद होने के कारण वह नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन जब से यह नयी सरकार आई है तो उसको वहाँ से हटा करके गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। इस तरह की जो भी योजनायें आयी थीं, जो सपा की सरकार में स्वीकृत हुईं थीं उन सभी योजनाओं पर इस सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार केवल अपनी बात पर विश्वास करती है और जनता के बीच झूठ बोल करके, गरीब जनता को गुमराह करके केवल वाहवाही लूटने का काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जनता को धोखा दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है। हमारी जनता को इसका एहसास हुआ और उसने फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव में सपा को जीत दिलाकर इसका असर भी दिखाया और जनता ने इस सरकार को सबक भी सिखाया। इस प्रदेश की जनता सीधी भी है, चतुर भी है और अन्याय करना भी जानती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अस्पतालों की एक गंभीर समस्या है। अस्पतालों में दवाईयाँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हैं, कुत्ते के काटने की सुई तक उपलब्ध नहीं है। आज गरीब आदमी किसी तरह मेडिकल स्टोर से कुत्ते के काटने की सुई खरीद कर लगवाने का काम करता है। सरकारी अस्पताओं के डाक्टर पर्ची पर दवा लिख देते हैं और गरीब आदमी वह दवा बाहर से खरीद नहीं पाता है। मा0 अखिलेख यादव जी के शासनकाल में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं था जहां दवा उपलब्ध न हो, कुत्ते के काटने की सुई उपलब्ध न हो, और इसी के साथ-साथ बड़ी-बड़ी बीमारियों से मरीजों को बचाने की व्यवस्था यदि किसी ने किया था तो वह मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि गांवों में बिजली के खम्बे तो गडे हुए हैं लेकिन उन पर तार नहीं हैं और जिन गांवों में बिजली के कनेक्शन हैं भी तो वहां पर बिजली का बिल इतना अधिक आ रहा है कि हर कोई उसकी भरपायी नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो बिजली का बिल आ रहा है वह फर्जी आ रहा है उसे बन्द किया जाये, उसे समाप्त किया जाये। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हमारे साथियों ने सही कहा है कि इस सरकार में दिनोदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, यह सरकार हर मुददे पर फेल हो चुकी है। आज जो बजट इस सरकार ने पेश किया है वह बिल्कुल दिशाहीन है। सड़कों के निर्माण से लेकर हर कार्य आज अधूरा पड़ा हुआ है। मगर इतना

जरूर है कि यह सरकार केवल भाषण देने में विश्वास करती है, काम करने में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती है। इसलिए मैं नेता विरोधी दल के भाषण पर अपना बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

राम फेरन पाण्डेय जी।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं अपने आप को बजट भाषण से सम्बद्ध करता हूँ। मैं कई दिन से सुन रहा हूँ हमारे वरिष्ठ साथी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा पर आजादी से लेकर अभी तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो हमारे शिक्षा मंत्री ने कर दिखाया है। मैं श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो नेपाल बॉर्डर का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन आज वे मॉर्डन स्कूल की तरह अच्छी ड्रेस पहन कर स्कूल जाते हैं। इसके लिए मैं मा0 शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, कृषि पर आधारित बहुत से कदम हमारी सरकार ने उठायें हैं। बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश के कई जिले तबाह हो रहे थे, श्रावस्ती जिला उनमे से एक था। हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी ने वहां पहुँच करके पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के मनुष्यों को तो चारा दिया ही, जानवरों की भी चिन्ता करने का काम किया है। यह मा0 योगी जी की सरकार ने किया है जिनको जानवरों की भी चिन्ता है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी सरकारों के दावे आज तक खोखले साबित हुए हैं और हमारे यहां की पूरी 46 हजार जनता को इससे लाभ मिला है। तमाम जगह ब्लाको में, तहसीलों में, जिला मुख्यालय में कैम्प लगा करके हमने सर्टिफिकेट बांटा है और सर्टिफिकेट में पचास प्रतिशत से अधिक लोग माइनारटी के थे। हमारी सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी काम कर रही है इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ । अभी सिंचाई की बात आई, जब से मैंने होश संभाला है सन 1982 में नहर का कार्यक्रम हुआ तब से लेकर अब तक लोग नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंचा पाये थे। पिछले पांच साल में नहर की योजना बंद हो गई थी लेकिन हमारी एक साल की योगी जी की सरकार ने नहर की योजना लान्च करके नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। बिजली की आप लोग बात करते हैं, हमारे यहां हर महीने 1500-1700 बिजली आती थी लेकिन बिजली कब आई और कब चली गई इसका हमको नहीं पता चलता था। हमारी जनता को नहीं पता था, लेकिन बिजली का बिल आता था। जब मोबाईल चार्ज करना होता था, तो इन्वर्टर नहीं काम करते थे, बिना जनरेटर के बिजली नहीं मिलती थी, लोग बिजली के लिए तरसते थे। आज हमारी सरकार ने 18 घण्टे, 20 घण्टे, 24 घण्टे बिजली देने का काम किया है। हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तीन दिन पहले इतना बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश से मिट्टी से पूरा प्रतिबन्ध हटा दिया और यहां तक घोषणा कर दी कि भट्ठा मालिक अगर ईंट का रेट कम करेंगे तो उनकी रायल्टी भी समाप्त कर दी जायेगी। पूरी पारदर्शिता से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसी से सम्बद्ध करते हुए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे श्रावस्ती में दो हवाई पट्टी शो पीस के रूप में बनकर खड़ी हुई थी, लेकिन आज तक उस पर संचालन का काम नहीं हुआ है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस पर भी अपना ध्यान

आकर्षित करे। यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले पन्द्रह साल की सरकारों के समय में श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र में इकौना और गिलौला के रोडवेज बस स्टेशन बंद हो चुके हैं, लोगो ने बस स्टेशन की जमीन पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि उस सरकारी धन को दुरुपयोग से बचाने के लिए उसको संचालित कराने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फाइनेन्सियल ईयर 2019 पर बोलने का मौका दिया है। वित्तीय वर्ष 2019 में चार लाख अट्ठाइस हजार करोड़ का जो ऐतिहासिक बजट दिया गया है यह काबिले तारीफ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया के एक बड़े देश पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन की है और हमारी आबादी 220 मिलियन की है। जब इतना बड़ा हमारा प्रदेश है जो ब्राजील की आबादी से भी बड़ा है तो उसका बजट दो हजार, तीन हजार करोड़ का नहीं होना चाहिये। चार लाख अट्ठाइस हजार करोड़ का जो बजट दिया गया है यह बहुत काबिले तारीफ है और इसमें एक जो विशेष फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया गया है इसकी मैं खासा तारीफ करना चाहता हूँ और सराहना करना चाहता हूँ । किसी भी देश की जो नींव होती है वह उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर से बनती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जर्मनी जब एक महान देश की अपनी जगह लेने आगे बढ़ा तो वहां पर आटो वाहन का रोड नेटवर्क बनाया गया।

मा0 अध्यक्ष जी, हिटलर ने बहुत गलत काम किये लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जिसकी आज तक सराहना की जाती है कि उसने जो आटो-वाहन नेटवर्क पूरे जर्मनी में बनाया। इसी तरीके से प्रेसीडेंट रूमेन ने अमेरिका में जब वह दूसरे विश्वयुद्ध से निकले, तो 1950 और 1960 के दशक में ही उन्होंने 'इण्टर स्टेट एक्सप्रेस-वे नेटवर्क' बनाना शुरू किया। जिसके बल पर आगे चलकर अमेरिका एक सुपर-पावर देश बना। ब्रिटेन में भी यह काम 1950 और 1960 के दशक में 'विलसन' के टाइम में मोटर-वे के रूप में किया गया। हमारा उत्तर प्रदेश इससे पीछे रहा। मा0 नितिन गडकरी जी, जब वह महाराष्ट्र के पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस एक्सप्रेस-वे का कॉन्सेप्ट भारत में लाने का काम किया। पूने को उन्होंने बम्बई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का काम किया। बाद में जब समाजवादी पार्टी को लोक सभा के चुनाव में करारी हार मिली तो उनकों समझ में आया कि केवल लैपटॉप बांटने से और समाजवादी पेंशन योजना इत्यादि से हमारी दाल नहीं गलने वाली। उसके जस्ट बाद जो बजट आया तो आप साफ फर्क देख सकते हैं कि हार के पहले और हार के बाद वाले बजट में कि अचानक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसको बहुत से लोग अखिलेश हाई-वे के नाम से जानते हैं, वह है आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे। जैसाकि मा0 मंत्री जी ने कहा कि उसको पूरा नहीं कर पाये, बड़े दुःख की बात है। अक्सर निगेटिव सोच की राजनीति होती है जिसको अंग्रेजी में पार्टीशियन पॉलीटिक्स कहते हैं कि अगर पार्टी के ही पक्ष में बोलना है और दूसरे का जो भी सही काम हो उसे गलत साबित कर देना है। इसके तहत अक्सर सरकारें क्या करती हैं कि पुरानी स्कीमों में पैसा देना बन्द कर देती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने कर दिखाया है कि हम लोग कभी भी इस तरीके की निगेटिव पॉलीटिक्स नहीं करते हैं।

केन्द्र में भी मोदी जी ने मनरेगा जो कांग्रेस की स्कीम थी, उसमें कांग्रेस भी उतना पैसा नहीं दे पाई जितना मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने देने का काम किया था। लगातार दो वित्तीय वर्ष से जिसको अखिलेश हाई-वे कहा जाता था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और इस सदन को बधाई देना चाहूंगा कि हम लोगों ने उसको इस लेवल तक कम्पलीट करा दिया है कि आज अगर हमारी चाइना और पाकिस्तान से जंग हो जाये और हमारे फाइटर प्लेन्स को अचानक इमरजेंसी में उतरना पड़े तो वह उन पर उतर सकते हैं। यह ट्रायल भी हमारी सरकार में हुआ है, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हो पाया था। यह चींजें आप चेक कर सकते हैं कि एयरफोर्स प्लेन पिछले फाइनेंसियल इयर में उतर चुके हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मैं इलाहाबाद से हूं। इलाहाबाद एक ऐसी क्रिटिक्ल जगह पर है कि बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल इलाहाबाद के संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा और यमुना के संगम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इलाहाबाद एक और चीज का मीटिंग प्वाइंट है एक और जंक्शन है। इलाहाबाद वह प्वाइंट जहां पर बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल आकर मिलते हैं। अगर आप इलाहाबाद के एक छोर से निकल जाइये तो आप जौनपुर और भदोही पहुंच जायेंगे और अगर आप दूसरे छोर से निकल जाइये तो सीधा चित्रकूट पहुंच जायेंगे। तो इसलिए यह जो दोंनो बड़े एरिया हैं पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड, इनको इस सरकार ने जो बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे देने का काम किया है, यह बहुत ही बढ़िया काम है और एक अर्थशास्त्र का पुराना मैक्सिम है 'इफ यू बिल्ड इट दे विल कम' अगर आप बनाओगे तो अपने आप उद्योगपति और निवेशक आयेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, गोमती नगर और एन0सी0आर0 में नोएडा। जब वहां पर लोगों को इन्फ्रास्ट्रक्चर मिला तो अपने आप बिना सरकारों की मदद के बिना नेताओं की मदद के विश्व भर से निवेशक वहां पर आये। जब यह पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे जिसके लिये 650 करोड़ और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए एक हजार करोड़ रूपये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय हो गया है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, मैं शार्ट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ । इस समय मैं इलाहाबाद का होते हुए खासकर सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की इलाहाबाद तक लिंक सुल्तानपुर के होते हुए दी जा रही है और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे की भी लिंक चित्रकूट के माध्यम से इलाहाबाद को दी जा रही है। इसके साथ-साथ मैं कुम्भ मेले के क्षेत्र से आता हूँ । कुम्भ मेले के लिए जो दोनों सालों में जिस तरीके से सरकार ने अपना कुबेर का खजाना खोला है अगर मैं उसके लिए धन्यवाद नहीं दूंगा तो कहीं न कहीं मैं अन्याय करूंगा। इलाहाबाद में जो मेन कुम्भ एरिया है उसमें पिछली बार भी एक हजार करोड़, 500 करोड़ देने का काम किया गया था और इस बजट में भी 1500 करोड़ देने का काम किया गया है। और एक परमानेंट सेक्रेटरियेट कुम्भ मेला प्राधिकरण के रूप में वहॉ पर दिया गया है। जिसका हेड एक आई0ए0एस0 करेगा और विभिन्न लोग जो कुम्भ मेले से जुड़े रहते हैं वह उसके मेम्बर रहेंगे। यह बहुत बड़ा काम किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, अब आप बैठिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, कहने को तो बहुत कुछ था। मैं बैठने के पहले बस एक बात कहना चाहूंगा कि भारत की छवि खराब जो पहले कुछ सालों में हुयी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जो आज हमें एक टाइगर इकानॉमी माना जा रहा है हमारे पहले भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो पॉच सबसे खराब अर्थव्यवस्था के देश थे उनमें गिना जाता था। उसका एक कारण था कि जो हमारे फिजिकल डेफिसिट थे, फिजिकल डेफिसिट एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि जितनी हमारी कमाई है उससे हम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पर हम कर्जा छोड़ने जा रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। वह पूरी दुनिया भांप रही थी और कहती थी कि भारत के फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा बहुत कमजोर है। हमारी सरकार प्रदेश में जब आयी तो उनको 4 प्रतिशत के ऊपर का फिजिकल डेफिसिट मिला। जबकि हमारा जो फिजिकल रेस्पांसिबिलिटी एक्ट है जिसका मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया उसमें तीन प्रतिशत की लक्ष्मण रेखा है कि तीन प्रतिशत के बियोंड आप नहीं जा सकते। मैं मुख्य मंत्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार को बधायी दूंगा कि आपने दोनों साल में बैक टू बैक 3 प्रतिशत के नीचे 2.95 प्रतिशत के लेवल पर फिजिकल डेफिसिट को ले आये हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी मुझे यह मौका देने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास जो सूची है उसमें नाम टिक नहीं हो पाये हैं तो कोई एक सदस्य समाजवादी पार्टी के बोल लें।

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट सत्र 2018-19 में चर्चा में बोलने का मुझे प्रथम बार अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ । मैं अपने आपको अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सम्बद्ध करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह कैसा बजट है जिसमें प्रदेश के सभी वर्ग हों चाहे वह किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों, नौजवान हों, व्यापारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, सभी दुखी हैं। सभी अपने आपको इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पिछले बजट का पैसा भी नहीं खर्च हो पाया और नया बजट प्रस्तुत कर दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं जनपद लखनऊ राजधानी से लगी हुयी विधान सभा मोहनलालगंज का प्रतिनिधित्व करता हूँ । मा0 अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र यहॉ से मात्र 15 किमी0 बाद से शुरू हो जाती है। मगर अफसोस की बात यह है कि सरकार ने जो चुनाव के समय नारा दिया था 'सबका साथ सबका विकास'। पर आज सब जगह पर उसका उल्टा हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा अनुसूचित जाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र है। जहॉ पर लगभग 60 प्रतिशत की आबादी दलित आबादी है। हमारे क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मोहनलालगंज क्षेत्र में ब्लाक विकास खण्ड, मोहनलालगंज में नहरें तो बनी हैं मगर नहरों में पानी नदारद है। नलकूप तो हैं मगर ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है वहां से नहरों की कमांड हटाई जाए। वहां पर सिंचाई के लिए

ट्यूबबेल, नलकूप स्थापित किये जाएं ताकि किसानों को अपने खेत की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके। मान्यवर, सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' परंतु हमारी विधान सभा के विकास खण्ड मोहनलालगंज में आजादी के इतने वर्ष बाद भी बालिकाओं के लिए एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना सरकार स्तर पर नहीं हो सकी है और आज भी जो गरीब किसानों की बच्चियां हैं उनके लिए शहर के डिग्री कॉलेज 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ जाते हैं। किसी भी किसान को अपनी बेटी को इतनी दूर पढ़ाने के लिए भेज पाना सम्भव नहीं है और ऐसी स्थिति में जब बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? मैं आपके माध्यम से सरकार से विकास खण्ड मोहनलाल गंज में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग करता हूं। मान्यवर, अगर विकास की बात की जाए तो मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारे विधान सभा क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टेडियम, अमूल डेरी, कैंसर हॉस्पिटल जैसी अनेक बड़ी-बड़ी परियोजनाएं लाई गयीं। हमारे क्षेत्र में चारों तरफ विकास कार्य चल रहे थे सभी सड़कें बराबर बन रही थीं, लेकिन पिछले एक वर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सभी विकास कार्य बिल्कुल रूक गये हैं। न तो किसी भी सड़क का निर्माण हो रहा है और जो भी निर्माण हो रहा था उसको भी रोकने का कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है। मान्यवर, मैं कस्बा मोहनलालगंज में स्थित मऊ रेलवे क्रॉसिंग पर जो जेल रोड गोसाईगंज, सुल्तानपुर को जोड़ती है उक्त मार्ग पर क्रॉसिंग बंद होने पर पूरा कस्बा जाम हो जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से गोसाईगंज मार्ग पर मऊ रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने की मांग करता हूं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में तमाम ऐसे गांव हैं जहां बारनाले पर पुल नहीं हैं जिसमें मोहनलाल गंज विकास खण्ड का मदारीखेड़ा गांव और गोसाईगंज में बागनाले पर एक-एक पुल बनवाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मान्यवर, खुजौली ग्राम सभा में खुजौली से नगराम मार्ग पर निर्माण कार्य हमारी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पिछली एक वर्ष से उस सड़क का निर्माण कार्य लगभग ठप पड़ा हुआ है। जो मटेरियल जहां पर पड़ा हुआ था वह आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नगराम से खुजौली मार्ग को यथाशीघ्र जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मान्यवर, आज हमारे क्षेत्र में राजस्ववाद मोहनलालगंज में काफी पैंडिंग है और आसपास काफी दूर होने के कारण हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक भी मुंसिफ न्यायालय नहीं है जबकि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मोहनलाल गंज में एक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाए और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो इस सरकार में पुलिस का उत्पीड़न हमारी विधान सभा क्षेत्र में बराबर गरीब किसान का बहुत ही शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्षेत्राधिकारी मोहनलाल गंज जो भी हैं जिनके द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है वह बंद कराया जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत अच्छा बोले हैं। अब हम मद संख्या-2 ले रहे हैं।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2740/29-6-2015-115सा-14, दिनांक 16 नवम्बर, 2015†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2740/29-6-2015-115सा-14, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, नियमावली, 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 की उपधारा(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-178/29-6-2016-116सा-14, दिनांक 20 जनवरी, 2016 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-178/29-6-2016-116सा-14, दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 की उपधारा(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2945/29-6-2016-115सा-2014, दिनांक 14 दिसम्बर 2016†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2945/29-6-2016-115सा-2014, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-1253/20-6-2017-116सा-2014, दिनांक 7 जुलाई, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-1253/20-6-2017-116सा-2014, दिनांक 7 जुलाई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2-2011(लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2-2011(लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र, 2017 (दिनांक 14-12-2017 से दिनांक 22-12-2017 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र, 2017 (दिनांक 14-12-2017 से दिनांक 22-12-2017 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

उ0 प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 140वां (एक सौ चालीसवां) प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति और सदन की अनुज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 140वां (एक सौ चालीसवां) प्रतिवेदन जो नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, वित्त, खाद्य एवं रसद, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन, औद्योगिक विकास, सचिवालय प्रशासन, वन, चीनी उद्योग, पर्यटन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, माध्यमिक शिक्षा, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण तथा बेसिक शिक्षा विभागों के वर्ष 1987 से 2016 तक के आश्वासनों से संबंधित हैं, सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) एवं 141वां (एक सौ इकतालिसवां) प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति और सदन की अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) एवं 141वां (एक सौ इकतालिसवां) प्रतिवेदन जो लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम एवं पर्यावरण विभागों के वर्ष 1999 से 2016 तक के आश्वासनों से संबंधित है, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापे नहीं गये।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में खेल का मैदान विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मिश्रा आदि निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री देवमणि द्विवेदी नहीं हैं।

जनपद गाजीपुर के ग्राम महेगवां पलहवीपुर व मीरपुर की आ0न0 एन0एच0-29 द्वारा अधिग्रहीत पचासी प्रभावित किसानों की प्रतिकर धनराशि लगभग 22 करोड़ रुपये दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कामेश्वर चौहान आदि निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 वीरेन्द्र यादव नहीं हैं।

जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र जलालपुर के ब्लॉक भियॉव के ग्राम पंचायत मथुरा रसूलपुर में रामजीत दलित के खेत से हसनपुर सम्पर्क मार्ग पर कौड़ाही बाजार तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 शून्य से लेपन कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र जलालपुर के ब्लॉक भियॉव के ग्राम पंचायत मथुरा रसूलपुर में रामजीत दलित के खेत से हसनपुर सम्पर्क मार्ग पर कौड़ाही बाजार तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 शून्य से लेपन कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जिला जौनपुर के ब्लाक-केराकत के अन्तर्गत नगर पंचायत केराकत में अग्निशमन केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशु जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री दिनेश चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला जौनपुर के ब्लाक-केराकत के अन्तर्गत नगर पंचायत केराकत में अग्निशमन केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशु जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जिला अम्बेडकरनगर के ब्लॉक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मिर्जाबेग दुःखवर (मकदूमपुर बना) के दक्षिण से तुरकहिया तालाब से ग्राम सभा नैली (नयानगर) तक के नाला की सफाई जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला अम्बेडकर नगर के ब्लॉक-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मिर्जाबेग दुःखवर (मकदूमपुर बना) के दक्षिण से तुरकहिया तालाब से ग्राम सभा नैली (नयानगर) तक के नाला की सफाई जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

---

† छापी नहीं गयी।

ग्राम सभा हरीपुर, ब्लाक-चकिया, जनपद चन्दौली में पक्की सड़क बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री शारदा प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम सभा हरीपुर, ब्लाक-चकिया, जनपद चन्दौली में पक्की सड़क बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के ग्राम पंचायत नसीरपुर (रसमई) के सादाबाद रजधेह में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन सिंह आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

श्री अध्यक्ष-

कुँ0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह ''रानू'' नहीं हैं।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में स्थित धुरियापार सहकारी चीनी मिल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में स्थित धुरियापार सहकारी चीनी मिल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल राय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

महामना राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती को गृह विज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं चित्रकला में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से महामना राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती को गृह विज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं चित्रकला में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(1) जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नजीरूद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नजीरूद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(3) जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र-351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक-ठेकमा की जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

श्री ज्ञान तिवारी जी नहीं है।

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा ग्वारी में राजकीय डिग्री कालेज/इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री बृजेश सिंह आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र रेउसा को तहसील व पुलिस सर्किल ऑफिस बनाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र अवस्थी आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा थानगांव में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री विकास शुक्ला आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

श्री अनिल सिंह जी नहीं है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुलरिहा के मजरा संग्राम खेड़ा से जिन्दा खेड़ा गांव तक गड्ढायुक्त कच्चे मार्ग का जनहित में डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्धमें डा0 सर्यैद सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछौरा से काशी प्रसाद खेड़ा गांव तक गड्ढायुक्त कच्चे मार्ग का जनहित में डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा नगर पंचायत मौरावां के अन्तर्गत कस्बे में दस वर्ष पूर्व स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरदीप त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

---

† छापी नहीं गयी।

जिला उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड-हिलौली के अन्तर्गत ग्राम दुन्दपुर के पास मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल तिवारी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जिला उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के कस्बा मौरावां के अन्तर्गत बसहा तिराहा के पास मौरावां-उन्नाव मुख्य मार्ग पर बनी संकरी पुलिया का चौड़ीकरण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद लखनऊ में नीलमथा रोड स्थित गोकुल धाम कालोनी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रानू त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

भूसानगर कानपुर देहात को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में विपिन सचान आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनोद कटियार-

मान्यपर, मैं आपकी अनुज्ञा से भूसानगर कानपुर देहात को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

सरवन खेड़ा कानपुर देहात में गत 50 वर्षों से पेयजल टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से सरवनखेड़ा कानपुर देहात में गत 50 वर्षों से पेयजल टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा भोगनीपुर के शाहजहांपुर जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार कटियार आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(3) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा भोगनीपुर के शाहजहांपुर जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार कटियार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बिजनौर वि0 स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के ग्राम चकनारंगी नगीना अकबराबाद मार्ग पर 300 मी0 नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री इफ्तेवार हुसैन आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के ग्राम चकनारंगी नगीना-अकबराबाद मार्ग पर 300 मी0 नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री इफ्तेखार हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत अकबराबाद-किरतपुर मार्ग के ग्राम बिरदोंनाली तक 2.00 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री अशफाक आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत अकबराबाद-किरतपुर मार्ग के ग्राम बिरदोंनाली तक 2.00 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री अशफाक व अन्य निवासीगण हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बिजनौर वि0 स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम पाडला से ग्राम मुबारकपुर खोसा (खुसियाकी) ईदगाह तक 1.5 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार आदि निवासीगण जनपद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर वि0 स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम पाडला से ग्राम मुबारकपुर खोसा (खुसियाकी) ईदगाह तक 1.5 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बिजनौर वि0 स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर में ग्राम अकबराबाद-किरतपुर मार्ग पर शिव मन्दिर से ग्राम बेगमपुर रूपचन्द (सिसौना) तक लम्बाई 700 मी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर वि0 स0 क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड किरतपुर में ग्राम अकबराबाद-किरतपुर मार्ग पर शिव मन्दिर से ग्राम बेगमपुर रूपचन्द (सिसौना) तक लम्बाई 700 मी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड कोतवाली के नगीना-नहटौर मार्ग सैदखेड़ी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम लालवाला (उग्रसैनपुर) में टूटी पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में जो कल्याण सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड कोतवाली के नगीना-नहटौर मार्ग सैदखेड़ी सम्पर्क मार्ग पर ग्राम लालवाला (उग्रसैनपुर) में टूटी पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में जो कल्याण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड किरतपुर के ग्राम शादीपुर-किरतपुर मार्ग से जीवनपुर तक लम्बाई 1.00 किमी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर वि0स0 क्षेत्र नगीना के विकासखण्ड किरतपुर के ग्राम शादीपुर-किरतपुर मार्ग से जीवनपुर तक लम्बाई 1.00 किमी0 सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बरेली की मीरगंज तहसील के फतेहगंज (प0) में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0 लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की मीरगंज तहसील के फतेहगंज (प0) में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0 लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह चौहान आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज से हुरहुरी दीवना होते हुये फतेहगंज (प0) को जोड़ने वाले पुराने रोड को शुरू कराने व दिजोड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत मीरगंज से हुरहुरी दीवना होते हुये फतेहगंज (प0) को जोड़ने वाले पुराने रोड को शुरू कराने व दिजोड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही से मिर्जापुर चौराहा तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही से मिर्जापुर चौराहा तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में सिधौली चौराहे से वाया हल्दीकला धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय आदि जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में सिधौली चौराहे से वाया हल्दीकला धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय आदि जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय प्रताप जायसवाल नहीं है।

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के ब्लाक रामनगर में बैदौला से असुरैला तक जाने वाले मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर सिंह आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद-बस्ती के तहसील-भानपुर में (पूर्व समाजवादी सरकार द्वारा तहसील स्तर पर विद्युत उपग्रह निर्माण की नीति के तहत) विद्युत उपग्रह को उर्जीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

जनपद-बस्ती के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के प्रमुख मार्ग सहनुआ-बरहपुर का निर्माण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेश जायसवाल आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' सदस्य विधान सभा का निवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि उनकी याचिका को श्री देवमणि द्विवेदी को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

जिला शाहजहांपुर के वि0स0 क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित कटरा रोडवेज बस अड्डा के नवीनीकरण व सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल कुमार आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री देवमणि द्विवेदी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जिला शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित कटरा रोडवेज बस अड्डा के नवीनीकरण व सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

[03.53] उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018†

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन विधेयक 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन में विधेयक 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती स्वाती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करती हूँ ।

---

†† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट में छापा है।

प्राइवेट आई0टी0आई0 पशिक्षण हेतु पंजीकृत छात्रों के फीस की प्रतिपूर्ति रोके जाने के संबंध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

आपने मुझे नियम 311 के अर्न्तगत अपनी सूचना पर विषय आकर्षित करने के लिए जो मौका दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

हमने आपका स्वीकार कर लिया वो नियम कहां निलंबित किया। आपने हमारी बात मानी और देर तक बैठे रहे। आपने कृपा की। आप अपनी बात कहिए।

श्री संजय गर्ग-

वास्तव में लोक महत्व का विषय है एवं बहुत तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेता विरोधी दल को पूजा में जाना है।

श्री संजय गर्ग-

मैं इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश के 2 लाख 40 हजार पंजीकृत विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है जो अंधकार में चले गए हैं। वह तमाम 2 लाख 40 हजार विद्यार्थी जिनका पंजीकरण राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के अंतर्गत हुआ था जो आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण लेकर किसी भी तरह से अपने भविष्य का निर्माण करने का सपना देख रहे थे उन प्राईवेट आई0टी0आई0 के अंदर उनकी फीस कितनी ली जा सके अचानक एक शासनादेश यहां 12 मार्च 2018 व 9 मार्च 2018 को निदेशक के द्वारा जारी किया गया। निदेशक, प्रशिक्षण सेवायोजन उत्तर प्रदेश के द्वारा ये बात कही गई कि जो फीस प्राईवेट आई0टी0आई0 में देने की बात कही जा रही थी और जिस फीस को 2015-2016 में 2016-2017 में भी जिन विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई जिसका आधार था जो केंद्र सरकार का भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के डी0जी0ई0टी0 के विभाग का पत्र संख्या डी0जी0ई0एन0टी0/19/19/2012 एण्ड टी0डी0एन0पी0टी0 डेटेड 29 दिसम्बर 2014 के अनुरूप ये निर्णय लिया गया था। वर्किंग कमेटी के ग्रुप के उसमें नॉरमेटिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी इन प्राईवेट आई0टी0आई0 को सुविधा दी जाए जिसमें जो रूरल एरिया के इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं उन्हें 15 हजार प्रतिवर्ष और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं उन्हें 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष। उसके अलावा जो अरबन क्षेत्र में इंजीनियरिंग ट्रेड के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 16 हजार 5 सौ रूपए प्रतिवर्ष और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति 13 हजार दो सौ रूपए प्रतिवर्ष। उपरोक्त राशि के जो भारत सरकार के द्वारा दी जा रही थी ये 2015-2016 और 2016-2017 के शैक्षिक क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति दी गई। वे जो अनुसूचित जाति के छात्र थे और जितनी राशि बचती थी उन्हें सामान्य और ओ0बी0सी0 के छात्रों में वितरित कर दिया जाता था। 2 लाख 40 हजार छात्रों का पंजीकरण पोर्टल में हुआ। अचानक पोर्टल के पंजीकरण को रोक दिया गया और 09 मार्च 2018 को एक तुगलकी आदेश इस आशय के साथ किया गया कि उन्हें 40 रुपये महीना, 480 रुपये प्रति वर्ष की

शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इस 480 रुपये मात्र में प्राइवेट आई0टी0आई0 जो असेवित हैं, उनके द्वारा प्रयोगशाला चलाना, शिक्षकों का वेतनमान देना, इन तमाम चीजों के अलावा जो उनके एक्सपेन्सेस हैं उन्हें उठाना भारी है। पिछली 12 तारीख से तमाम छात्र और प्राइवेट आई0टी0आई0 संचालक इस बात के लिए हड़ताल पर हैं और मा0 व्यावसायिक शिक्षा मंत्री अभी रोजगार मेले का उद्घाटन करने के लिए सहारनपुर गए थे वहाँ पर भी लोगों ने उनसे मिलकर अपनी समस्या को अवगत कराने का काम किया था। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई निर्णय लेना भी था तो फिर इन 02 लाख 40 हजार छात्रों को पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया जाता। पहले से ही समय रहते उस तरह का निर्देश जाने की बात कर दी होती तो ज्यादा बेहतर था परन्तु इस सब के अलावा प्रधान मंत्री के स्किल इण्डिया मिशन पर कुठाराघात करते हुए जिस तरह से यह तुगलकी आदेश हुआ है। निश्चित रूप से इससे उन तमाम छात्रों का भविष्य अँधेरे में चला गया। मैं आपके माध्यम से यह बात भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विभाग द्वारा कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनकी फीस औसतन 40 रुपये घण्टे के हिसाब से प्राइवेट ट्रेनिंग सेण्टर्स को दी जा रही है जिससे औसतन 3-5 माह के कोर्स की फीस 10-15 हजार रुपये होती है। पूरे के पूरे दो शैक्षिक सत्रों में यह फीस दी गई। अचानक इस फीस को रोक देने से हाहाकार मचा हुआ है और उनका पूरा भविष्य अंधकारमय है। मैं आपके माध्यम से शासन से यह आशा करता हूँ कि इस पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आई0टी0आई0 संचालकों और छात्रों को बुलाकर उनके बीच सामन्जस्य स्थापित करते हुए उनके भविष्य में अंधकार होने से रोकने का काम किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह मा0 मंत्री जी का है।

खेल तथा युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जो सवाल हैं उनके जवाब देना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

लगता है आपका माइक गड़बड़ है क्योंकि सवेरे भी गड़बड़ कर रहा था।

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, सुबह भी गड़बड़ कर रहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ दिन मौर्य जी के पास बैठो तो आवाज तेज हो जाएगी।

(सदन में हँसी)

श्री चेतन चौहान-

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम अवगत कराना है कि प्रदेश के किसी भी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों,

प्रशिक्षार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाना अथवा नहीं किया जाना यह विषय समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है और उसे ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेना है। बिन्दु-2, मा0 विधायक जी द्वारा भारत सरकार के जिस पत्र का उल्लेख किया जा रहा है, उसकी छाया प्रति संलग्न है। भारत सरकार के पत्र द्वारा शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है, मात्र शुल्क को सुझावित किया गया है। भारत सरकार के किसी भी सुझाव को स्वीकार किया जाना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। बिन्दु-3, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण शुल्क को कम नहीं किया गया है, वरन् राजकीय निजी आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अवगत कराया गया है। इसलिए उल्लेखनीय है कि प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु प्रशिक्षण शुल्क के नियमन, नियतन हेतु व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का शासनादेश दिनांक 03-02-2014 जो कि पिछली सरकार का था, (छाया प्रति संलग्न) जारी किया गया है। शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उनका अनुपालन प्रदेश के किसी भी आई0टी0आई0 द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया है जिसके कारण निजी आई0टी0आई0 हेतु प्रशिक्षण शुल्क का नियतन नहीं हो पाया है। बिन्दु-4, वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने स्तर से फीस प्रतिपूर्ति की गई है तथा इस सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को किसी भी उच्च स्तर पर अवगत नहीं कराया गया है लेकिन इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो विषय है। इस सम्बन्ध में परसों निजी आई0टी0आई0 के जो अधिकारी हैं और उनके कर्मचारियों के जो नेता हैं, वे भी मुझसे मिले थे। कल मैंने विभाग की बैठक बुलाई थी व्यावसायिक शिक्षा की भी और समाज कल्याण की भी। इन लोगों से वार्ता की है और उनसे यह कहा गया है कि निजी आई0टी0आई0 के मण्डलों के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाए क्योंकि इसमें दो-तीन पहलू हैं। यह भी है कि फीस जो एक प्रकार से निर्धारित नहीं की गयी है एक सुझाव केन्द्र सरकार के माध्यम से आया था लेकिन उसमें बहुत सारी कन्डीशन्स भी थीं, वह शर्तें जो हैं प्राइवेट आई0टी0आई0 द्वारा मान्य नहीं की गयी हैं जैसे कि इम्तिहान होना और वह इम्तिहान व्यावसायिक परिषद् कराएगी वह उन्होंने नहीं माना है, जो एडमिशन आई0टी0आई0 के द्वारा किये जाते थे वह अपने आप किये जाते थे जो कि विभाग को मान्य नहीं है तो ऐसी कुछ शर्तें थीं। वे यदि मान लेते हैं तो विभाग को कोई भी परेशानी नहीं है कोई भी आपत्ति नहीं है लेकिन बातचीत इसमें चल रही है। किसी प्रकार का कोई नुकसान करने वाली बात यहॉ पर नहीं आने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसमें आप समग्रता में विचार कर लीजिए।

जनपद-सुल्तानपुर श्री दीनानाथ पुत्र श्री तुलसीराम पासी के अपने निजी खेत से मिट्टी खनन करने पर कोतवाल द्वारा घूस की मांग न पूरी होने पर उन्हें एवं उनके परिवार को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना जिला सुल्तानपुर की है 24 तारीख को दीनानाथ पुत्र श्री तुलसीराम पासी जी अपने निजी खेत से एक ट्राली मिट्टी अपने निजी काम के लिए लेकर गए थे वह ट्राली उनके दरवाजे पर पहुँची ही थी कि तब तक एक कोतवाल श्री दिनेश सिंह व सिपाही

श्री सूर्यप्रकाश और पुष्पराज दीनानाथ जी के दरवाजे पर पहुँच गये और उनसे 500 रूपये प्रत्येक ट्राली जबरन वसूली करने लगे जितनी ट्राली मिट्टी लेकर आओगे 500 रूपये प्रत्येक ट्रॉली दो नहीं तो थाने चलो कहने लगे। उतने में ही वहाँ पर भीड़ एकत्र हो गई और वहाँ के प्रधान श्री राघवेन्द्र द्विवेदी जी जो अधिवक्ता हैं वह भी काफी लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए। कोतवाल ने जब देखा की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है तो उन्होंने किसी तरह से उस भीड़ को यह धमकाकर कहा कि मैं देख लूँगा और यह कहकर चले गए लेकिन रात में उन्हीं कोतवाल ने लगभग 12.00 बजे दीनानाथ के घर में जाकर पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर दी तथा महिलाओं के साथ अभद्रता की और यही नहीं राघवेन्द्र द्विवेदी जी जब कोर्ट से सुल्तानपुर तिराहे पर पहुँचे थे तो लगभग साढ़े 5 बजे कोतवाल ने इनको उठा लिया और इतनी बार मारा कि आज भी ये ट्रामा सेन्टर में भर्ती हैं और ये अपने जीवन-मरण की स्थिति में जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक महत्व का तात्कालिक विषय है।

श्री अध्यक्ष-

यदि आप सहमत हो तो मैं सरकार को कह दूँ कि सरकार कार्रवाई करा दे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब इन्होंने विषय उठाया है तो जवाब तो आ ही जाए। इसका जवाब आना जरूरी है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस घटना का जिक्र माननीय उमाशंकर जी ने किया ये घटना 24-25 फरवरी, 2018 की है। मान्यवर, जो घटना का कारण बताया गया वह कारण हो सकता है कि सही हो लेकिन मान्यवर, जो मारपीट की बात है। मारपीट की घटना में जिसकी पैरवी यहाँ से की जा रही है, जिस विषय के ऊपर यह सूचना दी गयी, मान्यवर, श्री राघवेन्द्र प्रकाश जी के विषय में जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार ये थाना मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के मजारिया दुराचारी संख्या-75(ए) हैं। मजारिया दुराचारी का मतलब है कि हिस्ट्रीसीटर-75(ए)हैं। इनके ऊपर केवल 13 मुकद्में हैं और अगर आप चाहें तो हम बता दें इनके ऊपर जो 13 मुकद्में हैं वह वर्ष 2001 से लेकर 2013 तक 13 मुकदमें हैं। इसमें 376 का एटेम्प्ट है, 395, 97 है, मान्यवर, 412 भी है, 452, 323 है और 3 मुकदमें इनके ऊपर एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के हैं। तो 13 मुकदमें वाले यह श्रीमान् राघवेन्द्र प्रकाश जी के लिए यह कहा गया कि इनके साथ मारपीट हुई। मान्यवर, मारपीट तो हुई लेकिन राघवेन्द्र जी ने ही पुलिस वालों को मारा और उसकी रिपोर्ट भी यह क्राइम नम्बर 36/2018, धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 332, 353, 341 मान्यवर, 341 रॉन्गफुल कन्फाइनमेण्ट की श्रेणी में आता है, 342 उसका पनिशमेण्ट है और इतनी दफाओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। यह 13 मुकदमें के अतिरिक्त है। उसके बाद जब यह पकड़ कर थाने लाए गए उसके बाद जब कचहरी रिमाण्ड के लिए ले जाए गए तो वहां भी झगड़ा हुआ और वहां भी एक मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ। 38/2018, 147, 224, 225, 225 बी, 323, 332, 353, 427 आई0पी0सी0। मान्यवर, अब रही बात तोड़फोड़ की घटना की अब चूंकि यहां विधान सभा में यह प्रकरण उठा और इसके पहले भी यह बात सामने आई तो चूंकि यह पुलिसवालों को अधिकार तो नहीं है कि किसी के यहां जाकर कोई तोड़फोड़ करें। तो सरकार ने दिनेश सिंह एस0आई0 को सूर्य प्रकाश, देवेश और पुष्पराज को निलम्बित कर दिया। अब जहां तक जीवन-मरण के प्रश्न से यह झूल रहे हैं

अगर आप कहें तो हम इनकी रिपोर्ट भिजवा दें। रिपोर्ट यह है कि इनके दो कन्टयूजन है और एक रेसिरेटेड वून्ड है। इनसाइज वून्ड भी नहीं है यानि कि धारदार हथियार से भी वार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय नेता प्रतिपक्ष मुतमई हैं तो सब हो गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप मुझे क्षमा करें, अभी तक तो यह पैरवी जो है, हमने नाम बाद में देखा हम तो सोचते थे कि यह आपकी तरफ से आया है क्योंकि ए क्लास हिस्ट्री शीटर की पैरवी जो है हम यह सोचते नहीं थे कि यह भी करेंगे। तो हमने तैयारी की तब हमने नोटिस नहीं देखा था कि किसकी तरफ से नोटिस आया है लेकिन जब पता चला तो मान्यवर, यह मेडिकल रिपोर्ट भी है और मेरे पास सस्पेंशन की रिपोर्ट भी है और जो उनकी जन्मपत्री केस की है, वह भी है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो वर्मा जी सब हो गया ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दीनानाथ जो पासी हैं इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है केवल यह मिट्टी निकाल रहे थे और ट्राली ले जाकर घर पर खड़ी की थी। केवल वह उनसे रिश्वत मांग रहे थे उन्होंने नहीं दी, इस आधार पर इनके खिलाफ कार्यवाही हुई। चूंकि राघवेन्द्र द्विवेदी गांव के प्रधान हैं और प्रधान की हैसियत से उनके समर्थन में आए जिसके कारण यह कार्यवाही की गयी। मान्यवर, वह कचहरी से निकल रहे थे और रास्ते में ही पकड़ लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पुलिस पर भी कार्यवाही सरकार द्वारा हो गयी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो सस्पेंड किया गया है, जो इन्चार्ज जिम्मेदार है उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह खनन के काम में रूकावट डालने के लिए खनन के काम के कारण, उसको रोक न पाने के कारण रिसर्चमेण्ट किया गया है। इस घटना पर किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है। मान्यवर, इनके साथ जिस तरह से इसके घर में उत्पीड़न किया गया, जिस तरह से दीनानाथ के पूरे परिवार को उत्पीड़ित किया गया निश्चित रूप से यह बहुत ही गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो मुकदमों वाली बात बता रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दीनानाथ के ऊपर कहां मुकदमा है।

श्री अध्यक्ष-

दीनानाथ उन्हीं के साथ तो नहीं था ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दीनानाथ जो कि अनुसूचित जाति के हैं, पासी समाज के हैं इनके परिवार का इनसे विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी यह अपने निजी खेत से अपने घर ले गए थे। दो सिपाही आते हैं वह उनसे पांच हजार रूपये मांगते हैं। मान्यवर, वह रूपये देने से इंकार करते हैं कि यह हम अपने लिए लाएं हैं, सरकार ने नियम बनाया है कि दस ट्राली तक हम ला सकते हैं और इसलिए इस पर कोई बात नहीं होगी और केवल इसी आधार पर उनके साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं, पूरा गांव जुट जाता है। जब गांव के लोग जुट जाते हैं और प्रधान उस गांव के हैं राघवेन्द्र द्विवेदी जी, इनको भी मजबूरन आना पड़ता है मान्यवर। राघवेन्द्र द्विवेदी जी वकील भी हैं और गांव के प्रधान भी हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से यह अत्यन्त ही गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आप नोटिस देख लें। दीनानाथ की घटना को इसमें इम्फेसिस नहीं किया गया, इसमें दिया गया है कि राघवेन्द्र द्विवेदी को बुरी तरह पीटा गया, द्विवेदी ट्रॉमा सेन्टर, लखनऊ में जीवन-मरण से संघर्ष कर रहे हैं। जीवन-मरण से संघर्ष कंज्यूनल ऑफ लेसिनेटिड वुण्ड से थोड़े ही होता है। जीवन-मरण से संघर्ष करने के लिए वैसी कोई इंजरी होनी चाहिए। जो घटना आपने बतायी दीनानाथ के साथ उसके जवाब में मैंने बता दिया है कि एक दरोगा और तीन सिपाही सस्पेंड कर दिये गये। संस्पेंशन ऑर्डर भी मेरे पास है। जिनके लिए यह बताया गया था कि जीवन-मरण से जूझ रहे हैं, उनको पीटा गया, यह उनकी केस हिस्ट्री है, जो मैंने बताया कि मजारिया ए क्लास हिस्ट्री शीटर हैं और तेरह मुकदमे उन पर हैं। जब यह घटना हुई उसके पहले तेरह मुकदमे हो चुके थे और उसमें जितनी भी संगीन धारायें हैं वो सब इनके ऊपर दर्ज हैं। 2001 से लेकर 2013 तक ये यह मुकदमे हैं, पढ़ दें, तो आप सुन लीजिए। क्राइम नं0 238/2001, 452, 323, 504, 506 थाना मुसाफिर खाना, अमेठी। दूसरा 117 ए/2002 147, 148, 323, 504, 506 आई0पी0सी0, मुसाफिर खाना, अमेठी। सी 4/2006 157, 323, 427।

श्री अध्यक्ष-

पूरा सुनेंगे क्या?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुकदमा आप देख लें, किस तरह के मुकदमे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आगे सुन तो लें 436, 376।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सी0जे0एम0 ने उनकी चोट को देखकर आदेश किया कि पहले इनका इलाज कराइये। मान्यवर, सी0जे0एम0 ने कहा हमने नहीं कहा और न ही पुलिस ले आई थी इलाज कराने।

श्री अध्यक्ष-

तो उस पर कार्य वाही तो हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दूसरी जो मुख्य बात है वह श्री दीनानाथ का मामला है। दीनानाथ केवल एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी ले गये थे इसलिए उनकी घर की औरतों से लेकर पूरे परिवार को परेशान किया गया।

श्री अध्यक्ष-

दीनानाथ के प्रकरण की ही तो ये जांच कराये हैं तभी तो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नोटिस तो देख लें। दीनानाथ की चार लाइनें हैं केवल, बाकी सब कुछ राघवेन्द्र जी के लिए कहा गया है।

श्री लालजी वर्मा-

ग्राह्यता पर हम यहां बताते कि उसके साथ कैसे ज्यादती हुई। नोटिस में सारी डिटेल नहीं लिखी जाती है, ये आप भी जानते हैं मान्यवर, हम भी जानते हैं, सभी यह जानते हैं। नोटिस में अगर पूरी डिटेल लिखी जाती तो एक ही पेज में हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब करना क्या है वर्मा जी?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि जो सम्बन्धित इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने घर में घुसकर इस तरह से दीनानाथ के पूरे परिवार के साथ उत्पात मचाने का काम किया नम्बर एक। दूसरे मान्यवर, फर्जी मुकदमा उनके ऊपर लादने का काम किया गया, यह दोनों मामले हैं। साथ ही साथ प्रधान को जिस तरह से पकड़ा गया, वो कचहरी से आ रहे थे, रास्ते में गोलबन्दी करके पकड़ा गया, जैसे बहुत बड़े अपराधी हों। उनकी शिकायत केवल यही थी कि वो दीनानाथ की मदद को वहाँ आये थे। इसलिए मान्यवर ऐसे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और साथ ही साथ जो फर्जी मुकदमा दीनानाथ के परिवार के ऊपर लादा गया है उसको समाप्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा ये आपके माध्यम से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में पूरा विवरण है, सौ प्रतिशत। अभी वो बता भी चुके हैं दो बार। अब आप उन पर छोड़ दीजिए पूरा विषय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दीनानाथ के मामले में दिखवा लेंगे । लेकिन नोटिस में जिस राघवेन्द्र के ऊपर फोकस किया गया था, जो जीवन मरण से झूल रहे हैं, ऐसा बताया गया, उनकी हमने ए क्लास

हिस्ट्रीशीट और इसमें 302 से लेकर जितनी अच्छी-अच्छी दफायें हैं आई0पी0सी0 में, वह सब इसमें शामिल हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

हिस्ट्रीशीट का मतलब, क्या आप उसको उड़ा देंगे, फर्जी फंसा देंगे । प्रधान है और बहुत से लोग विधायक बने होगें हिस्ट्रीशीट तो उनकी भी होगी ।

श्री अध्यक्ष-

आप उनकी मदद में क्या चाहते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो फर्जी मामला है, इस पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिये और इस मामले की उच्चस्तरीय जॉच होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो कहा है कि जॉच करायेंगे । जॉच का स्पष्ट आश्वासन उनका आ गया, ठीक है । अब अगला विषय लेते हैं ।

कई दिन से बजट पर सामान्य चर्चा चल रही थी । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उत्तर भाषण के लिये माननीय वित्त मंत्री जी अपनी बात रखें ।

[04.20] वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक चर्चा पर वित्त मंत्री का उत्तर भाषण

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी, बसपा के श्री लालजी वर्मा, कांग्रेस विधायक दल के श्री अजय कुमार 'लल्लू' नहीं हैं, अपना दल के श्री नील रतन जी पटेल, मेरे मंत्रिमंडल की सहयोगी और राज्य मंत्री हमारे यहॉ श्रीमती अनुपमा जी जायसवाल, माननीय सदस्य श्री कैलाश नाथ जी शुक्ला, श्री चन्द्रिका प्रसाद जी उपाध्याय, श्री मनोज जी पारस, श्री रोशन लाल जी वर्मा, श्री अब्दुल्ला आजम जी सहित तमाम माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । अब मैं सीधे माननीय नेता प्रतिपक्ष पर ही आ जाता हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे विषय थे जिनके उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिये हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऐसे थे, मुझे लगता है कि जिनके बारे में कहना बहुत आवश्यक है । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट को समाप्त नहीं कर पाये तो नये बजट की क्या जरूरत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष के लिये एक बजट होता है और संवैधानिक बाध्यता होती है। स्वाभाविक रूप से उसके लिये प्रेजेंट करना और प्रेजेन्ट करके उसको पारित कराना यह संवैधानिक बाध्यता है। इसी तरह से आपने एक प्रश्न और किया कि कुल 15 दिन बचे हैं और बजट पूरा खर्च नहीं हुआ, अभी तक कुल 35 प्रतिशत ही बजट खर्च हुआ है। तो मान्यवर काफी कुछ डिटेल आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री जी ने बता दी है लेकिन फिर भी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ऊर्जा विभाग है ।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई ऐसी बात नेता प्रतिपक्ष की आप जानते हो जो बहुत गोपनीय हो, वह आप बताइये ।

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, गोपनीय बात होगी तो फिर नेता प्रतिपक्ष क्या रहेंगे । बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर कहा गया । लेकिन हकीकत यह है और मुझको लगता है कि आदरणीय नेता जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय यह दिया है कि केन्द्र सरकार आपको बजट नहीं देती थी जब आपकी सरकार थी और हमारी सरकार के लिये केन्द्र सरकार के बजट से बराबर स्वीकृतियॉ मिल रही हैं । मान्यवर, जो लोक कल्याणकारी योजनायें होती हैं उनका आपने कभी किसी का हिसाब नहीं दिया, परिणाम तो कहीं न कहीं आयेगा ही । यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स आपके द्वारा नहीं दिये गये । इसका परिणाम सामने आया । कल्याणकारी योजनायें थीं जैसे आवास की थी, शिक्षा की थी, आप चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री जी के नाम से न हों और हमारे समाजवादियों के नाम से हो । इस विषमता के चलते मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाया । जहॉ तक प्रश्न इस बात का है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से अनेकानेक योजनायें चला रही हैं । केन्द्र की ही सारी योजनायें नहीं हैं, केंन्द्र सरकार की योजनायें तो कुल हमारे पास हैं, मैक्सिमम 16 प्रतिशत ही इस बजट के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। अब उद्योग के अंदर, अवस्थापना निवेश के अंदर हमने 1400 करोड़ रूपया दिया है। क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिये और इस कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रूपया दिया है। एक जनपद, एक उत्पाद में 250 करोड़ रूपया दिया है। मुख्य मंत्री युवा रोजगार योजना में 100 करोड़ रूपया दिया गया है। मेट्रो की परियोजनाओं में लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रूपया हमने दिया है। तो यह मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार का यह बजट जो सर्वांगीण भी और हर चीज के अंदर उन्होंने अपने-अपने सीमित संसाधनों से, मैंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं। लेकिन, सर्वांगीण विकास को लेकर चलने वाला यह बजट है और एक-एक चीज के ऊपर हम ने इस तरह से इसको सुनिश्चित किया है और अपने में यह अभूतपूर्व है। अर्थव्यवस्था का इससे विकास होगा। बजट के आकार में भी हमने वृद्धि की है। हम कहीं पर भी एफ0आर0बी0एम0 का उल्लंघन नहीं कर पाये हैं, उसके अंदर विदइन स्टेटस उसको मेनटेन किया है और इसलिये यह बजट चाहे किसानों से जुड़े हुए विवाद का हो और चाहे किसी भी तरह का हो, जो यह पर्यटन की बात जो आपने उठायी थी, किसानों की बात भी आपने उठाई थी, वह रिपीट न करते हुये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारा का सारा मेरा बजट जो इस वर्तमान सरकार का आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें किसी भी तरह से कमी नहीं है। सर्वांगीण विकास के साथ-साथ यह पूरे के पूरे प्रदेश को आगे लेकर चलने वाला बजट है। हॉ, आदरणीय लालजी वर्मा ने जरूर जो यह बात उठायी है और बजट के अंदर शिक्षा के बारे में कहा है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के बारे में सरकार बहुत ज्यादा गंभीरता से काम कर रही है और इस पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और पहली बार ऐसा हुआ है कि नीचे नर्सरी से लगाकर ऊपर तक के बच्चों को पढ़ने के लिये हमने गणवेश भी दिया है, उनके लिए ड्रेस भी दिया है, उनके लिये जूता भी दिया है, उनके लिए मोजा भी दिया है। उनकी पुस्तकें अच्छे काम कार्जों की हों इस बात की चिंता भी इस सरकार के माननीय मंत्रीगण ने किया है। मान्यवर, हमने सामान्य बजट के अन्दर जो कहा, आदरणीय लालजी वर्मा ने तो उस पर 50 से 60 प्रतिशत नहीं बल्कि इस समय जो है, लगभग-लगभग हम 87-88 प्रतिशत तक की जो है, वह हमारी निकासी बजट से हो चुकी है और आगे भी हम निश्चित इस सब के लिये पूरा

करने जा रहे हैं। मैं निश्चित एक चीज और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल मीट हुई है, वह इंडस्ट्रियल मीट हमारे लिये उत्तर प्रदेश के सामने बहुत बड़ा माइलस्टोन के रूप में हमारे सामने है, हमारी क्रेडिबिलिटी इसके अन्दर आई है। हमारी सरकार की विश्वसनीयता जो है, वह खाली भारत वर्ष में ही नहीं है, सम्पूर्ण विश्व के अंदर है और इसीलिये लगभग 28 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट किये थे और जैसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ घोषणा की थी कि 20 हजार करोड़ का तो खाली ये डिफेंस इन्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना की बात है, वह इसमें सम्मिलित है। मैं आदरणीय अजय कुमार जी 'लल्लू' के भी बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने आलू के बारे में जो प्रश्न उठाये थे, यह सब लोग जानते हैं कि आज आलू की स्थिति के बारे में हमारे यहाँ जो है, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाकर इसकी प्राइज भी डिक्लेयर कराई है और आज बाजार का जो मूल्य है, आज हमारे सामने उसका परिणाम है। मैं अन्त में बहुत कुछ न कह कर मान्यवर, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यह बजट पूरी तरह से जनहित में है। यह बजट जो पूरी तरह से काश्तकारों के हित में, मान्यवर, यह बजट जो है, वह दबे-कुचले, इन सारे के सारे समाज के जितने लोग हैं, उन सब को साथ लेकर चलने के लिये है और कोई भी चीज अगर साथ लेकर चली जाती है तो यह सर्वांगीण विकास के लिये होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने इस सामान्य चर्चा में महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिये हैं। आशा है, मेरी तरफ से माननीय नेता विरोधी दल, माननीय अन्य नेता दल जो हैं, उनकी जिज्ञासाओं का निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाधान हुआ होगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, इस बजट का निश्चित रूप से पूरे समाज के ऊपर असर पड़ना है। मिलजुल कर जो बार-बार बात आती है हम लोग आगे चलें और इस बजट को पास करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मुख्य मंत्री जी का पूरा उत्तर भाषण सुना और मैंने मा0 वित्त मंत्री जी का भी उत्तर भाषण सुना और मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में वित्त मंत्री जी अगर मुख्य मंत्री होते तो यह प्रदेश जरूर विकास के रास्ते पर जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल विपक्ष की आलोचना में ही अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं जो कि एक अच्छी संसदीय परम्परा नहीं है। यह अच्छी परम्परा नहीं है हम लोग किसी से व्यक्तिगत लगाव की बात नहीं करते हैं, यह संसद है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं हम सब आपस में मित्र हैं, सब एक हैं, सब चुनकर आते हैं, सभी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। जैसे मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मा0 राम गोविन्द जी जमीन के कार्यकर्ता हैं, इनको किसी ने बनाकर दे दिया होगा, यह असली जानते तो इस तरह से नहीं कहते। मान्यवर, बजट में जो कमी हुई थी वह तो इनकी किताब में है, मैंने मद भी बताया था मा0 वित्त मंत्री जी, मदवार मैंने बताया था कि इस-इस मद में इतने-इतने पैसे की कटौती हुई है पिछले साल के एवज में। फिर मैं पढ़ूँगा तो बड़ा लम्बा हो जायेगा इसलिए मैं एक में ही कहता हूँ अनुदान सं0-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग रु0 36 लाख 65 हजार 287.70 लाख, एक मैं कह दे रहा हूँ तो यह अनुदान सं0-11, अब यह कैसे हो सकता है कि हम नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब कि मा0 मुख्य मंत्री जी को फुर्सत नहीं पढ़ने की और वह बिना पढ़े हुए यहाँ भाषण दे रहे हैं। जो बजट की किताब में मा0 वित्तमंत्री जी ने लिखा है उससे यह निकाला गया है या तो इनका बजट भाषण गलत है, या फिर इनकी जो पुस्तिका छपी है वह गलत है, या तो मा0 मुख्यमंत्री जी गलत हैं, उनको सदन में असत्य प्रलाप नहीं करना चाहिए था। दूसरा मैंने यह कहा था सही बात है एक साल हो गया बजट पास हुए और विभागों ने बजट में पैसा खर्च ही नहीं किया। यह जो बजट पास कर रहे हैं इसकी भी कोई

गारंटी नहीं कि बजट का पैसा खर्च होगा और आखिर में बजट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है श्रीमन् क्योंकि एक आदमी को नौकरी नहीं मिली है। ऋण के विषय में मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे, ऋण ग्रस्तता के विषय में कह रहे थे हमको जानकारी नहीं है तो हम कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, वर्ष 2016-17 में बाजार ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 13.2 प्रतिशत था, वर्ष 2017-18 में बाजार ऋण 14.6 प्रतिशत हुआ और वर्ष 2018-19 में बाजार ऋण 16 प्रतिशत से अनुमानित है। मान्यवर, यह बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यह तो लिखित है, यह आपकी बुक्स में है जो आपने किताब छपवाई है उसमें है और उसमें भी मा0 मुख्यमंत्री जी कह दें कि नेता विरोधी दल असत्य बोलते हैं। मान्यवर, ऐसी ही बात होगी तो यह बिल्डिंग गिर जायेगी, बिल्कुल बिल्डिंग गिर जायेगी, लोकतन्त्र ध्वस्त हो जायेगा, केवल विरोध पक्ष को कोसना, बेईमान बताना, घूसखोर कहना, लूट लेना, यह संसदीय कौशल नहीं है। संसदीय कौशल है कि अगर संसदीय कार्यमंत्री कोई ऐसी बात भी कहें कि हमें चोट भी लग जाये और हमको ख्याल भी उसका न हो। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में संसदीय कौशल में घोर गिरावट मैं देख रहा हूँ जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत से हमारे मा0 सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, अच्छे-अच्छे भाषण किये हैं लेकिन अब जिन्दगी भर यही कहते रहेंगे कि हमने लूट लिया। हमने लूट लिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा स्वाभाव नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी व्यक्तिगत बात कहते हैं। एक हमारे छोटे भाई सामने बैठते हैं, उन्होंने हमारा उदाहरण दे दिया। आपको बहुत-बहुत बधाई, लेकिन फिर मैं यह कहता हूँ कि दुनिया की किसी भी एजेंसी से रामगोविंद चौधरी की जांच करा लिया जाए, दुनिया की किसी भी एजेंसी से। व्यक्तिगत आक्षेप है, बलिया का चोखा-बाटी है। आपकी सरकार को आए बहुत साल नहीं हुए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बलिया की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जिसको लोग मूर्खता का भोजन कहते थे, गरीबता का भोजन कहते थे, बाटी-चोखा को, वह आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देशभर में फैल गया है। आज फाइव स्टार होटलों में परोसा जा रहा है, बड़े-बड़े लोगों का शादी-व्याह हो रहा है उसमें भी अब परोसा जा रहा है। अल्प बचत, जो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे, सुन लीजिए। मैं भी ठीक से मुख्य मंत्री जी को सुन रहा था । अल्प बचत, 2016-17 में 5.2 प्रतिशत थी, वर्ष 2017-18 में 4.4 प्रतिशत हुई और 2018-19 में 3.7 प्रतिशत हो गयी। यह क्या है श्रीमान् ? बड़ा विकास, बड़ा काम, 24 घंटे मुख्य मंत्री का काम, 48 घंटे मंत्री का काम, विधायक लोगों के पास तो काम ही नहीं है। अगर कोई भी अपने कर्तव्य निष्ठ लोगों को सरकार में भेजा है, अगर सरकार उसी को बेईमान समझने लगेगी, तो उस सरकार जैसी बेईमान कोई सरकार हो नहीं हो सकती। यह क्या है ? मैं पूरा लिखित बताया। मा0 मुख्य मंत्री जी, फसल बीमा योजना पर कह रहे थे । फसल बीमा योजना में पिछले बजट में 450 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। उसमें किसानों को कितने करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कम्पनी ने किया, और सरकार ने कितना बीमा कम्पनी को दिया है, यह बताएंगे मा0 वित्त मंत्री जी। जनवरी, 2017 में मोहल्लों की गलियों में फेरी लगाने वालों और सब्जी मंडी में फुटपाथ पर सामान बेचने वालों से कितनी-कितनी फीस ली जायेगी, मा0 वित्त मंत्री जी बताएंगे इसको मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताया है। सब्जी मंडी फुटपाथ पर काम करके जो गरीब जीता था और मा0 मुख्य मंत्री जी जिस गरीब की बात कर रहे थे आपने गरीबी देखी कहां है ? आप तो जहां हैं वहां मठ है वहां पर तो चढ़ावा आता है। यदि सरकार ने गरीबी देखी होती जिसमें 500 रूपये गरीब बहन-बेटियों को पेंशन देते थे तो उसको 1000 रुपये कर के सभी को देते। तब गरीब के हिमायती कहलाते। अगर यह सरकार गरीब की हिमायती होती, तो जो हम 20 हजार कन्या विद्या धन देते थे उसको यह सरकार देती। अगर ये किसानों के हमदर्द होते तो हमने किसानों की सिंचाई मुफ्त की, नहर की, ट्यूबवेल की, फसल बीमा योजना लागू की। हमने शत प्रतिशत किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। अब कहेंगे तो बहुत

डीटेल में चला जाएगा। अगर आप किसान के हितैषी होते, तो मैंने ही कहा था और हमारी सरकार ने वादा भी किय था कि अगर 2017 के चुनाव में हमारी सरकार बन जाएगी, तो जितने भी किसानों के निजी ट्यूबवेल हैं, चाहे बिजली से चलते हैं, चाहे डीजल से चलते हैं उसका भी हम नहर और ट्यूबवेल की तरह से फ्री कर देंगे। आपने क्या किया? किसानों के लिए, कौन से घड़ियाली ऑसू बहा रहे हैं। श्रीमन्, इस तरह से विपक्ष की सही बातों को नकारना सही नहीं होता। ऐसे विकास नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि पहली बार, हमेशा उनको पहली बार याद आ रहा है। पहली बार हम एक्सप्रेस-वे बनाने जा रहे हैं। इसको कोई सत्य मानेगा। अध्यक्ष जी, आप सत्य मानेंगे इसको। अरे, ऐसी बात कहिए, मैंने उस समय टोक कर भी कहा था क्या मा0 कल्याण सिंह जी अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में काम नहीं किये थे। क्या माननीय राजनाथ सिंह जी, मा0 राम प्रकाश गुप्ता जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम नहीं किये थे, मा0 मुलायम सिंह यादव जी, बहिन मायावती जी, स्व0 वीर बहादुर सिंह जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम नहीं किये थे? पहली बार-पहली बार, हर चीज पहली बार! तो हर बार पहली बार यह भी हो रहा है कि बजट पास हो रहा है और जनता ठन-ठन गोपाल पा रही है। यह भी अध्यक्ष जी, पहली बार हो रहा है। वायदा करने के बावजूद कि 30 दिन के अन्दर हम सबको नौकरी देंगे, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिला। अभी माननीय नेता सदन कह रहे थे कि 32 लाख लोगों को नौकरी दिया। हम जानते हैं अखबार में तो यह निकल ही जायेगा, मुख्य मंत्री जी का भाषण निकलता है। नौजवान तो फूल जायेगा कि अब तो हम स्वर्ग में पहुँच गये। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव के पहले देश में घूम-घूम करके कहा था कि नौजवानों तुमको नौकरी मिल रही है? नौजवान खड़े होकर हाथ जोड़ते थे नहीं सरकार, नहीं, तो नौकरी चाहिए, हॉ सरकार। भा0ज0पा0 सरकार बनाओ हर साल मैं दो करोड़ लोगों को नौकरी दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये शब्दों का इतना बढ़िया तालमेल करते हैं कि आदमी ठग जाता है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर।) सुनिये। जिस एक्सप्रेस-वे की बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप वित्त मंत्री जी से पूछ लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सत्तापक्ष के लोग मुख्य मंत्री समेत सभी हमारे मित्र हैं और विपक्ष के लोग भी सत्तापक्ष के मित्र हैं। पक्ष और विपक्ष से ही यह सदन चलता है। लेकिन श्रीमन्, हमेशा विपक्ष को रॉन्ग साइड पर ले जाना यह सत्तादल को शोभा नहीं देता है। किसानों के हमदर्द हैं, कर्जमाफी की बात कही। हमारे सिकन्दरपुर तहसील के दो मामले ले आये थे। गलतियॉ होती हैं, अबकी तो दो रुपया आया था, डेढ़ रुपया आया था, आठ आना आया था कर्जमाफी। (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा कहा गया कि एक लाख रुपये का कर्ज भी माफ किया गया है।) सुन लीजिए। 01 लाख रुपया कर्ज भी माफ हुआ होगा उसको मैं नकार तो नहीं रहा हूँ । लेकिन जो किसानों का माफ हुआ, किसी का 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, ढ़ाई रुपया, तीन रुपया, चार रुपया, जितना इन्होंने पैसा लिया था कर्जमाफी के लिए आज तक उसका आधा पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अब प्रचार क्या हो गया कि सारे किसानों का कर्जा माफ। अरे! वाह रे भारतीय जनता पार्टी, आपके विषय में लोगों की एक सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी चरित्रवान है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर) अब हम कह रहे हैं तो आप क्यों ताली बजा रहे हो ? ऐसा-वैसा क्यों कर रहे हो ? मैं इमरजेंसी में आपके नजदीक रहा हूँ, आपके लोगों को साथ ले करके आन्दोलन चलाया है इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ । लेकिन मान्यवर, कितना चरित्र बदल गया, कितना चरित्र बदल गया? हाउस में असत्य बोलना ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, क्या दोबारा बहस शुरू हो गयी? एक बार स्पष्टीकरण तो मॉग सकते हैं माननीय नेता विरोधी दल और यह परम्परा भी रही है। यह दोबारा भाषण की परम्परा, नई-नई परम्परा केवल हम ही नई डाल रहे हैं। एक बात आपने यह कहा कि संसदीय कौशल हमने कम किया। मान्यवर, जो व्यक्ति जिस पार्टी की तरफ से यह कहा जाय देश टूट जायेगा, यह बिल्डिंग गिर जायेगी। हम जीते तो कलयुग आ गया तो यह सब संसदीय कौशल है मान्यवर और हमारा संसदीय कौशल कम हुआ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं मान रहा हूँ कि यह संसदीय कौशल नहीं होता तो आप संसदीय कार्य मंत्री होते कैसे। बैठ जाइये। आपमें संसदीय कौशल होता नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री होते कैसे। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि जो माननीय नेता सदन ने हमको यह कहा कि राम गोविन्द चौधरी जी पढ़ कर के नहीं आये हैं। ऐसे ही उन्होंने कह दिया तो उसकी मैंने सफाई दी। कि जो बात मैंने कही आपकी पुस्तिकाओं में जो छपा है उसकी बात है। तो श्रीमन्, यह बजट, मैंने उस दिन भी कहा था कि किसान को छला गया है, गरीब को छला गया है, बेरोजगारों को छला गया है। देखिये संसदीय कार्य मंत्री जी, एक भर्ती हम लोगों के जमाने से हो रही थी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एल0टी0 पुरूष और महिला 1,768 पदों की। किसी भी प्रदेश में बी0ए0 विषय नहीं है। इन्होंने बी0ए0 भी उसमें घुसेड़ दिया। कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम नौकरियों की बौछार ले आ रहे हैं। शिक्षामित्रों का तो हम कर रहे थे। हमको गर्व है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो राम गोविन्द चौधरी ने किया। अब भी अगर मौका आयेगा तो उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक राम गोविन्द चौधरी ही बनायेंगें। आप नौकरी देंगें? एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर को पढ़ाने के लिये, अध्यक्ष जी जरा आप सुन लीजिये। बी0ए0 पास होना चाहिए, बी0टी0सी0 पास होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए इन्होंने लिखित परीक्षा इसलिये किया कि इतना कठिन पर्चा बनायेंगें कि 90 प्रतिशत लड़के फेल हो जायेंगें, केवल 10 प्रतिशत पास होंगें और इन 10 प्रतिशत को यह नौकरी देंगें।(सत्ता पक्ष से टोका टाकी) अभी जो टी0ई0टी0 का प्रश्न आपने किया था माननीय अध्यक्ष जी, जो टी0ई0टी0 का प्रश्न आया था जिसमें शिक्षामित्र फेल हो गये थे वह इसीलिये आया था। अगर वह टी0ई0टी0 का प्रश्न आपके वर्तमान के आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 और आई0पी0एस0 को दे दीजिये और उनसे हल करवा दीजिये तो जो कहिये सो। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के लिये इतनी योग्यता। हमने थर्ड क्लास, सेकेन्ड क्लास, फर्स्ट क्लास पास कर ली।

(श्री राजेश अग्रवाल, माननीय वित्त मंत्री जी के कुछ कहने के लिये उठने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वित्त मंत्री जी हमारी बात मानते हैं, मैं उनकी बात मान लिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में यह जो बजट आया है इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है, रोजगार पाने वाले व्यक्तियों का भला होने वाला नहीं है, इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है। इससे छात्रों का भला होने वाला नहीं है। अभी मैंने उस दिन जो कहा उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कि सोरांव जिले में गोड़ धुरिया, खरवार जाति जो जनजाति के हैं, यह गरीब की सरकार है,

इनको प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है। मुख्य मंत्री जी इतना तक नहीं कह पाये कि हम उनको प्रमाण-पत्र जारी करवा देंगें इसलिये श्रीमन्, यह सरकार पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, समाज विरोधी है, जो समाजवादी धारा के हैं, सेक्यूलर दिमाग के हैं उनके सारे लोगों के मन के खिलाफ यह बजट है। इस बजट में कुछ नहीं है। बजट यह केवल एक प्रक्रिया है जैसा वित्त मंत्री जी ने सही कहा कि यह एक प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

राजेश जी की बात मानकर आप समर्थन नहीं कर रहे है क्या?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी बात मान ली अध्यक्ष जी। इन्हीं शब्दों के साथ चूँकि यह बजट..

श्री राजेश अग्रवाल-

नेता प्रतिपक्ष जी अपने दुख से दुखी नहीं है।

श्री राजेश अग्रवाल-

मैं बस एक मिनट लूँगा।अध्यक्ष जी, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष अपने दुख से दुखी नहीं हैं दूसरे के सुख से बहुत दुखी हैं। मैं चलते-चलते एक लाइन कहना चाहता हूँ-

कभी जलाओ मुझे तुम, कभी बुझाओ मुझे तुम,
तुम्हें कसम है और आजमाओ मुझे तुम ।।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था-

ये गलत कहा किसी ने कि मेरा पता नहीं है
कोई ढूँढ़ने कभी वहां तक मुझे गया ही नहीं है
कोई मंजिल के करीब आकर भटक जाता है
कोई मंजिल पर पहुँचता है भटक जाने से पहले।।

तो यह तो मंजिल पर आने के पहले ही भटक गये,-

मजा चख लेने दो, उसे गैरों की मुहब्बत का भी
इतनी चाहत के बाद भी जो मेरा न हुआ
वह औरों का क्या होगा।।

जो जनता का हुआ ही नहीं, गरीब का हुआ ही नहीं, बेरोजगार का हुआ ही नहीं,दलितों का हुआ ही नहीं, महिलाओं का हुआ ही नहीं, तो किसका होगा,यह सरकार जानें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जितने माननीय सदस्यों के पास नियम-51 की सूचना है वह अगले दो दिनों में दे दें सब स्वीकार कर लेंगे दो दिन के भीतर।

आज दिनांक 22-03-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 67 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री अजय सिंह जनपद बस्ती के हर्रेया विधान सभा क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व बजाज ग्रुप द्वारा खरीदी गई 125 एकड़ जमीन पर शुगर मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री रमाशंकर पटेल जनपद मिर्जापुर में मैगमा फाइनेंस कम्पनी द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को फर्जी तरीके से ऋण देने एवं मनमाना ब्याज वसूले जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह.जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0 संख्या 17/18, दिनांक 08-01-2018 के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री संगम लाल गुप्ता जनपद प्रतापगढ़ के जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण शासनादेशों का उल्लंघन करते हुये बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा, पांचवी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में श्री सचिन की भूमि पर किये गये कब्जे के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, छठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री राकेश राठौर जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र खैराबाद में जंगली व आवारा कुत्तों की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में, तथा आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के पारा क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की लापरवाही से दिनांक 20-03-2018 को ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने के सम्बन्ध में हैं, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री संजय गर्ग सिंचाई विभाग सहारनपुर द्वारा महानगर के बीच बह रही ढमोला नदी के गलत सीमांकन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री नफीस अहमद जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2003 से कार्यरत अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, श्रीमती अर्चना सिंह का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा.जनपद पीलीभीत के महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस उ0प्र0 में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना डा0 मुकेश वर्मा जनपद फिरोजाबाद व आगरा के मध्य यमुना नदी पर फरौल नगरयिा में एक बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौहदवीं सूचना श्री हरीराम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में तैनात जिला समन्वयक को कार्यमुक्त करते हुये बी0एस0ए0 के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, सोलहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी जनपद लखनऊ के दुबग्गा में सीतापुर बाईपास से बेगरिया होते हुये नहर के ऊपर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, सत्रहवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा जनपद लखनऊ के तेज कृष्ण खेड़ा में निर्बल की भूमि पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, अठारहवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले की सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के निजामाबाद मेहनगर विद्युत वितरण खण्ड तृतीय का मुख्यालय भवन प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में, बीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में उचित दर पर बालू उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई जनपद कानपुर नगर में हेलीपैड बनाये जाने के कारण पुराने नीम के वृक्ष काटे

जाने के सम्बन्ध में, बाइसवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार जनपद पीलीभीत में गन्ना विभाग द्वारा किये गये टेण्डर एवं सड़कों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, तेईसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौबीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'.जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पच्चीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र परिसर की खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, तथा छबीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

क्रम	नाम
1	श्री अबरार अहमद
2	चौधरी नाहिद हसन
3	श्री विपिन कुमार डेविड
4	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
5	श्रीमती साधना सिंह
6	डा0 जी0एस0धर्मेश
7	श्रीमती मनीषा अनुरागी
8	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
9	डा0 अरूण कुमार
10	श्री सुशील कुमार शाक्य
11	डा0 श्याम बिहारी लाल,
12	डा0 मन्जू शिवाच
13	श्रीमती सुनीता
14	श्री विक्रम सिंह सैनी
15	डा0 विमलेश पासवान
16	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
17	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव
18	श्री पूरन प्रकाश
19	श्री शीतल पाण्डेय
20	श्रीमती सरिता भदौरिया
21	श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस

क्रम	नाम
22	श्री दलवीर सिंह
23	श्री मसूद अख्तर
24	श्री नरेश सैनी
25	श्री विनय शंकर तिवारी
26	श्री जटाशंकर त्रिपाठी
27	श्री सत्यपाल सिंह राठौर
28	डा0 जमुना प्रसाद सरोज
29	श्री राहुल प्रकाश
30	श्री हाकिम लाल बिन्द
31	श्री संजय प्रताप जायसवाल
32	श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य
33	श्री कपिल देव अग्रवाल
34	श्री प्रमोद उटवाल
35	श्री रितेश पाण्डेय
36	श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
37	श्री मनीष असीजा
38	श्री राम नरेश रावत
39	श्री अनिल कुमार मौर्य,
40	श्री राकेश प्रताप सिंह तथा
41	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा।

जनपद फैजाबाद स्थित जिला चिकित्सालय में आवश्यक स्टाफ की तैनाती किये जाने एवं ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय फैजाबाद में स्थापित सी0 टी0 स्कैन मशीन दिनांक 09-09-2017 से अक्रियाशील है।

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स-सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा उक्त मशीन की मरम्मत की गयी परन्तु मशीन क्रियाशील नहीं हो पायी। जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में सिंगल स्लाइस सी0टी0 स्कैन मशीन वर्ष 2006 में स्थापित करायी गयी थी। उक्त मशीन का प्रभावी जीवनकाल पूर्ण हो जाने के कारण उक्त मशीन के स्थान पर नयी सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है। जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में चिकित्सक संवर्ग के कुल 46 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 28 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं एवं कुल 18 पद रिक्त हैं। पैरामेडिकल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 180 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 124 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कुल 56 पर रिक्त है।

शासनादेश संख्या-596(क)/पांच-6-2017-43जी0/2017 दिनांक 06-05-2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में चिकित्सकीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न की जाए तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली में एन0एच0-28 के किनारे कुशहरी ग्राम पंचायत में 100 बेड का अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर बनाया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बड़े पाइप डलवाने के सम्बन्ध में डा0 जी0एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बड़े पाइप डलवाने के संबंध में.....

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[इन पाइपों के माध्यम से ही नहर में पानी बहता रहता था। नहर ऊपर से पटी होने के कारण गन्दगी भी नहीं थी और जनता का छोटे-छोटी पुलियों के माध्यम से आवागमन भी होता था। जनता को कोई परेशानी नहीं थी।

लेकिन विगत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में किसी एन0जी0ओ0 के द्वारा आर्थिक लाभ की दृष्टि से जे0सी0बी0 मशीन लगाकर नहर में पड़े इन पाइपों को उखाड़कर किनारे डाल दिया गया, जिससे आवागमन की व्यवस्था में अचानक व्यवधान पैदा हो गया और नहर में जल भराव पैदा हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। जनता के आक्रोश को दृष्टिगत रखते हुये इस समस्या के समाधान हेतु नहर में पुनः पाइप डालकर पूर्ववत बनाया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुये राजपुर चुंगी क्षेत्र स्थित नहर में पुनः पाइप डालकर पूर्ववत बनाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण कराया गया। राजपुर चुंगी क्षेत्र माइनर पार्क में ताजगंज वार्ड उखरार मोड़ से गुरू गोविन्द नगर पुलिया तक नगर को वर्ष 2009 में ह्यूम पाइप से कवर्ड करने का कार्य तत्कालीन माहपौर के निर्देशों के क्रम में कुल लागत 32.65 लाख की धनराशि से आगरा के अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नगर से अनापत्ति प्राप्त करते हुये कराया गया है। नगर निगम द्वारा पाइपों में बहने वाले जल की गन्दगी को साफ करने का कार्य कराया जाता रहा है। ह्यूम पाइप को हटाये जाने हेतु श्री केशो मेहरा, पूर्व प्रदेश महामंत्री (संगठन) भाजपा, उ0प्र0 पूर्व विधायक आगरा छावनी के पत्र के क्रम में तृतीय मंडल सिंचाई कार्य, आगरा के द्वारा अनापत्ति निरस्त करते हुये ह्यूम पाइप हटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त तत्कालीन महापौर द्वारा दिनांक 17-05-2017 व 22-07-2017 तथा मा0 उप मुख्य मंत्री के आगरा भ्रमण के दौरान श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव, जलाधिकार फाउण्डेशन, आगरा के पत्र दिनांक 20-08-2017 के क्रम में मा0 उप मुख्य मंत्री जी के द्वारा पार्क माइनर को चालू कराये जाने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनांक 26-08-2017 के द्वारा पार्क माइनर नहर को खुलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा को प्रकरण के निस्तारण हेतु नामित किया गया। प्रशासन आगरा के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 09-02-2018 के द्वारा उक्त पाइप लाइन को नगर निगम के खर्चे पर ही निकाले जाने हेतु लिखा गया है एवं तद्नुसार कार्यवाही करते हुये पाइपों को नहर माइनर से हटा दिया गया।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर में नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वक्तव्य स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद क्षेत्र के 20 ग्रामों को जोड़े जाने के उपरान्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद क्षेत्र के 20 ग्रामों को जोड़े.....

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[सन् 2009 में जब विधान सभाओं का परिसीमन हुआ था उस समय लगभग 20 ग्राम मलिहाबाद क्षेत्र के काट करके नवनिर्मित पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में जोड़ दिये गये थे। जो नगर निगम की सीमा में सम्मिलित हो गये। उन ग्रामों में किसानों ने अपने खेतों को सोसाइटीज को बेच दिया जिन्होंने प्लाटिंग करके बिना डेवलपमेन्ट कराये जनता को भवन निर्माण करने के लिये बेच दिया। लोगों ने इन प्लाटों पर मकान बना लिये और इनका नगर निगम में एसेसमेन्ट हो गया और नगर निगम इनसे हाउस टैक्स और जल कर वसूल कर रही है। इनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो गया, लेकिन इनको नगर निगम की मूल-भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का जो विकास से दूर हैं, विकास होना अति आवश्यक है किन्तु समस्या इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र से हट जाने के बाद ग्राम पंचायत इनका विकास करने से मना करती है और नगर निगम यह कहकर कि यह अनियोजित कालोनी है इसलिये इनका विकास नहीं करती है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों की हालत त्रिशंकु जैसी हो गयी है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अनियोजित कालोनियों को विकसित करने के लिये अलग से कोई योजना बना करके मूल भूत सुविधायें उपलब्ध कराये।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।''

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनियोजित रूप से बसाई गई अवैध कालोनियों को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1973 के अनुसार नियमितीकरण कर, अध्यासियों से विकास शुल्क लेकर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यद्यपि नगर निगम द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अपने सीमित संसाधनों से जनहित में समय-समय पर कार्य कराये जाते है। मलिहाबाद विधान सभा के प्रश्नगत पूर्व क्षेत्र जो पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित हुए है उनके अन्तर्गत आने वाले नगर निगम के वार्डों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 1144.13 लाख के कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं तथा रु0 273.00 लाख के कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गयी है।]

जनपद वाराणसी के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में श्री नील रतन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद वाराणसी के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड में व्याप्त अनियमितता के संबंध में.....

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रखण्ड प्रथम, वाराणसी में तैनात कर्मचारी अजय कुमार श्रीवास्तव नियम विरुद्ध चपरासी से लिपिक के पद पर वर्ष 2013 में पदोन्नति कर दी गयी है। इनके पदोन्नति में विभाग के कई अधिकारियों के मिलीभगत से आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है। उक्त विभाग के अधिकारी द्वारा लीपा पोती कर अजय कुमार श्रीवास्तव को बचाने में लगे है। अजय कुमार श्रीवास्तव जब लिपिक पद हेतु टंकण परीक्षा को उत्तीर्ण किया तो वह चिकित्सीय अवकाश पर था। जिसकी जांच प्रमुख चिकित्साधीक्षक, सर सुन्दर लाल चिकित्सालय बी0एच0यू0, वाराणसी को सौपी गयी। परन्तु उनके द्वारा आज तक जांच नहीं करायी गयी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित न होना फर्जी कार्यवाही को परिलक्षित करता है। यह कि जांच के दौरान इनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को धन प्रलोभन देकर जांच को निष्प्रभावित किया जा रहा है। इनको संबंधित विभाग के खण्डीय कार्यालय में उसी पटल कार्य आवंटित कर दिया गया है, जिससे अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड प्रथम वाराणसी की जानबूझ कर मिली भगत कर शासकीय धन के लूट खसोट एवं बन्दरबांट में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संलिप्तता को स्पष्ट रूप में उजागर करता है। संबंधित विभाग के इस कृत्य से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अजय कुमार श्रीवास्तव का अन्यत्र स्थानान्तरण कर इनके द्वारा की जा रही बड़े पैमाने पर लूट खसोट एवं उनके चिकित्सीय प्रमाणक तथा टंकण परीक्षा की निष्पक्ष जांच कराने हेतु एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कराकर इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही कराने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-वक्तव्य-

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, धावक की पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2952/दिनांक 13-04-2010 द्वारा इस प्रतिबन्ध के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी कि 06 माह के अन्दर कार्मिक को टंकण की अपेक्षित गति 25 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा मूल पद पर प्रत्यावर्तित मान लिया जायेगा। श्री श्रीवास्तव की टंकण परीक्षा अनुदेशक के समक्ष ली गई, जिसमें अपेक्षित गति प्राप्त न होने के कारण उनको मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा लिपिक पद पर सेवा बहाली कराने के उद्देश्य से एक प्रत्यावेदन प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को दिया गया, जिसके क्रम में श्री श्रीवास्तव की टंकण परीक्षा दिनांक 24-09-2013 को आयोजित की गई, जिसमें उन्हें उत्तीर्ण घोषित करने के उपरान्त लिपिक के पद पर बहाल कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का दिनांक 26-11-2012 से 27-09-2013 (कुल 306 दिवस) का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त खण्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त चिकित्सा एवं टंकण परीक्षा के जांच के सम्बन्ध में मा0 विधायक, सेवापुरी द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी, वाराणसी को पत्र लिखा गया जिसके सन्दर्भ में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा श्री श्रीवास्तव की टंकण परीक्षा लेने हेतु निर्देशित किया गया तथा चिकित्सा की जांच हेतु श्री श्रीवास्तव को सरसुन्दर लाल चिकित्सालय बी0एच0यू0, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु श्री अजय कुमार श्रीवास्तव चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु उपस्थित नहीं हुये।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, वाराणसी के समक्ष यह शिकायत संज्ञान में आने पर कि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से चिकित्सीय अवकाश पर होने के बावजूद श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 24-09-2013 को टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण कराई गयी है, जिलाधिकारी, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड-प्रथम, वाराणसी को सम्बोधित पत्र संख्या-513/लोक शिकायत-2017 दिनांक 04-09-2017 द्वारा इस आधार पर श्री श्रीवास्तव को दिनांक 08-09-2017 को राइफल क्लब, कलेक्ट्रेट, वाराणसी में टंकण परीक्षा के लिये उपस्थित होने के निर्देश दिये गये कि श्री श्रीवास्तव चिकित्सीय अवकाश की अवधि में बिना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये/बिना कार्यभार ग्रहण किये टंकण परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से बिना टंकण परीक्षा दिये ही उन्हें उत्तीर्ण किया गया। इस सम्बन्ध में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी के आदेश दिनांक 04-09-2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना के साथ माननीय उच्च

न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42216/17 योजित की गयी है, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।]

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मैं सिंचाई मंत्री को बताना चाहूंगा कि अजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि कर्मचारी के रूप में वहां पर थे और 306 दिवस के लिए यह चिकित्सीय अवकाश पर गये हुए थे और उसी दौरान इनको टंकण परीक्षा पास करा करके इनका प्रमोशन कर दिया गया और इसकी तमाम किसानों के द्वारा शिकायत की गयी तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखने का काम किया तो उन्होंने टंकण परीक्षा की जांच के लिए उनको कलेक्ट्रेट में बुलवाने का काम किया, उसके खिलाफ वह मा0 उच्च न्यायालय चले गये और मा0 उच्च न्यायालय ने उस पर उनसे यह कहा कि जिलाधिकारी जांच करवा सकते हैं, ऐसा मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और इसको दर्शाया जा रहा है कि यह मामला विचाराधीन है। इसको संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करायी जाए, क्योंकि यह पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किया गया है, तमाम भ्रष्टाचार वहां पर स्थापित हैं और इस एक मामले के उजागर होने से कई और मामले उजागर होंगे। हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच कराकर मामले को ओपेन कराया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है इस पर जिलाधिकारी ने न्यायालय के आदेश के अनुसार परीक्षा कराने का आदेश दिया। परीक्षा हुई, परीक्षा में भी पास पाए गए, इसके बाद फिर कोई शिकायत की गयी है। यदि कोई ऐसी शिकायत है, हम जांच करा लेंगे।

भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश में समुचित तरह से लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वक्तव्य भी स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर नेशनल हाई-वे से सेंट मोमिना स्कूल के पास लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत मेरठ-बुलन्दशहर नेशनल हाई-वे से सेंट मोमिना स्कूल के पास.....

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[से लिंक मार्ग जो कि ग्राम गिनौरा शेख होकर ग्राम शाहनगर (बुलन्दशहर-सैदपुर मार्ग) तक जाता है, मेरठ-बदायूं मार्ग से सैदपुर मार्ग वाया गिनौरा शेख मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 7.925 किमी0 है। मार्ग का किमी0 1, 2 (540) लेपित सतह का है तथा इस भाग में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, जो संतोषजनक है। मार्ग का किमी0-2 (460), 3(300) गिनौरा शेख आबादी भाग है, जिसमें इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगी है, जो कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग के किमी0-3 (700), 4, 5, 6, 7(200) में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, जो संतोषजनक है।

मार्ग के किमी0-7 (800) व 8 (925) में जिला योजना के अन्तर्गत पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 35.39 लाख का स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु0 17.45 लाख का आवंटन निर्गत किया जा चुका है। उक्त आवंटन के सापेक्ष 7(075), 8(925) लम्बाई में कार्य मार्च, 2017 में पूर्ण करा दिया गया था, मार्ग के किमी0-7(725) में कार्य प्रगति में है। कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

महिला कल्याण मंत्री (प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी)-

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित..

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पर्यटन मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[किये जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2017-2018 में पर्यटन विभाग के आय-व्ययक में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हैं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम की सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के नांगल क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर ...

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[क्षेत्र में जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है तो सहायता के लिये जिला मुख्यालय से आने वाले सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सहायता के लिये मुख्यालय से आने वाले सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस कारण जानमाल का नुकसान ज्यादा हो जाता है। भविष्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नागल अथवा रामपुर मनिहारन में फायर स्टेशन का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के नागल क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर समुचित सहायता/वाहन अग्निशमन केन्द्र देवबंद से उपलब्ध कराये जाते हैं। रामपुर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। रामपुर मनिहारन में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर समुचित सहायता/वाहन जनपद मुख्यालय सहारनपुर से उपलब्ध कराये जाते हैं।]

प्रदेश के सरकारी विभाग को कैन्टीन में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों एवं प्लेटों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार प्रजापति द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बंध में अवगत कराना है कि 50 माइक्रोन से पतली...

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, पढ़ा हुआ माना गया)

[पॉलीथीन के सामान एम0ओ0ई0एफ0सी0सी0 के नोटिफिकेशन द्वारा प्रतिबन्धित है। अतः बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण व मिट्टी के बर्तन बनाने व बेचने वाले बहुसंख्यक शिल्पकार समाज के मिलने वाले रोजगार के दृष्टिगत विधान सभा की कैन्टीन सहित सम्पूर्ण विधान भवन से लेकर प्रदेश के सभी सरकारी आफिसों, अस्पतालों, रोडवेज बस स्टैण्डों समेत तभी सार्वजनिक स्थलों के इर्द-गिर्द स्थित होटल-ढाबों से प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाकर, उनके स्थान पर मिट्टी से निर्मित कुल्हड़ों और प्लेटों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना उचित है। नगर विकास विभाग इससे सहमत है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियान में विकास खण्ड पटेहरा एवं रजगढ़ में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

इसका वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है।

संसदीय एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह अभी आ गया है अनुमोदन के लिए अगर आप अनुमति दें तो सुना दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है पढ़ दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उक्त के सम्बंध में अवगत कराया जाना है कि नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से सम्बंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जनपद मिर्जापुर के विकासखण्ड पटेहरा एवं राजगढ़ के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था का बिन्दु ग्रामीण क्षेत्र से सम्बंधित है इस सम्बंध में प्रकरण में कार्यवाही कराए जाने का..

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह ग्राम्य विकास से सम्बंधित है। केवल इतनी बात है।

श्री रमाशंकर पटेल-

मान्यवर, यह ग्राम्य विकास से सम्बंधित है। लेकिन इसका उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें ग्राम्य विकास विभाग को कहा गया है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रमाशंकर पटेल-

इसमें 2 तारीख को मीटिंग रखी गई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम 26 मार्च 2018 को 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजे सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2018 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 22 मार्च, 2018।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 46-47पर

संलग्नक-1

जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत प्रशिक्षण प्रदाता एवं संचालित कोर्स की सूची

क्र0 सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	प्रशिक्षण प्रदाता का पता	तहसील का नाम	संचालित कोर्स
1	2	3	4	5
1	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	जलाहाबाद	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट
2	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	दिलाजक कैंट मेन पुलिस स्टेशन गेट शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	लेखा सहायक टैली, डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट
3	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	सदर बाजार नियर सरताज पब्लिक स्कूल मेन मार्केट निगोही तहसील तिलहर शाहजहांपुर	तिलहर	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, लोन अप्रूवल ऑफिसर
4	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	मोहल्ला चिनार नियम महर्षि भारद्वाज स्कूल शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	लेखा सहायक टैली, हाथ की कढ़ाई
5	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	मिथलेश कुमारी इन्टर कालेज परौरा रोड कलां तहसील कलां जिला शाहजहांपुर-242127	कलान	लेखा सहायक टैली, हाथ की कढ़ाई
6	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	आता चौराहा एच0पी0 गैस एजेन्सी के सामने बृजविहार कालोनी शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	लेखा सहायक टेली
7	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	नियम पी0एस0 निगोही शाहजहांपुर निगोही	तिलहर	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट

1	2	3	4	5
8	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	जनता बाल विद्या मन्दिर के सामने बिलसन्दा रोड बांदा शाहजहांपुर	पुवांया	वेब डिजाइनिंग तथा प्रकाशन सहायक
9	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	ग्राम व पोस्ट खमरिया तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर	तिलहर	लेखा सहायक टेली
10	फ्यूचर शेप सोशल एजूकेशनल सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	तिलहर	वेब डिजाइनिंग तथा प्रकाशन सहायक, परम्परागत कढ़ाई, वेब डिजाइनिंग तथा प्रकाशन सहायक
11	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोजा शाहजहांपुर	गौस नगर नियम पावर हाउस	शाहजहांपुर	आटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, फैब्रीकेशन, गारमेंट मेकिंग
12	जीवन ज्योति शिक्षा एवम् जन कल्याण समिति	गौस नगर नियम पावर हाउस	पुवांया	असिस्टेंट फैशन सेल्स एण्ड शोरूम रिप्रजेन्टेटिव
13	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम	गौस नगर निगम पावर हाउस	तिलहर	एकाउन्टिंग
14	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम	गौसा नगर नियम पावर हाउस पुवांया	पुवांया	लेखा सहायक टैली, हाथ की कढ़ाई
15	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम	गौसा नगर नियम पावर हाउस पुवांया	पुवांया	लेखा सहायक टैली, हाथ की कढ़ाई
16	मदीहा एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	पुवांया	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट
17	मदीहा एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	पुवांया	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट फैशन सेल्स एण्ड शोरूम रिप्रजेन्टेटिव
18	मदीहा एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर निगम पावर हाउस	शाहजहांपुर	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, हैण्ड इम्ब्राइडरी

1	2	3	4	5
19	मदीहा एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	शाहजहांपुर	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट
20	मदीहा एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	शाहजहांपुर	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट
21	मदीहा एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	पुवांया	डी0टी0पी0 और प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, हैण्ड इम्ब्राइडरी
22	मॉस इन्फोटेक सोसाइटी	गौस नगर निगम पावर हाउस	पुवांया	एकाउन्टिंग सेल्स पर्सन
23	मॉस इन्फोटेक सोसाइटी	गौस नगर नियम पावर हाउस	शाहजहांपुर	एकाउन्टिंग सेल्स पर्सन

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

संलग्नक-02

वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में योजनावार प्राप्त धनराशि का विवरण

धनराशि रु0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	कुल प्राप्त धनराशि 2017-18
		प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	
		A	B	C	D	E	(A+B+C+D+E)=F
1	एस0डी0आई0	100,000,000	642,158,475	-	-	-	742,158,475
2	एस0सी0ए0 टू एस0सी0एस0पी0	236,000,000	-	-	450,000,000	-	686,000,000
3	बी0ए0डी0पी0		25,000,000	24,834,000	-	4,585,000	54,419,000
4	एम0एस0डी0पी0		373,930,000	-	-	-	373,930,000
5	पी0एम0के0वी0वाई0					100,000,000	100,000,000
6	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना		-	2,212,000,000	208,086,117	-	2,420,086,117
7	बी0ओ0सी0डब्लू0		50,000,000		-	-	50,000,000
8	स्टेट स्किल डेवलपमेंट		150,000,000	200,000,000	699,682,000	750,000,000	1,799,682,000
	योग	336,000,000	1,241,088,475	2,436,834,000	1,357,768,117	854,585,000	6,226,275,592

पी0एस0यू0पी0-एल0 117 विधान सभा (216)-3-10-2018-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।